राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 10 | विधान सभा के दशम् सत्र का चतुर्थ दिवस | संख्या 4

बृहस्पतिवार,
दिनांक 18 मार्च, 1971,

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, कृषि, राजनैतिक विभाग, विधि, सहकारी, आयुर्वेद, गृह विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्रीमती मदनकौर।

प्रश्न संख्या 25.

पचपदरा-पाटोदी वाया कानोट सड़क

25. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बाड़मेर जिले में पचपदरा से पाटोदी होती हुई कानोट सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग के चार्ज में है?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क की मेन्टीनेन्स बिलकुल नहीं हो रही है जिसके फलस्वरूप सारी सड़क पर भारी मात्रा में रेत जमा हो गई है?

(3) क्या यह भी सही है कि लूनी नदी में पानी आने पर जोधपुर से बाड़मेर जाने के लिये यही एक मात्र सड़क है?

(4) क्या राज्य सरकार अधिक वित्तीय प्रावधान रख कर इस सड़क को मिट्टी से बचाने की शीघ्र व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) **:**

(1) जी हां।

(2) उपलब्ध धनराशि अनुसार थोड़ी मरम्मत हो पाती है। आंधी से इस ग्रेवल रोड पर कहीं कहीं रेत जमा हो गई है।

(3) जी, यह सही नहीं है। बाड़मेर पहुंचा जा सकता है।

(4) अर्थाभाव के कारण अधिक वित्तीय प्रावधान संभव नहीं हुआ है।

श्रीमती मदनकौर : अध्यक्ष महोदय, इस सड़क पर लगभग तीन चार मील पर बहुत अधिक मिट्टी पड़ी हुई है और उस पर मोटरों का निकलना सम्भव नहीं है और मंत्री महोदय यह कह रहे है कि थोड़ी मिट्टी है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जो मेरे पास में जानकारी थी वह मैंने दे दी है। वैसे आपको भी मालूम है कि तमाम इस इलाके में रेत और मिट्टी के ढेर हैं और वे पूरे तौर पर सडक को रोक लेते हैं और जो हमेशा होता है । जितना हमारे पास में धनराशि है उसके अनुसार करते हैं। जैसा आपने अभी कहा है कि तीन मील की सडक पर रेत है । उसकी जांच करा ली जायेगी और उसको हटवाने की कोशिश की जायगी

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : कब तक हटा देंगे ।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कुदरत के खेल को कोई नहीं मिटा सकता उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता ।

श्रीमती मदनकौर : तीन चार मील की दूरी पर सड़क पर रेत का टीला आ गया है और वहां पर कोई बस, मोटर तक नहीं निकल सकती है। क्या मंत्री महोदय इसकी गम्भीरता को देखेंगे और वहां पर शीघ्र ही गेंग लगाकर मिट्टी को साफ करायेंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : यह मैं निवेदन कर चुका हूं और इसका इन्तजाम हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य । प्रश्न संख्या 26 !

नगरपालिकाओं को भूमि विक्रय के अधिकार

26. **श्री हंसराज आर्य (भादरा)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) गंगानगर जिले की जिन जिन नगरपालिकाओं से भूमि विक्रय के अधिकार सरकार ने ले लिये थे उन्हें कब तक वापिस दे दिये जायेंगे ?

(2) जिन जिन नगरपालिकाओं में भाखरा की मंडियों का प्रावधान है क्या उन मण्डियों की भूमि विक्रय के अधिकार भी नगरपालिकाओं को दिये जायेंगे ?

(3) यदि हां, तो कब तक ?

(4) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या गंगानगर जिले में कहीं नगर विकास न्यास भी बनाया जायगा ?

(6) यदि हां, तो कहां कहां पर बनाया जावेगा और कब तक ?

उपमंत्री स्वायत्त शासन (श्री खेतसिंह):

(1) केवल घोषित केनाल प्रोजेक्ट सीमा क्षेत्रों में भूमि विक्रय के अधिकार वापिस लिये गये थे । तदुपरान्त वर्ष 1967 में ऐसे अधिकार नगरपालिकाओं को सीमित क्षेत्रों में वापिस दे दिये गये थे ।

(2) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(3) खण्ड दो के जवाब में इसका जवाब दे दिया गया है ।

(4) खण्ड दो के जवाब में इसका जवाब दे दिया गया है ।

(5) यह विषय विचाराधीन है ।

(6) गंगानगर में न्यास का गठन विचाराधीन है ।

Page No 3

श्री हंसराज आर्य : सीमित अधिकार दे दिये गये हैं इसका क्या मतलब है?

श्री खेतसिंह : जहां जहां से कैनाल गई है जैसे भाखरा, राजस्थान कैनाल उन क्षेत्रों की जमीन गवर्नमेन्ट ने विक्रय करना रोक दी थी। गवर्नमेन्ट यह चाहती थी कि कैनाल एरिया है और पता नहीं कितनी जमीन और कहीं पर कैनाल वगैरह के लिये चाही जायेगी और कैनाल बनाई जायेगी उस वक्त में सारे के सारे अधिकार ले लिये गये थे लेकिन उसके बाद में नगरपालिकाओं ने एतराज उठाया और सन् 67 के अन्दर कैनाल प्रोजेक्ट के अन्दर कुछ प्लाटस् को छोड़कर बाकी के क्षेत्र में उनको वापिस अधिकार दे दिये गये थे कि वे अपने इस दायरे के अन्दर जमीन का विक्रय करें।

श्री हंसराज आर्य : किस रूप से अधिकार दिये थे? गंग कैनाल, भाखरा और राजस्थान नहर के इलाके के भी दिये गये हैं?

श्री खेतसिंह : प्रश्न 2 के उत्तर में निवेदन किया जा चुका है कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री हंसराज आर्य : सीमित अधिकार का क्या मतलब है। अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं से भूमि विक्रय के अधिकार छीन लिये गये थे। सरकार मंडी आबाद करना चाहती थी और उस वक्त पता नहीं था कि कितनी भूमि चाहियेगी। अब इसकी क्या सीमा की है और रोक लगाई है— इसका क्या मतलब है?

श्री खेतसिंह : इस पर भी मैंने निवेदन कर दिया है, हम इस पर भी विचार कर रहे हैं और जल्दी ही निर्णय ले लेंगे।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, आज से कई साल पहले मंडियों के लिये भूमि एक्वायर की गई थी। मंडिया बन चुकी हैं, वाटर वर्क्स, सड़कें बन चुकी हैं उसके बाद भी अधिकार नहीं दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको पूछने दीजियेगा आवश्यक पाबन्दी लगाने का क्या सारांश है?

श्री खेतसिंह : आपने यह प्रश्न किया है। इसके अलावा भी यह पत्रावली मन्त्री महोदय के विचाराधीन है और जल्दी ही उस पर निर्णय ले लिया जायगा।

श्री हंसराज आर्य : कब तक?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ): आज तक नगरपालिका क्षेत्र में आबादी वाली भूमि का विक्रय नहीं हुआ है, क्या यह सही है?

श्री हंसराज आर्य : लोग जमीनों पर नाजायज कब्जा कर रहे हैं और गवर्नमेन्ट को अर्थ का नुकसान हो रहा है। यह कब तक चलता रहेगा?

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : दोनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाये।

श्री खेतसिंह : आप के प्रश्न के उत्तर में मैंने निवेदन कर दिया है कोई एग्जेक्ट डेट नहीं दे सकता हूं लेकिन यह प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो जायगा जैसा कि आप लोग महसूस करते हैं वैसा ही हम भी महसूस करते हैं कि लोग अनधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं और फिर उनको हटाने में दिक्कत आयेगी इसलिये जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री हंसराज आर्य : कोई निश्चित तारीख इसके लिये नहीं तय कर सकते हैं। एक साल, दो साल, चार साल कोई तो मुकर्रर कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री वैद।

श्री दौलतराम सारण : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, अध्यक्ष महोदय।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, उत्तर नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : क्या कोलोनाइजेशन कानून लागू होने के पश्चात् आज तक कोई मण्डी क्षेत्र में भूमि आबादी के लिये विक्रय नहीं की गई है?

मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री भीखाभाई): यह कोलोनाईजन से सम्बन्धित है, हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण: मेरा प्रश्न जरा कान से सुनिये। मैंने यह पूछा है कि उस क्षेत्र में नगरपालिकाओं के द्वारा कोलोनाइजेशन एक्ट लागू होने के पश्चात् आज तक कोई भूमि का विक्रय नहीं किया गया है? कोलोनाइजेशन एक्ट लागू होने के पश्चात् क्या भूमि का विक्रय करना मना है?

श्री भीखाभाई : यह उत्तर में आ गया है कि लिमिटेड अधिकार दिये गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : लिमिटेड अधिकार देने के बाद कहां कहां पर लिमिटेड अधिकार दिये गये हैं और किस सीमा तक दिये गये हैं?

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, दोनों विभागों के मंत्री पास पास में बैठे हैं। आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। वे मिल कर उत्तर दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री वैद प्रश्न संख्या 27।

कृषि फार्म, ग्राम खासोली

27. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या चूरू नगर के पास खासोली ग्राम में कोई सरकार द्वारा कृषि फार्म बनाया गया था? अगर हां, तो उस फार्म का क्षेत्रफल कितना है और उसमें सिंचाई के क्या साधन बनाये गये हैं?

(2) उस फार्म को बनाने में सरकार की कितनी धन राशि खर्च हुई और प्रति वर्ष उस फार्म का आय व्यय कितना हुआ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह फार्म इस समय बन्द पड़ा हुआ है और कृषि कार्य नहीं हो रहा है? अगर हां, तो क्यों?

(श्री लाभचन्द वैद)

(4) इस खासोली स्थित कृषि फार्म के भविष्य के बारे में सरकार ने क्या सोचा है ? सरकार खुद इस फार्म पर कृषि करेगी या इस फार्म को सरकार ठेके पर देगी या और कोई योजना इस फार्म के बारे में सरकार ने सोच रखी है ?

उप मंत्री, कृषि श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विकास विभाग से सम्बन्धित है इसलिये इसको स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय, गत दो सत्रों से मैं यह प्रश्न पूछता चला आ रहा हूं और हर बार इसको स्थगित कर दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : अभी इसको स्थगित कर दिया गया है।

श्री लाभचन्द वैद : उत्तर कब तक मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष : इसी सत्र में मिल जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मेहता।

भीलवाडा में राजनैतिक पीडितों की संख्या।

28. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) :** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भीलवाड़ा में राजनैतिक पीड़ितों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से किस किस को कितने रुपये मासिक मिल रहे हैं ? फहरिस्त सदन की मेज पर की कृपा करें।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) भीलवाड़ा जिले के जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को राज्य सरकार द्वारा नियमों के अन्तर्गत पेन्शन स्वीकृत की गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय इस फहरिश्त में 18 नाम ही बताये गये हैं तो क्या भीलवाड़ा जिले में 18 लोग ही हैं जो राजनैतिक पीड़ित हैं ? आप राजनैतिक पीड़ित मानते किस को हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने जो सूची सदन की मेज पर रख दी उन्हीं लोगों को आर्थिक पेन्शन दी जाती है, भीलवाड़ा जिले के अन्दर।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या आपकी दृष्टि में स्वर्गीय विजयसिंह पथिक की माता जानकी देवी राजनैतिक पीडितों में आती हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : हां, आती

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनको क्या मिलता है ? कृपा करके बतायेंगे, उनका नाम सूची में नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह भीलवाडा में नहीं रहती, इसलिये उनका नाम सूची में नहीं है। उनको 250 रु. मासिक दिया जाता है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या आप बतायेंगे कि श्री गणपतलाल जी राजनैतिक पीडितों में आते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, राजनैतिक पीडितों में आते ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इनको क्या मासिक पेन्शन दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इनको कैश दिया जाता है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : तो फिर क्या दिया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने तो कैश के लिये पूछा, उसका जवाब दे दिया गया है । आगे का मुझे मालूम नहीं है जितना पूछा है, उसकी जानकारी है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या राजनैतिक पीडित स्वर्गवासी हो जायेंगे फिर भी उनको यह सहायता दी जायेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : नियमानुसार आवश्यक नहीं है कि किसी के स्वर्गवास होने के बाद भी दिया जाय लेकिन विशेष परिस्थितियां हों तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : राजनैतिक पीडित हो जाने के बाद क्या इसी तरह··

श्री अध्यक्ष: हाईपोथेटिकल है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इसमें कुछ लोगों को 150 रुपया मिलता है तो कुछ लोगों को केवल 20 रु. मासिक ही मिलता है । इतना अन्तर क्यों है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : परिवार की मासिक आय, परिवार की सदस्य संख्या आदि को देखते हुए इस बारे में निर्णय लिया जाता है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं किसी की पेन्शन को कम नहीं करना चाहता, अध्यक्ष महोदय, उनको जितना दिया जाना चाहिये दें लेकिन एक ब्रह्मचारी हैं और साधू सीताराम जी हैं उनको 90 रु. और 75 रु. मिलते हैं और एक बाई है उनको केवल 20 रु. मिलते हैं और एक काशी प्रसाद जी व्यास हैं उनको 25 रु. मिलते हैं । यह अन्तर क्यों ? क्या इसको फिर से कन्सीडर करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : 150 रु. दिया जा रहा है, माननीय सदस्य भी जानते हैं वे बहुत बीमार रहते हैं । इन्हीं बातों को ख्याल में रखकर दिया जा रहा है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : करिये, आप 150 रु. करिये और मैं तो कहता हूँ 200 करिये लेकिन मैं चाहता हूं आज के इस युग में 20 रु. दे रहे हैं। कृपा करके उनको फिर से कन्सीडर कीजिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर आय के श्रोत दूसरे न हों तो फिर से दरख्वास्त दे सकते हैं–कन्सीडर करेंगे।

प्रश्न सं. 29

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री हरलाल सिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न सं. 30

श्री लादूराम सुलानिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लाभचन्द वैद ।

निलम्बित सहायक नाजिर सिविल जजी, रतनगढ ।

31. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) श्री भैराराम, सहायक नाजिर, सिविल जजी, रतनगढ़ को कब कब किस अभियोग में और किसके हुक्म से निलम्बित किया गया ? कृपया आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाय।

(2) क्या श्री भैराराम मजकूर को कोई चार्ज शीट दी गई ? यदि हां, तो चार्जशीटों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जाये।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान हाईकोर्ट से उक्त श्री भैराराम के खिलाफ की गई सारी कार्यवाहियां रद्द करदी गई ? यदि हां, तो विभाग को क्या कोई धनराशि खर्च मुकदमा के एवज में हर्जाने स्वरूप चुकानी पड़ी है ?

(4) श्री भैराराम के खिलाफ विभाग को अभियोग की पैरवी में नीचे के कोर्टो व हाई कोर्टों में कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी ? और कोर्ट ने क्या इस खर्च के लिए किसी को जिम्मेदार बताया है ?

उप मंत्री, विधि (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) श्री भैराराम को सिविल जजी, रतनगढ़ के आदेश दिनांक 11-4-59 से निलम्बित किया गया। अभियोग व निलम्बन आदेश की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी हां, चार्जशीटों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी नहीं।

(4) (1) 140.50 पैसे सरकारी वकील की फीस के दिये गये हैं। 39.35 पैसे श्री भैराराम को अपील के खर्च के दिये गये हैं।

(2) कोर्ट ने किसी को भी जिम्मेदार नहीं बताया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लाभचन्द वैद: क्या श्री भैराराम कोर्ट द्वारा वापिस वहाल कर दिया गया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज द्वारा बहाल कर दिया गया था।

श्री लाभचन्द वैद: क्या निलम्बित अवस्था का वेतन चुका दिया गया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा: यह जानकारी नहीं है।

श्री लाभ चन्द वैद: क्यों नहीं है ?

विधि मंत्री (श्री वरकतुल्ला खां): मैं बता दूं, जो ड्यू था वन फोर्थ सेलेरी

(श्री बरकतुल्ला खां)
उस पर बहस चल रही थी उसके बाद रिटायर हुये। मैं शुरू से बता दूं-पहले यह हुआ उनका जो केस था वह हाई कोर्ट में गया था। रिट पिटीशन की-पहले यह केस रिजेक्ट हो गया था। सिविल जज ने इसको मंजूर किया और मंजूर करने के बाद चार्ज ऑफिसर उनको खुद को बनाना चाहिये था उसके बाद डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी हुई और हाई कोर्ट ने यह तय किया कि उनकी पेन्शन और ग्रेच्यूटी कम कर दी जाये। उन पर चार्ज बना कर दिया जा रहा है और....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हंसराज आर्य।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों का एकीकरण।

32. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जहां पर एक ग्राम पंचायत में दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां थी उनका एकीकरण करके दो के स्थान पर एक एक ग्राम सेवा सहकारी समिति बना दी गई है ?

(2) यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि पंचायतों में आपसी झगड़ों के कारण उक्त निर्णय से हानि होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सहकारिता मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : (1) जी हां।

(2) प्राथमिक कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियों को सक्षम इकाई बनाने की दृष्टि से भारत सरकार की नीति के अनुसार प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों का एकीकरण किया गया।

(3) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : क्या सरकार की मंशा है कि सहकारिता से लाभ उठाने के लिये ग्रामों में दो दो इकाइयां बनाई जायेंगी ?

श्री अमृतलाल यादव : बिलकुल नहीं।

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय, गांवों में इतनी जबरदस्त पार्टियां हैं कि अगर वे एक साथ बैठेंगी तो झगड़ा हो जायेगा। फिर इससे सरकार का क्या उद्देश्य है ?

श्री अमृतलाल यादव: सरकार का उद्देश्य हर एक समिति को सक्षम बनाने का है। गांवों की पार्टियों को एक होना चाहिये।

श्री हंसराज आर्य : दो ग्राम सेवा सहकारी समितियां एक साथ नहीं बैठ सकेंगी-एक पार्टी काम करेगी, एक पार्टी काम नहीं करेगी। क्या सरकार दो दो सहकारी सेवा समितियां बनाने को तैयार है।

श्री अमृतलाल यादव : सरकार दो दो बनाने को बिलकुल तैयार नहीं है। जो सेवा समितियां हैं दो-दो, तीन-तीन उनको

(श्री अमृतलाल यादव)
एक किया गया है और यह इसलिये किया गया है कि वे आर्थिक स्थिति से सक्षम हों और सफलतापूर्वक काम कर सकें।

श्री हंसराज आर्य : वे कैसे कर सकेंगे, उनमें तो झगड़े होंगे।

श्री अमृतलाल यादव : आर्थिक दृष्टि से उनका सक्षम होना बहुत जरूरी है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : क्या यह सही है कि राजस्थान में 20–20 गांव की एक पंचायत है और भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दूसरे प्रान्तों में एक एक गांव की एक एक पंचायत है इसलिये यह व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिये। 20–20 गांव में 3–4 सोसाइटीज हैं वे चल नहीं सकती हैं तो राज्य सरकार इस पर पुनः विचार करेगी।

श्री हंसराज आर्य : किसी पंचायत में दो ग्राम सेवा सहकारी समिति रहें तो सरकार को क्या हानि है, मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री अमृतलाल यादव : यह भारत सरकार ने रिजर्व बैंक की एडवाइस पर तय किया है कि छोटी छोटी सहकारी समितियां होती हैं वे आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होती हैं। वे व्यवस्थापकों की तनख्वाह तक नहीं दे सकती हैं और ज्यादा काम भी नहीं कर सकती हैं इसलिये यह तय किया कि वे सक्षम इकाई होनी चाहिये लेकिन जहां कहीं भी कोई ग्राम पंचायत इतनी बड़ी है कि जहां हमारे क्राईटेरिया के आधार पर सहकारी समिति सक्षम है तो ऐसी दो भी हो सकती हैं। माननीय सदस्य को मालूम है हमारे यहां इसका प्रोविजन है कि अपील करें और अपील में यह देखा लिया जा सकता है कि जो ग्राम पंचायत का बड़ा एरिया है और आर्थिक रूप से ठीक तरह चल सकती है तो उस पर निर्णय लिया जा सकता है।

श्री हंसराज आर्य : सरकार हमारे देश में सीलिंग लागू कर रही है। सीलिंग में किसी जगह 25 बीघा है, किसी जगह 30 बीघा है तो यह आपका कर्तव्य है कि उस पर अमल करायें।

श्री अमृतलाल यादव : वह तो हम कर रहे हैं।

श्री हंसराज आर्य : क्या दो–दो सोसायटी बना दी जायेगी।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य मैंने निवेदन किया जहां ऐसी परिस्थिति समझते हैं वे इसके लिये अपील कर सकते हैं। उसके रास्ते हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सही है कि जिन सेवा सहकारी समितियों का एकीकरण किया गया है–सक्षम होने के नाते और सहकारी विभाग ने कहा है सक्षम इकाई है फिर भी मंत्री महोदय के आदेश से उसके टुकड़े करके अलग अलग समिति बनाई है।

श्री अमृतलाल यादव : यह प्रश्न अलग है। आप अपील कर सकते हैं उस पर गौर किया जा सकता है। ऐसी समिति होगी तो गौर करेंगे।

श्री नत्थीसिंह : अपील कर रहे हैं सहकारी विभाग ने मना किया है लेकिन

(श्री नत्थीसिंह)

मंत्री महोदय ने स्वयं के आदेश से उसको अलग अलग करवाया है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, माननीय सदस्य।

श्री नत्थी सिंह : नीति से सम्बन्धित है, अध्यक्ष महोदय।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि पहले लार्ज स्केल पर सहकारी समितियां थीं और उनको राज्य सरकार ने भारत सरकार की नीति के अनुसार छोटी सहकारी समिति गांव वार बनाई, क्या यह सही है ?

श्री अमृतलाल यादव : लार्ज स्केल पर सहकारी समिति थी · · ·

श्री दौलतराम सारण : और गांव वालों ने छोटी सहकारी समिति बनाई।

श्री अमृतलाल यादव : यह कैसे ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लार्ज स्केल पर सहकारी समिति बनाई थी जिनके 500 सदस्य होते थे और उनको भंग करके छोटी सहकारी समिति भारत सरकार की सलाह पर बनाई गई थी, क्या यह सही है ?

श्री अमृतलाल यादव : वह तो आपको भी मालूम है।

श्री दौलतराम सारण : मुझे भी मालूम है यह क्या उत्तर हुआ ? यह नीति का सवाल है, यह लोगों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लार्ज स्केल समितियां बनाई और उनको तोड़ कर छोटी बनाई गयी और अब छोटी को तोड़कर बड़ी बना रहे हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या यह सही है कि जो भी विभाग आपके पास आया उसी का बन्टाधार कर दिया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्रीमती मदन कौर।

पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में खोदे गये नलकूप

33. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में अब तक जो नलकूप खोदे गये, वे सभी पक्की सड़कों के साथ हैं ? क्या इसका कारण यह है कि पानी के सोर्स सड़कों के साथ साथ ही चलते है ?

(2) क्या पानी के सोर्स सड़कों से दूर रेतीले क्षेत्रों में सम्भव नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान भूतल जल बोर्ड के पास ड्रिलिंग मशीनों को खींचने के उपयुक्त साधन के अभाव में विस्तृत रेतीले क्षेत्र में नलकूप ट्राई ही नहीं किये जा सके ?

(श्रीमती मदन कौर)

(4) क्या डी-क्राउलर ट्रैक्टर ड्रिलिंग मशीनों को रेतीले क्षेत्र में खींच ले जाने में सार्थक हो सकते हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इनकी खरीद का विचार रखती है? यदि डी-क्राउलर ट्रैक्टर इस काम के लिए उपयुक्त नहीं हैं तो क्या कोई अन्य प्रकार की मशीन ड्रिलर्स को रेत में नहीं खींच सकती ?

उप मंत्री कृषि (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं, पश्चिमी रेगिस्तानी जिलों में कई नलकूप पक्की सड़कों से दूर रेगिस्तान के अन्दरूनी इलाकों में खोदे गये हैं।

(2) पानी के स्रोत सड़कों से दूर रेतीले क्षेत्रों में भी हैं।

(3) जी नहीं, राजस्थान भूजल मण्डल के पास ड्रिलिंग मशीनों के खींचने के उपयुक्त साधन हैं तथा विस्तृत रेतीले क्षेत्र में भी नलकूप बनाये गये हैं।

(4) डी-8 क्राउलर ट्रैक्टर ड्रिलिंग मशीनों को रेतीले क्षेत्रों में खींच ले जाने में सार्थक हैं तथा इस प्रकार के दो ट्रैक्टर्स भूजल मण्डल के पास हैं।

श्रीमती मदन कौर : रेगिस्तानी क्षेत्र में सड़क से दूर कहां कहां नलकूप खोदे गये और खासकर बाड़मेर क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं ?

श्री खेतसिंह : रेगिस्तानी इलाके के अन्दर जो सड़क से दूर नलकूप खोदे गये वह जैसलमेर क्षेत्र के अन्दर राजमथाई, पाली-1। बीकानेर क्षेत्र में वासलपुर, खोरू बच्चू लालमदेसर, मीठाकुआ, केसरदेसर, किरचू। चूरू क्षेत्र में घनेरू, बसरंगसर। बाड़मेर क्षेत्र में समीतड़ा व भीमड़ा। ......

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि यह सब सड़क के ऊपर हैं ?

श्री खेतसिंह : आप सुनिये तो सही।

श्री दौलतराम सारण : मैंने सब सुन लिया। आप गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह : जोधपुर क्षेत्र में मोलमकौर आदि।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, केवल दो नलकूप ऐसे हैं कि जो सड़क से दूर खोदे गये हैं और मेरी मान्यता है कि यहां भी कच्ची सड़कें हैं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो इत्तला है उसके अनुसार निवेदन किया। हां, यह सही है कि पहले जितने खोदे गये वह सड़कों के पास खोदे गये और वह एक्सप्लोरेटरी और ज्योलाजिकल सर्वे आफ इन्डिया ने एक्सपेरीमेन्टल बेसिस पर सड़कों के पास खोदे थे और उनको डवलप करके हमने अपने हाथ में लिये हैं लेकिन भूजल मण्डल ने और अकाल के समय में नलकूप खोदे गये हैं उनमें ऐसे भी हैं कि जो रेगिस्तान के बीचोंबीच आये हुए हैं और जैसलमेर क्षेत्र के अन्दर माननीय सदस्य मानेंगे कि पाली-1 सड़क से 30-35 मील दूर है।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : अध्यक्ष महोदय, केवल एक ही खोदा गया है राजमथाई और वह बिलकुल सड़क के पास खोदा गया है।

Page No 12

श्री खेतसिंह : इसके अलावा भी बीकानेर का मैंने कहा बासलपुर का वह भी सड़क से बहुत दूर है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : केवल मात्र एक ही है।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या यह सही है कि जालौर जिले में कोई भी ट्यूबवैल नहीं खोदा गया ?

श्री खेतसिंह : बहुत खोदे गये हैं।

श्री आईदानसिंह : आपने एक भी नहीं बताया। आप बतायें कि सड़क से दूर कौन कौन से है ?

श्री खेतसिंह : यह तो मुझे मालुम हैं कि कौन–कौन से हैं। जैसे नून . . .

श्री आईदानसिंह : कितनी दूर है ? आधी मील पर ही है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति है कि जिन ट्यूब वैल्स के पास सड़क नहीं है और सड़क से दूर हैं उनको सड़कों से मिला दिया जायेगा ? अगर हां, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष : या खिसका दिया जायेगा।

श्री खेतसिंह : इसका भूतल जल मण्डल से सीधा ताल्लुक नहीं है यह काम या तो अकाल राहत के समय किया जा सकता है या फिर नवाब साहब मेहरबानी करें तब हो सकता है।

श्री आईदानसिंह : यह गलत है। जब ट्यूब वैल बने थे तो इनके प्रोडक्ट को मण्डियों में पहुंचाने के लिए ट्यूबवैल को सड़कों से मिला देने का प्रावधान था और यह स्कीम में है अगर आप ठीक तरह से देखेंगे तो आपको मालुम होगा।

श्रीमती मदन कौर : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार से जानना चाहूंगी कि बाड़मेर जिले में केवल दो नलकूप ऐसे बताये जो कि सड़क से दूर हैं और असलियत में यह है कि वे सड़क से करीब–करीब किनारे पर ही हैं, क्या राज्य सरकार भविष्य में रेतीले इलाके और खासकर बाड़मेर जिले में सड़कों से दूर और नलकूप खुदाने का इरादा रखती है ?

श्री खेतसिंह : यह डिपार्टमेंट तो सिर्फ खोदने का काम करता है और इस विभाग के पास अपने अलग से कोई फण्ड्स नहीं हैं कि जिससे नलकूप खोद दें। या तो अकाल सहायता विभाग पैसा देता है और कहता है कि यह यह नलकूप खोद दो, तो हम खोद देते हैं या फिर कभी केनाल डिपार्टमेन्ट कहता है तो हम खोद देते हैं। हमारे खुद के ऐसे फण्ड्स नहीं हैं कि जिससे कि हम खुद ही अपनी मर्जी से खोद दें।

श्री विजयसिंह : चुनावों के समय कहां से पैसा आ जाता है ?

श्रीमती मदन कौर : ड्रिलिंग मशीन और ट्रैक्टर्स का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

श्री खेतसिंह : यह तो अलग से प्रश्न है। मैं कैसे बता सकता हूं लेकिन मैंने निवेदन किया कि यह साधन हमारे पास हैं और यदि कोई सज्जन इसके लिए पैसे जमा

(श्री खेतसिंह)
कराने के लिए तैयार हैं तो हम उसके यहां भी भेजने का प्रयास करेंगे।

श्रीमती मदन कौर : क्या यह सही है कि यह बेकार पड़ी हैं ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि अनेक किसानों ने अपने कुए ब्लास्ट और बोरिंग कराने के लिए पैसा जमा करा रखा है और उनके कुए नहीं खुदवाये जा रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : यह अलग से प्रश्न है लेकिन जो प्रायोरिटी रजिस्टर है और जिनके पैसे जमा कराये हुए हैं प्रायोरिटी बेसिस पर हम उनको भेजते रहे हैं और उनका काम चलता रहता है।

श्री दौलतराम सारण : आपने कैसे कह दिया कि कोई सदस्य पैसा देगा तो हम तुरन्त भेज देंगे। आप बिना प्रायोरिटी के कैसे भेज देंगे ?

श्री अध्यक्ष : सब्जेक्ट टू प्रायोरिटी।

श्री आईदानसिंह : क्या यह सही है कि भूतल जल मण्डल के पास आज कोई भी योजना नलकूप बनाने की नहीं है ?

श्री खेतसिंह : आप मेरे जवाब को नहीं समझे हैं। मैंने निवेदन किया कि योजना या तो योजना विभाग बनाता है या फिर अकाल सहायता विभाग बनाता है।

श्री आईदानसिंह : मैं अर्ज करूंगा कि आपके पास में कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिसके तहत नलकूप खोदे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : यह खुदवाने का काम करते हैं, योजना का नहीं।

श्री आईदानसिंह : फण्ड्स तो होने चाहिये ?

श्री खेतसिंह : अभी भी खोदे जा रहे हैं। योजना डिपार्टमेन्ट ने पैसा दिया जैसे राजाखेड़ा के अन्दर खोद रहे हैं। हमारे खुद के पास ऐसा फण्ड नहीं है कि जिससे हम अपनी मर्जी से यह नलकूप खुदवा सकें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या आप ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं कि ट्यूब वैल . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है 22 वर्ष की आजादी के पश्चात् कि पश्चिमी क्षेत्रों के अन्दर अमुक जगहों पर इतने नलकूप खोदे जायेंगे और उस सम्बन्ध में सरकार कितने नलकूप अभी तक खोद चुकी है ? इस सम्बन्ध में क्या मन्त्री महोदय जानकारी देने की स्थिति में हैं ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया अध्यक्ष महोदय कि जैसे पब्लिक हैल्थ इन्जीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसके पास प्रावधान है कि अमुक गांव के अन्दर नल योजना के द्वारा पानी वितरण करेंगे, अगर वह डिपार्टमेन्ट लिखता है कि इस गांव के अन्दर खुदवाना चाहते हैं और इतना फण्ड हम डाइवर्ट करते हैं तो हम उसके अनुसार ट्यूबवैल खोदते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : जिन गांवों में ट्यूबवैल खुद गये हैं उन गांवों में बिजली पहुंचाने का इरादा है क्या सरकार का ?

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट 34।

कोटड़ी तहसील में चिकित्सा की व्यवस्था

34. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ी तहसील में कई पंचायत हैडक्वार्टर ऐसे हैं जहां किसी भी प्रकार की चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो वहां औषधालयों की स्थापना के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बड़ला, गेंदल्या, जीत्या, सूंठेका आदि कई गांव ऐसे हैं जहां तुरन्त दवाखाने खुलने चाहिएं ?

राज्य मन्त्री, आयुर्वेद (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) कुछ पंचायत हैडक्वार्टर्स स्वयं पर चिकित्सा सुविधा नहीं है किन्तु इनसे दो से आठ मील की परिधि में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर्स पर अर्थाभाव के कारण औषधालय खोलना संभव नहीं है।

(2) जी नहीं।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अर्थाभाव के कारण लोगों को मरते हुए नहीं बचा सकते हैं तो गरीबी को कैसे हटायेंगे ? दवाखानों के लिए अर्थाभाव है, तो कौन से काम करने के लिए पैसा है ? पंचायत हैडक्वार्टर पर दवा नहीं मिलती है, मोटर नहीं चलती है तो वह हो सकता है लेकिन बिना दवा के लोग मरें और अर्थाभाव है तो हमारी सुख-सुविधाओं को कम करें। आप जो रुपये हमको····

श्री अध्यक्ष : प्रश्न करें माननीय सदस्य।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपका अर्थाभाव कैसे मिटेगा और दवाखाने कैसे बनेंगे ?

श्री अध्यक्ष : क्या अर्थाभाव मिट सकने की सम्भावनाएं हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा: राजस्थान में 7361 पंचायत हैडक्वार्टर्स हैं इसलिए 7361 पंचायत हैडक्वार्टर्स पर एक साथ औषधालय खोलना राजस्थान सरकार के लिए असम्भव है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कितने खोलने सम्भव हैं हर साल ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : हर साल खोले जाते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कितने ? मैं यही तो निवेदन करना चाहता हूँ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : इस साल 35 खोले गये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 7 हजार दवाखाने खोलने में कितने वर्ष लगेंगे ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह आप हिसाब लगा लें। इस समय कितने हैं वह मैं बता सकता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मंत्री महोदय ने जो इस तरह का जवाब दिया है इससे बढ़कर दुःख की बात नहीं हो सकती है। लोगों को मरने से बचाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आप लाखों की गाड़ियों में बैठकर घूमा करें।

श्री अध्यक्ष : क्या आप एक लाख की गाड़ी में फिरते हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : नहीं।

प्रश्न संख्या 35

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री हरलालसिंह खर्रा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य।

भारत-पाक सीमा पर पकड़ा गया सोना

36. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर के अन्त में या दिसम्बर, सन् 70 के पहले सप्ताह में पाकिस्तान से लाया गया सौ किलो सोना 9 ऊंटों पर विभाग के अधिकारियों ने जोधपुर में भारत-पाक सीमा पर पकड़ा था और यह सारी अंगूठियां थीं ?

(2) यह सोना लाने वाले तस्करी कौन थे ? उनका नाम, बाप का नाम, जाति और गांव सहित पूरा पता दिया जाय ?

(3) यह सोना कितनी कीमत का था ? कहां से लाया गया था तथा कहां ले जाया जा रहा था ?

(4) इस तस्करी में कुल कितने तस्कर तथा कितने ऊंट पकड़े गये थे ?

(5) क्या यह सही है कि यह खबर दैनिक नवभारत टाइम्स में दिनांक 7-12-70 को छपी है ?

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) जी नहीं, यह गलत है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(5) जी हां, ऐसी खबर अवश्य छपी है, जो गलत है।

श्री हंसराज आर्य : यह नवभारत टाइम्स में 7-12-70 को छपी है—

100 किलो सोना बरामद

"(जोधपुर निस) जोधपुर संभागीय जैसलमेर सीमा से विलंब से प्राप्त समाचार के अनुसार भारतीय सीमा के भीतर ऊंटों के काफिले से एक सौ किलो सोने की तस्कर अंगूठियां पकड़ी गई हैं। यह एक सौ किलो तस्कर सोना नौ ऊंटों पर लदा हुआ पाकिस्तान से आया था। यह ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व सीमा सुरक्षा दल ने भारत से जा रहे तस्करी कपड़े, दो सौ किलो इलायची, भारी मात्रा में लौंग और पाकिस्तान से लाये जा रहे बादाम को भारत-पाक सीमा पर ऊंटों पर बरामद

(श्री हंसराज आर्य)

किया था।"

इतनी बड़ी खबर एक जिम्मेदार अखबार में छपती है तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि उनसे पूछती कि यह खबर छपी है वह किस तरह से छपी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इसमें सीमा-सुरक्षा के लिए आपने रैफरेन्स दिया है। यह खबर पुलिस के सूत्रों से तो अखबार में छपी नहीं है इसलिए इसकी जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। सोने के स्मगलिंग वगैरह को सेन्ट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट देखता है और सीमा-सुरक्षा पुलिस भी देखती है तो केवल पुलिस के लिए ही आवश्यक नहीं था कि वह कन्ट्राडिक्शन निकालती। पता नहीं दूसरे डिपार्टमेंट में, जिनका इससे सम्बन्ध रहता है उनके यहा, कोई कार्यवाही की गई हो।

श्री हंसराज आर्य : क्या पुलिस का यह कर्तव्य नहीं है कि वह इस चीज को देखे कि इस तरह की खबर कैसे छपी है। अगर वह खबर गलत है तो यह तो कह सकती है कि यह गलत है। क्या यह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी ? इतना तो आप कह सकते हैं कि यह जो बात छपी है वह गलत है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने इसके बारे में जानकारी की है और जानकारी करने पर इसको गलत पाया है और अखबार में गलत छपा है।

श्री अध्यक्ष : दूसरे महकमों ने भी कहा है कि वह गलत है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने डी. आई. जी., बी. एस. एफ. और सैन्ट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से पूछा है तो उन्होंने बताया है कि इस तरह कि कार्यवाही नहीं हुई।

श्री हंसराज आर्य : तो अखबार वाले से पूछते कि यह किस तरह से छप गया।

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई आवश्यक नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : सोना नहीं पकड़ा गया तो लौंग, इलायची, कपड़ा वगैरह पकड़ा गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सोने का पूछा गया था तो उसकी जानकारी की गई।

श्री दौलतराम सारण : अखबार में छपने की जो सूचना दी गई है उसमें सोने के साथ साथ लौंग, इलायची वगैरह भी थी तो उसकी जानकारी करना चाहिए था।

श्री हीरालाल देवपुरा : केवल सोने से सम्बन्धित था।

श्री हंसराज आर्य : सोना ही नहीं है, उसमें इलायची, कपड़ा वगैरह भी है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इलायची, लौंग वगैरा तो कई बार कई जगह पकड़े जाते हैं। कहां पकड़ा, किसने पकड़ा उसकी इत्तिला दें तो जानकारी करके जवाब दिया जाय।

श्री हंसराज आर्य : राजस्थान में तस्कर व्यापार करने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और यह बात सही है कि हमारी सीमा पर ये छाये हुए हैं।

(श्री हंसराज आर्य)
मैं कहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इन लोगों पर कन्ट्रोल करे नहीं तो राजस्थान भर में ये फैल जायेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह सरकार के ध्यान में है और सरकार ने सक्रिय कदम उठाकर कई बार इनको पकड़ा भी है। माननीय सदस्य कोई खास सूचना दें तो उनकी सूचना के अनुसार कार्यवाही की जा सके।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मनोहरसिंह मेहता।

बेडच नदी पर पुल

37. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कस्बा बडल्यास और बंरूदनी के मध्य बेडच नदी पर खुर्रा या पुल न बनाने से वर्ष भर में लगभग 6 महीनों तक बसें व ट्रक नहीं आ जा सकते और आवागमन एक तरह से रुक जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्षा-काल में आज भी हजारों लोगों को नदी उसी प्रकार तैर कर पार करनी होती है जैसे आजादी के पूर्व किया करते थे ?

(3) क्या उक्त नदी पर जिसका सम्बन्ध सैंकड़ों गांवों से है पुल बनाने का इरादा सरकार रखती है ? यदि हां, तो क्या इसी वर्ष उक्त पुल का काम प्रारम्भ हो सकेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) बडल्यास और बरूंदनी के मध्य आवागमन किस अवधि तक अवरुद्ध होता है इस विभाग की जानकारी में नहीं है क्योंकि यह मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(2) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(3) जी हां विचाराधीन है। अर्थाभाव के कारण पुल-निर्माण कार्य इस वर्ष संभव नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नवाब साहब से . . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय साहब।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मन्त्री महोदय, माफ करियेगा।

यह निवेदन करूंगा कि आप खुद बेडच नदी पर पधारे थे और आपको मालूम है कि 6 महीने रास्ता बन्द रहता है। क्या आपको यह मालूम है कि गर्भवती औरत को भी उसी तरह से नदी को तैर कर उतार कर आना पड़ता है जैसे कोई पशु तैरता हो ? क्या यह सही है कि आपने यह वायदा किया था हजारों आदमियों के सामने कि इसी वर्ष में यह पुल जल्दी से जल्दी बनेगा ? क्या यह सही है कि तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में आपने यह फर्माया था ?

एक माननीय सदस्य : भूल गये होंगे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसमें कुछ बातें सही हैं और बहुत कुछ गलत हैं। मैं कोई वायदा नहीं करता हूं। वायदा उसी चीज

(श्री अमीनुद्दीन अहमद)

का करूंगा जब कि कोई चीज मैं कर सकूंगा। इसलिए मैं वायदा कभी नहीं करता हूं। ऐसी स्थिति राजस्थान में बहुत सी जगहों पर है और ऐसी जगहें मैंने जाकर देखी हैं राजस्थान में। हालात जैसे हैं उसमें कोई न कोई साधन होने चाहिए। अगर नहीं हो सकते हैं तो दूसरी बात है। वायदा मैं नहीं कर सकता हूं। आपने कहा था कि 20–25 हजार देने के लिए तैयार हैं चन्दा करके, तो मैंने कहा था कि मैं देखूंगा कि कुछ रकम किस तरह से और मिलाकर यह काम तैयार किया जा सकता है। मैं वही काम कर सकता हूं सड़कों का जो कि प्रायोरिटी लिस्ट में है। जहां सड़कें नहीं हैं वहां काम करना बड़ा कठिन है। विशेष तौर से जहां कोई सड़क नहीं है वहां कोई प्रायोरिटी मेरे लिए नहीं है। आपने कहा था कि आप कुछ चन्दा करा कर दे सकते हैं। तो मैंने इन्सानियत के नाते सोचा था कि अगर मेरे पास से कुछ प्रावधान हो सका तो करवा दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या यह पुल इसलिए नहीं बना कि मनोहरसिंहजी मेहता ने कुछ रुपये नहीं दिये ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मेरे सामने मनोहरसिंहजी के स्थान पर कोई भी साहब हो मेरा फर्ज है यह देखने का कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। उस नाते वह है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैंने 25 हजार का वादा उस समय भी किया था और आज भी तैयार हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या मनोहरसिंहजी मेहता 25 हजार रुपया दे दें तो पुलिया बन जायगी ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : ये आधी रकम दे दें। जितने में तैयार हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं समझता हूं कि पुलिया की बात उतनी ही आवश्यक है जितनी कि सड़क की। मैं समझता हूं कि मौके का मामला देखते हुये इस महत्वपूर्ण मुकाम पर पुलिया बनाना मैं परम आवश्यक समझता हूं। क्या मन्त्री महोदय 25 हजार के पचड़े में न पड़कर इसके मौके को देखते हुये दो क्षेत्रों को मिलाना परम आवश्यक नहीं समझते हैं ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जैसा मैंने कहा है, यह एक ही मौका नहीं है, बहुत से ऐसे राजस्थान में हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिया की 25 हजार राशि निर्धारित की है तो सड़क कितने रुपये लेकर बनायेंगे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : मैंने यह प्रायोरिटी की बात कही है। इसके अलावा कोई और बात हो तो दूसरे नजरिये से देखी जायगी।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह दरियाफ्त करना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो काम किया जाता है उसके लिए क्या यह आवश्यक है कि पैसा दिया जाये तभी होगा ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : अगर कोई पैसा देना चाहे तो। उसमें हमें आसानी हो जायेगी।

Page No 19

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस 25 हजार में कोई कमी बेशी की गुंजाइश है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बेशी हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: यह 25 हजार रुपया इकट्ठा कर लिया गया है क्या ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक एक घर से पैसा लिया जायेगा। लाखों को तकलीफ है इसलिए मैंने कहा है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय यह पी. डब्ल्यू. डी. में कितने परसेण्ट कायदा है लेने का ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : कोई कायदा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : फिफ्टी फिफ्टी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 25 हजार तो हम आज ही कर लेंगे। लेकिन आप तब तक कार में नहीं चलेंगे। जीप में चलेंगे। आप यह संकल्प कर लीजिये। आप काम शुरू करवा दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : संकल्प तो नवाब साहब ने जब निकाह किया था तब भी नहीं किया था।

श्री अध्यक्ष (माननीय मन्त्री से): आप जब उधर गये तो क्या किसी जगह दर्द भी हुआ था ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : बहुत सी जगह दर्द हुआ था ?

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर में जब आप पिछली बार दौरे पर गये थे तो वहां एक मुसलमानों का ग्राम भानपुरा है वहां आप का स्वागत किया गया था। आपने सड़क बनाने के लिए कहा था। वह रुपया कहां चला गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से नहीं है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : इसका मैं इस लिए जवाब देना चाहता हूं कि आपने मुसलमानों का नाम लिया है हालांकि वहां सिक्ख भी थे वह सभी मिले। खासकर मुसलमानों का नाम लिया यह गलत बात है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मगर मैं कहना चाहता हूं कि वहां के लिए आपने क्या सोची जो वहां सड़क बनाने के लिए सोची उसको आप जरूरी समझते हैं ? टीबों की सड़क है, वह जरूरी नहीं समझते हैं। उसके लिए अर्थाभाव के कारण कार्य नहीं कर सकते हैं। बहाना करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : कहीं सड़क पर दो दो फुट के गड्ढे पड़े हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : किसी दूसरी तरफ सड़क बनाने के लिए खासतौर से आप आदेश देते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री लादूराम सुलानिया।

श्री हरलालसिंह।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न संख्या 35। यह बहुत आवश्यक है। इसका उत्तर दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : पहले जो हैं उनको देख लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह हैं नहीं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह बहुत जरूरी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समाजवादी प्रश्न है 'राजकीय कृषि फार्म' मुनाफा नुकसान क्या है?

श्री मनोहरसिंह मेहता : इससे लाखों की बचत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री। अच्छा 35 है।

एक माननीय सदस्य : कृषि मंत्री।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री।

राजकीय कृषि फार्म

35. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (सवाई माधोपुर) की अनुपस्थिति में (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल जौहरी बाजार, जयपुर द्वारा पूछा गया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कहां कहां राजकीय कृषि फार्म कितने कितने एकड़ में कब कब से चालू हैं?

(2) उपरोक्त फार्म चालू होने के बाद उन पर हर साल कितना कितना खर्चा हुआ व कितनी कितनी आय हुई? सालवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : इसे मैं स्थगित करने के लिए निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : चलो, टण्टा ही मिटा। प्रश्न समाप्त हुये। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

खण्डेला–कोटड़ी सड़क

श्री हरलालसिंह खर्रा (सवाई माधोपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या खण्डेला से कोटड़ी (सीकर जिला) सड़क बनी उसकी लम्बाई ज्यादा बता कर ठेकेदार को पेमेन्ट कर दिया गया था? यदि हां, तो वास्तव में कितनी लम्बी सड़क बनी थी व कितनी का पेमेन्ट हुआ व इसकी रिपोर्ट किस अधिकारी ने की?

(2) क्या राज्य सरकार द्वारा जांच करने पर ठेकेदार से रकम काट ली गई है? यदि हां, तो इसकी जानकारी कैसे हुई व कितनी रकम काटी गई?

(3) इसमें मौके के किस किस अधिकारी को दोषी पाया गया व किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही आज तक की गई?

(स्थगित किया गया)

मारवाड़ी बागरी जाति के व्यक्तियों को प्लाटों का आवंटन

30. **श्री लादूराम सुलानिया** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री मादूराम सुलानिया)

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगर स्थित आदर्श नगर में मारवाड़ी बागरी (अनुसूचित जाति) के परिवार लम्बी अवधि से अपना जीवन झुग्गियों में बीता रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि इनमें कुछ परिवारों को नगर विकास न्यास द्वारा भू-खण्ड आवंटित किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कितने परिवारों को ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त बस्ती के निवासियों को आवश्यक धनराशि नगर विकास न्यास में लम्बी अवधि पूर्व जमा हो जाने के बाद भी उन्हें अभी तक आवंटित भू-खण्डों के कब्जे नहीं दिये गये जबकि उनके द्वारा न्यास के अधिकारियों व अन्य उच्चाधिकारियों तथा मंत्री महोदय को सैंकड़ों प्रार्थना-पत्र दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उन्हें आज तक कब्जे क्यों नहीं दिये गये ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि इस बस्ती के निर्माण हेतु अब तक सडक व नल योजना की व्यवस्था नगर विकास न्यास द्वारा नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में ही उपरोक्त बस्ती के निवासियों को उनके अलोट शुदा प्लाटों के कब्जे दिलाकर व उन्हें अन्य आवश्यक सुविधा प्रदान करायेगी ? यदि हां, तो किस तिथि तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

1. जी हां ।

2. जी हां । इस क्षेत्र में बसे सभी 23 परिवारों को न्यास द्वारा भू-खण्ड आवंटित किए गए थे ।

3. जी नहीं । कुछ एक को छोड़कर लगभग अधिकांश भू-खण्डों के कब्जे सम्बन्धित व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं । कुछ भू-खण्डों में हरिजन परिवारों के अनाधिकृत मकान आ जाने के कारण उनका आधिपत्य नहीं दिया जा सका किन्तु अब उन हरिजन परिवारों के समीप भी निर्माण किए जा रहे क्वार्टर्स का आवंटन शीघ्र किया जायेगा अतः शेष बागड़ियों को भी उनके भू-खण्डों का कब्जा बहुत शीघ्र ही दिया जाना सम्भव हो जायेगा ।

4. योजना के मानचित्र में मुख्य नगर नियोजक द्वारा अधिक भू-खण्डों का प्रावधान रखते हुए संशोधन किया गया जो न्यास को दिनांक 30-7-70 को प्राप्त हुआ । इस संशोधन के अनुसार वहां बसे हरिजनों को हटाकर निर्मित क्वार्टर्स का आवंटन किया जाना है ताकि आवंटित भू-खण्डों का आधिपत्य बागड़ियों को देते हुए हरिजनों को भी सुव्यवस्थित रूप से बसाया जा सके । अब इस योजना में सड़क व नल योजना में निकट भविष्य में प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ।

5. संशोधित मानचित्र के अनुसार अधिकांश आवंटियों को यथा समय उन्हीं भू-खण्डों के कब्जे दिलाए जाकर बसा दिया गया है और निकट भविष्य में उन्हें आवश्यक सुविधायें दिए जाने हेतु न्यास शीघ्र कार्य कर रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

22. श्री **हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या आयुर्वेद विभाग ने इस वर्ष कोई नया अनुसंधान किया है ?

(2) यदि हां, तो कौन सी नई औषधी तैयार की है और वह किस प्रकार की बीमारी के लिए लाभ दायक सिद्ध हुई है ?

(3) राजस्थान में ए. बी. और सी. श्रेणी के औषधालयों को श्रेणीवार सालाना कितनी कितनी दवाएं दी जाती हैं ?

(4) क्या यह सही है कि गांवों में जन संख्या बराबर बढ़ती जा रही है ? यदि हां, तो क्या भविष्य में जन संख्या के अनुपात से औषधालयों को दवाएं दी जावेंगी ?

(5) 1 जनवरी, 1970 से 31 दिसम्बर, 1970 तक कुल कितने नये औषधालय खोले गये हैं ? जिलेवार तहसील-वार व गांववार सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उत्तर

1. जी नहीं ।

2. प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

3. प्रति वर्ष 'अ' श्रेणी औषधालय को 6000 से 24,000 'बी' श्रेणी को 2400 रुपये की औषधियां एवं 'सी' श्रेणी को 1200 रुपये की औषधियां सप्लाई की जाती हैं । इसके अतिरिक्त रोगी संख्या के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त औषधियां भी उपलब्ध करायी जाती हैं ।

4. जी हां । रोगियों की आवश्यकता अनुसार औषधियां दी जावेंगी ।

5. सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

चूरू जिले में आयुर्वेदिक औषधालय

23. श्री **रावतराम** (छापर) : क्या आयुर्वेद मन्त्री, यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला परिषद् चूरू ने जिले के किन किन गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव भेजा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रस्ताव कब आया और इस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

1. जिला परिषद् चूरू ने निम्न गावों में वर्ष 1970-71 में औषधालय खोलने के प्रस्ताव भेजे हैं ।

1. लखासर 2. धानोती बडी 3. जैठासर 4. जसरासर 5. चांमोई 6. सहला 7. तेहग देसर 8. लोहडिया ।

2. उक्त प्रस्ताव दिनांक 22-8-70 को प्राप्त हुए । ग्राम धानोती बडी एवं

(आयुर्वेद मंत्री)
सहला में इस वर्ष नये औषधालय खोल दिये गये हैं।

बुलडोजरों का उपयोग

24. **श्री हंसराज आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान सरकार के पास में कुल कितने बुलडोजर हैं और उनका कहां कहां पर क्या उपयोग हो रहा है ?

(2) जिन किसानों की भूमि बुलडोजरों से समतल की जाती है वह किस शर्त पर की जाती है ? क्या किसानों को कुछ अनुदान भी दिया जाता है ?

(3) यदि हां, तो क्या अनुदान दिया जाता है ?

(4) क्या भूमि समतल करने के लिए कर्ज भी दिया जाता है ?

(5) यदि हां, तो वह कर्ज किस शर्त पर किसानों को दिया जाता है ?

(6) क्या कुछ बुलडोजर गंगानगर जिले में भी भूमि समतल कर रहे हैं ?

(7) यदि हां, तो कितने बुलडोजर हैं ?

(8) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या वहां गंगानगर में बुलडोजरों की आवश्यकता नहीं है ?

उत्तर

(1) कृषि उद्योग निगम के पास चालू व्यवस्था में कुल 23 बुलडोजर हैं और उनका उपयोग कोटा, हनुमानगढ़ और यपुर क्षेत्र में हो रहा है।

(2. व 3.) कृषि उद्योग निगम द्वारा बुलडोजर से किसानों की भूमि प्रत्येक घण्टे की दर से समतल की जाती है। कृषि व उद्योग निगम द्वारा किसानों को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है परन्तु राज्य सरकार भूमि समतल करवाने के लिए 10 प्रतिशत रकम अनुदान के रूप में देती है।

(4) भूमि समतल कराने के लिए कुल प्रमाणित खर्च का 10 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

(5) जी हां। यथा सम्भव बजट में प्राप्त धनराशि के अनुसार सहकारी भूमि विकास बैंक तथा व्यापारिक बैंक भी इस कार्य के लिए ऋण देती हैं।

(6) ए. आर. सी. स्कीम के अन्तर्गत भूमि समतल करने के लिए ऋण दिया जाता है। पहले तीन वर्षों में किसी प्रकार के ऋण की वसूली नहीं की जाती है। 3 साल के बाद हर साल सालाना बराबर किश्तों में ऋण की बसूली 10 साल में की जाती है जिस पर 9 प्रतिशत ब्याज वसूल किया जाता है।

(7) जी हां। 3 बुलडोजर हैं।

(8) वहां गंगानगर में तीन बुलडोजर कार्य कर रहे हैं परन्तु और अधिक की आवश्यकता है। अतिरिक्त बुलडोजर खरीदने के प्रयत्न जारी हैं।

कृषि स्नातकों को काश्त के लिए भूमि

25. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री हंसराज आर्य)

(1) राजस्थान में आज तक कितने कृषि स्नातकों को आजीविका के लिए काश्त की भूमि दी गई है ?

(2) क्या भविष्य में और भी भूमि ऐसे स्नातकों को दी जावेगी ?

(3) क्या इस प्रकार के स्नातकों के लिए कहीं पर कृषि भूमि रिजर्व की गई है ?

(4) यदि हां, तो कहां पर और कितने एकड़ ?

(5) यह भूमि किस शर्त पर दी जाती है ?

(6) क्या उनको सर्विस मिलने पर यह भूमि उनसे वापिस ले ली जावेगी ?

(7) जिन स्नातकों की दरख्वास्तें बाकी हैं उनको भूमि कब तक दे दी जावेगी? कुल कितनी दरख्वास्ते हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान के राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में 75 कृषि स्नातकों को 1172 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र के राजस्व तहसील अनुपगढ़ में कुल 3125 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है ।

(5) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना सहकारी भूमि आवंटन एवं विक्री) नियम, 1967 के नियम 17 (ए) के तहत निम्न शर्तों पर भूमि आवंटन किया जाता है—

1—भूमि स्नातकों का बेरोजगार होना ।

2—खुद काश्त करना ।

3—अन्य भूमि हीनों की तरह इनसे भी भूमि का मूल्य लिया जावेगा ।

4- आवंटन की तिथि के पांच वर्ष के अन्दर वेरोजगार कृषि स्नातकों को जिनको कि भूमि आवंटित की गई है, रोजगार मिल जाने पर भूमि कीमत के पेटे जितनी किश्तें हासिल होंगी वे वापिस कर दी जावेंगी ।

5-सुधार पर कृषि स्नातकों द्वारा जो खर्च किया जावेगा उसका मुआवजा दिया जावेगा ।

(6) जी हां ।

(7) खरीफ फसल से पहले पहले अलोट कर दी जावेगी । उपनिवेशन आयुक्त कार्यालय में कुल 199 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

26. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या गैर कृषि स्नातक मंडी सचिवों का वेतन कृषि स्नातक मंडी सचिवों के समान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री हंसराज आर्य)

(2) क्या गैर कृषि स्नातक सचिवों का वेतनमान कृषि स्नातक सचिवों के वेतनमान के बराबर करने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो समान कार्य करने वालों के लिए वेतनमानों में असमानता क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने इनका वेतनमान समान करने का निर्णय ले लिया है ? अगर हां, तो आदेशों की क्रियान्विति में क्या बाधा आ रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि 'क' श्रेणी की मंडियों में नियुक्त किये जाने वाले सचिवों का वेतनमान निर्धारित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार 'ख', 'ग' श्रेणी की मंडियों हेतु भी अलग से वेतनमान निर्धारित करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और आज तक ना करने का क्या कारण है ?

(5) राज्य की 'क', 'ख', 'ग' श्रेणियों की कुल कितनी कितनी मंडियां हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(6) क्या यह सही है कि राज्य में जब से कृषि उपज मंडियों का गठन हुआ है उसी समय से कार्य करते आ रहे मंडी कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ? अब सरकार उक्त नियम कब तक बनाने का विचार रखती है ?

(7) क्या सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति को कार्यालय भवन व कृषक विश्राम गृहों के लिए भूमि आवंटित कर दी है ? यदि हां, तो किन किन मंडी समितियों को कब कब और कितनी कितनी व किस कीमत पर दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या भाखरा क्षेत्र में नोहर भादरा की नई मंडियां अभी तक आबाद नहीं हुई ? क्या इन नई मंडियों को कृषि उपज मंडी समितियां आबाद शीघ्र कर सकती हैं ? क्या सरकार नई मंडियों की भूमि को कृषि उपज मंडी समितियों को हस्तान्तरण करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं, तो इसमें क्या बाधा आ रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। 1-9-'68 की राणावत रिपोर्ट के अनुसार रिविजन आफ पे स्केल के अन्तर्गत जो कृषि सहायक 155-485 की वेतन श्रृंखला में कार्य कर रहे थे और कृषि स्नातक थे उनकी वेतन श्रृंखला को रिवाइज करके 225-525 किया गया। मण्डी सचिव जो कृषि स्नातक नहीं थे उनकी वेतन श्रृंखला में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उनकी वेतन श्रृंखला में परिवर्तन किए जाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। (क) श्रेणी के मण्डी समितियों के सचिवों की वेतन श्रृंखला 375-850 निर्धारित कर दी गयी है। (ख) व (ग) मंडी सचिवों के वेतनमान अलग से निर्धारित करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(कृषि मंत्री)

(5) सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है ।

(6) मण्डी समितियों के सेवा नियम सम्बन्धी प्रस्तावित प्रारूप समितियों के पास उनकी सम्मति, सुझावादि हेतु प्रसारित किए गए हैं । उनके प्राप्त होने पर अंतिम रूप दिया जा सकेगा ।

(7) कुछ मण्डी समितियों को राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गयी है' प्रतापगढ़ में 14 बीघा तथा गुलाबपुरा में 31 बीघा । कुछ स्थानों में छोटे छोटे भू-खण्ड भी उपलब्ध कराये गये हैं ।

(8) यह प्रश्न कृषि विभाग से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि इसका सम्बन्ध उपनिवेशन विभाग से है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

राज्य में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र

27. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कहां कहां पर किस प्रकार के कितने कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये है ?

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकार गर्भाधान से पशुधन में कमजोरी आई है ?

(3) राजस्थान में राजकीय सांडशाला कहां कहां पर हैं और उनसे सालाना कितने सांड तैयार करके गांवों को किस कीमत पर दिये जाते हैं ?

(4) राजस्थान में कहां कहां के तालाबों में मछलियां पकड़ने के ठेके दिये जाते हैं ?

(5) क्या इन ठेकों के लिए कोई धनराशि निर्धारित है या नीलामी बुलाकर ठेके दिये जाते हैं ?

(6) इन ठेकों से सरकार को सालाना तालाब वार क्या आय होती है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(7) राजस्थान में कुल कितनी कुक्कुट शालाएं हैं और शालावार आज तक उनको कुल कितना कर्ज दिया गया है और कर्ज की शर्तें क्या हैं ?

(8) क्या मुर्गियों में भी कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है ?

(9) राजस्थान में कहां कहां पर ऊंट शालाएं हैं क्या उनमें भी कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है ?

(10) राजस्थान में कहां कहां पर सरकारी दुग्ध-शालाएं हैं ? क्या वे शालाएं सभी घाटे में चल रही हैं ?

(11) यदि हां, तो क्यों ?

(12) उपरोक्त सूचना सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राजस्थान में जिन जिन स्थानों पर गर्भाधान केन्द्र, ग्राम आधार योजनाएं खोली गई है उनकी सूचना संलग्न है ।

(2) जी नहीं ।

(पशुपालन मंत्री)

(3) राजस्थान में नोहर में एक सांड शाला है और इसके साथ साथ, 6 गौसंवर्धन शालायें है वहां पर जो बछड़े पैदा होते हैं उन्हें भी वितरण किया जाता है। विगत तीन वर्षों में वितरण सांडों का ब्यौरा संलग्न है। पंचायत समितियों को सांड मुफ्त देने की व्यवस्था है तथा किसानों को व्यक्तिगत रूप से जो सांड वितरण किये जाते हैं वह मूल्य का 50 प्रतिशत की कीमत पर लिये जाते हैं। तालिका संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

(6) तालिका संलग्न है।

(7) राजस्थान में 7 राजकीय और 640 निजी कुक्कुट शालायें हैं। निजी कुक्कुट शालाओं को कितना ऋण स्वीकृत किया गया है की सूची संलग्न है।

(8) जी नहीं।

(9) राजस्थान में केवल एक ही ऊंट प्रजनन केन्द्र है जो बीकानेर में स्थित है।

(10) ऊंटों में कृत्रिम गर्भाधान नहीं कराया जाता है।

(11) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(12) उपरोक्त ही।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कत्ल का मामला

28. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आज से 3 साल पहले भादरा तहसील में थाना भादरा में रासलाना ग्राम पंचायत के सरपंच श्री हरलाल यादव का कत्ल हुआ था ?

(2) यदि हां, तो आज तक उस कत्ल के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया ?

(3) क्या यह सही है कि भादरा थाने के अधिकारियों ने कातिलों से रिश्वत लेकर उस कत्ल को वट्टे खाते लिख दिया है ?

(4) क्या इस केस में जयपुर से किसी अधिकारी को लगाया जावेगा ?

(5) क्या भादरा कस्बा से एक मील के फासले पर आज से चार साल पहले जो कत्ल गांव जनाने के एक नायक हरिजन का हुआ था उस कत्ल के कातिलों को पकड़ लिया गया है जो भादरा थाना की सीमा में हुआ था ?

(6) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(7) क्या वह नायक आत्मघात करके खुद मरा था ?

(8) क्या कातिल कत्ल के बाद में उस नायक का ऊंट भी चुराकर ले गये थे ?

(9) यदि हां, तो क्या उस ऊंट की चोरी का पता लगाया गया, तथा वह ऊंट किसका था ?

(10) वह नायक क्या किसी के सीरी रहता था ?

(श्री हंसराज आर्य)

(11) यदि हां तो उस सीरी रखने वाले का क्या नाम है ? कौनसा गांव है ?

(12) इस जनाने के नायक की कत्ल की और रासलाना के सरपंच की कत्ल की किस किस अधिकारी ने जांच की है ?

(13) क्या इन दोनों कत्लों की जांच करा कर कातिलों को शीघ्र पकड़ा जावेगा ?

(14) यदि हां, तो कब तक ?

(15) क्या दोनों कत्लों के मुल्जिम इलाके में छुपे हुए हैं ?

(16) क्या यह सही है कि दोनों कत्लों के मुलजिमों को पुलिस गिरफ्तार करना नहीं चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है।

(2) इस हत्या अपराध में एक ही अपराधी रामेश्वर पुत्र गिरधारी नायक साकिन जटान था जो बाद वारदात के ही फरार है। पुलिस द्वारा उसकी गिरफ्तारी के भरसक प्रयत्न करने तथा उसकी हाजरी के लिये धारा 87–88 जाब्ता फौजदारी की कानूनी कार्यवाही कराने के बावजूद भी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका है।

512 का चालान 19–11–68 को किया और 27–10–70 को कोर्ट ने इस कार्यवाही को पूरी कर दी।

(3) जी नहीं, यह गलत है।

(4) जी नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मुलजिम नामजद होकर इश्तहारी मफरूर है।

(5) जी हां, भादरा सीमा में होने वाली हजारी नायक की हत्या हुई थी। इस अपराध के अपराधी का बावजूद भरसक प्रयत्न करने पर भी सुराग नहीं चला है इसलिये अपराधी गिरफ्तार नहीं हुये।

(6) क्योंकि बावजूद भरसक प्रयत्न के भी यह अपराध अदम पता रहा है।

(7) जी नहीं।

(8) जी हां।

(9) जी नहीं, चोरी गये ऊंट का पता नहीं लगा है। यह ऊंट जोताराम पुत्र रामजान जाट साकिन जटान का था जो वक्त वारदात हजारी मृतक के पास मिला था।

(10) जी हां।

(11) सीरी रखने वाले का नाम जोताराम पुत्र रामजान जाट है यह जटान का रहने वाला है।

(12) हजारी नायक की हत्या अनुसंधान एस.एच.ओ. भादरा तथा उदमीराम निरीक्षक सी. आई. डी. (सी. बी.) द्वारा की गई है।

(13) श्री हरलाल सरपंच की हत्या की अनुसंधान एस.एच.ओ. भादरा ने की है। दोनों मुकदमों का अनुसंधान किया जा चुका है। रासलाना गांव के मुकदमे में मुलजिम फरार है जिसकी गिरफ्तारी की चेष्टा जारी है।

(गृह मंत्री)

14. इसके मुतल्लिक कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

15. मुलजिमान फरार हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वे कहां छिपे हुए हैं।

16. जी नहीं।

मारवाड़ी बाकरियों को भवन निर्माण हेतु भू-खंड

29. श्री लाडूराम सूलानिया (फागी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जयपुर नगर परिषद् सीमा के क्षेत्र आदर्श नगर में मारवाड़ी बागरियों को भवन निर्माण हेतु गत पांच वर्षों से अब तक भू-खण्ड नगर विकास न्यास जयपुर से अलाट किये जाकर वसूली करली गई है। यदि हां, तो जिन लोगों से अलाटशुदा भू-खण्ड की राशि ले ली गई हैं उनके नाम, पिता का नाम, जाति भू-खण्ड का क्षेत्रफल व अलाट करनें की तिथि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि अभी तक उपरोक्त वसूली के अलोट शुदा भू-खण्डों के कब्जे उन गरीब पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को नहीं दिये गये हैं जिन्होंने राशि जमा करा दी हैं और अपना तथा अपने परिवार का जीवन झोपडियों व तम्बुओं में बिता रहे है। यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं उनके नाम, पिता का नाम, जाति के सूची सदन की मेज पर मय कब्जे नहीं देने के कारण के रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि बिना भू-खण्ड के कब्जे दिये ही उन्हें एक माह का नोटिस तामीर नहीं करने के कारण भू-खण्ड का अलाटमेंट कैंसिल करनें का दिया गया है। यदि हां, तो इसमें क्यों नहीं उन दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया गया जिनकी लापरवाही के कारण दो वर्ष की अवधि व्यतीत हो जानें पर भी आवंटित भू-खण्डों के कब्जे नहीं दिये जा सकें।

(4) क्या यह भी सही हैं कि इस सम्बन्ध में उपरोक्त आवंटित भू-खण्डों के स्वामियों द्वारा समय समय पर नगर विकास न्यास जयपुर के अधिकारियों के समक्ष प्रार्थना की गई हैं।

(5) क्या राज्य सरकार उपरोक्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की दयनीय दशा की ओर ध्यान देकर निकट भविष्य में ही उन्हें आवंटित शुदा भू-खण्डों के कब्जे दिलाकर उनके भवन निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या नगर विकास न्यास परिगणित जातियों के लोगों को प्लाट देते समय इस बात की प्राथमिकता देती हैं कि अलग बस्तियों में इनको प्लाट देकर बसाया जाय यदि हां, तो किन नियमों के तहत?

उत्तर

1. जी हां। यह प्रश्न पूर्व में भी प्रश्न संख्या 606 दिनांक 6-8-69 के अन्तर्गत पूछा जा चुका है और उसकी यह प्रति पुनः भेजी गई है। आवंटियों एवं राशि जमा कराने वालों की सूची विस्तृत विवरण सहित तालिका 'अ' में संलग्न है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

2. अधिकांश आवटियों को आवंटित भू-खण्डों का अधिपत्य दिया जा चुका है । चूंकि मुख्य नगर नियोजक राजस्थान के परामर्श से योजना का मानचित्र दिनांक 30-7-70 को संशोधित कर न्यास को प्राप्त हुआ और इसके अतिरिक्त बागरियों को आवंटित भू-खण्डों पर जिन हरिजन परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा था उन्हें इसी बस्ती में क्वार्टर्स निर्मित कर आवंटन की कार्यवाही की जानी थी अत: आवंटियों के भू-खण्डों का अधिपत्य होने में विलम्ब हुआ वर्तमान में अधिकांश आवंटियों को भू-खण्डो का कब्जा दिया जा चुका है एवं शेष व्यक्तियों को भी बहुत शीघ्र ही अधिपत्य दिये जाने की सम्भावना है ।

3. जी नहीं ।

4. जी हां ।

5. जी हां । अधिकांश भू-खण्डों के कब्जे एवं भवन निर्माण हेतु साईट प्लान दिए जा चुके हैं । निकट भविष्य में शेष भू-खण्डों के कब्जे भी अतिशीघ्र दिए जायेंगे ।

6. जी नहीं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई है:—

(1) श्री बृजवल्लभ बोहरा व श्री रामप्रसाद बोहरा, सदस्य विधान- सभा ने जिला कोटा की तहसील लाडपुरा के तीन प्रमुख ग्राम अभयपुरा, जामपुरा एवं प्रहलादपुरा के किसानों की करीब 2–3 हजार बीघा भूमि को एक लम्बे समय से बाई व दाई नहर से पानी न मिलने के कारण वहां की फसलें सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(2) श्री हीराभाई, सदस्य विधान सभा ने कुशलगढ़ क्षेत्र की खरीफ फसल को कीड़ा लग जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(3) राज्य के बीमा कार्यालय को 3-4 विभागों में विभक्त कर उक्त कार्यालय को बीकानेर, जोधपुर व उदयपुर क्षेत्र में ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

उपरोक्त तीनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है । जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

इनके अतिरिक्त एक और प्रस्ताव की सूचना श्री केसरीसिंह हाडा, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें जिला बूंदी की कच्ची सड़कों को पक्का न करने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है । यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है । अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

इनके अलावा कुछ पेंडिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी

(श्री अध्यक्ष)

प्राप्त हो चुकी है। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(1) श्री शीशराम पूनिया की हत्या के बारे में निर्दोष व्यक्तियों को फसाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य व श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में नागौर जिले में हुई गुण्डागर्दी से सम्बन्धित श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) बारां तहसील के कुछ गांवों को पार्वती नहर का पानी न मिलने के कारण फसल को क्षति पहुंचने के सम्बन्ध में श्री देवीदत्त गाड़िया सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) बूंदी जिले के गुढ़ा गोकुलपुरा बांध का निर्माण कार्य पूरा न होने के सम्बन्ध में श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) अजमेर में जानवरों के अस्पताल के डा. श्री सुरेश शंकर बानी द्वारा महिला को फरार किये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवान दास शास्त्री, श्री श्रवणलाल, श्री बृज वल्लभ वोहरा, श्री लाभचन्द वैद्य, श्री रामप्रसाद बोहरा, श्री अम्बालाल, सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

ऊपर बतलाये गये स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में जो जानकारी राज्य सरकार से मिली है उसको देखते हुये ये स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इनको प्रस्तुत करने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): इस पर बयान तो होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: क्या?

श्री रामानन्द अग्रवाल: ये अजमेर का मामला माननीय सदस्य ने उठाया इस पर बयान तो करा देते।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): अध्यक्ष महोदय, किसी आदमी को कत्ल के केस में झूठा फंसाया जाये, क्या यह अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है?

श्री अध्यक्ष: वह चालान हो चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य: जान बूझकर निर्दोष आदमियों को फांसी पर लटका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य: कोई भी जांच नहीं करवाई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

सब जूडिस में केस चालान हो चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य: चालान हो चुका है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, किसी निर्दोष आदमी को फांसी पर लटका देना...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

Page No 32

श्री गिरधारी लाल व्यास : (आसीन्द) चालान हो चुका है अदालत में।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने गृह मन्त्री को चिट्ठी लिखी, मुख्य मन्त्री को चिट्ठी लिखी लेकिन इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री गिरधारी लाल व्यास : केस का चालान हो गया है, उसके बाद भी आप बोले जा रहे है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल व्यास : केस सब जुडिस है।

श्री अध्यक्ष : केस सब जुडिस है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप कुछ जानते नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने 16 तारीख को रखा था प्रस्ताव, इसलिए मैं

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानना चाहता हूं कि कितनी तारीख को चालान पेश किया गया ?

श्री रामप्रसाद बोहरा : जिला कोटा की तहसील लाडपुरा के तीन प्रमुख ग्रामों को पानी न मिलने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा था

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री रामनारायण चौधरी : शर्म नहीं आती।

श्री रामचन्द्र आर्य : तुमको शर्म नहीं आती।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस तरीके से आप सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाते है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानना चाहता हूं कि किस तारीख को चालान पेश हुआ ?

श्री रामनारायण चौधरी : मुलजिमों की पैरवी करते है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सही कहता हूं। दोषी नहीं हैं। इसकी जांच कराई जाय। राजनैतिक लाभ उठाने के लिए जबरदस्ती चालान किया गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजय सिंह (मकराना) : माननीय सदस्य को इतना बता देने में क्या एतराज है कि किस तारीख को चालान हुआ ?

श्री अध्यक्ष : मेरी जानकारी में नहीं है।

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 33

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने कौनसी जानकारी ली हैं। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं ली है।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): जिला कोटा के सम्बन्ध में मैंने एक महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव रखा है। अभयपुरा, जामपुरा एवं प्रहलादपुरा के किसानों की करीब दो-तीन हजार बीघा भूमि को पानी नहीं मिला है। हम बराबर निवेदन कर रहे हैं कि फसल सूख गई है या सूख जाने वाली है · · ·

श्री अध्यक्ष : रिजेक्ट कर दिया गया है। नहीं स्वीकार किया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानना चाहता हूँ · · ·

श्री रामप्रसाद बोहरा : इस सम्बन्ध में क्या होगा, यह मन्त्री महोदय बता दें। उनको पानी नहीं मिलता है इसलिए गेहूं की फसल सूख जायगी।

श्री अध्यक्ष : जिसका रिजेक्शन हो चुका है उस पर भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था बारां तहसील · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : किस तारीख को चालान हुआ उस मामले का ?

श्री देवीदत्त गाडिया : बारां तहसील के पांच गांव और चार पंचायत समितियों के दस गांवों को नहरी भूमि पर पानी नहीं मिल रहा है · · ·

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं · ·

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्रजी ! बैठिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं बैठता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इस बारे में जानना चाहता हूं कौनसी तारीख को चालान हुआ। मैंने गृह मंत्रीजी को चिट्ठी लिखी है, मुख्य मन्त्री को चिट्ठी लिखी है · · ·

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : माननीय सदस्य बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। देखिये, आपका व्यवहार दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह मामूली बात है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या समझते हैं बात को ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य !

+ + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 34

श्री रामचन्द्र आर्य : निर्दोष व्यक्ति को फंसा कर · ·

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : निकालिये बाहर।

श्री रामचन्द्र आर्य : बाहर निकालने की क्या धमकी देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरीके से व्यवहार करते हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह उकसा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोटा फायरिंग के सम्बन्ध में · ·

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बाहर निकाले जाने की धमकी देना उचित नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें देरी क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य ! (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर .एक माननीय सदस्य को निपटा लेने दीजिये। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप उचित मानते हैं धमकी देना !

श्री अध्यक्ष : हां साहब, अब तो बैठिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानकारी चाहता हूं · · ·

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ! माननीय रामचन्द्र आर्य ! अंकित नहीं हो !

श्री रामचन्द्र आर्य : ++++

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : ++++

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : ++++

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य ! मैं माननीय श्री रामचन्द्र आर्य को · · ·

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): नाम से पुकारता हूं।

श्री अध्यक्ष : निवेदन करता हूं कि वह स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। (श्री रामचन्द्र आर्य के खड़े रहने पर) अब क्या सदन मुझे आदेश देता है ?

श्री देवीदत गाड़िया : जवाब दिला दीजिये। किस तारीख को चालान हुआ।

+++ अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : कोई हद होती है, कोई सीमा होती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस सदन के अन्दर···

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य ! अंकित नहीं हो !

श्री रामचन्द्र आर्य : + + + +

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिल्कुल चेअर की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं माननीय श्री आर्य, आपसे बार–बार निवेदन कर चुका हूं, भूत में भी बार बार निवेदन करता रहा हूं . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो मुझे मालूम है।

श्री अध्यक्ष : और वर्तमान में बहुत निवेदन करता रहा हूं, आप स्थान ग्रहण करें। विघ्न न डालें। मुझे नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य न करें। (विराम) लेकिन मैं बैठूंगा, आप उठेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब नहीं उठेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब नहीं उठेंगे।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामचन्द्र आर्य के खड़े होने पर) यह देखिये।

श्री नत्थीसिंह : क्योंकि मुख्य मन्त्री जी आ गये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने इनको चिट्ठी लिखी हैं।

श्री अध्यक्ष : अंकित नही हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + + +

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय श्री आर्य, आपको नाम से सम्बोधित करना चाहता हूं और मैं बार बार सम्बोधित करके फिर रुक जाता हूं। अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

कोटा फायरिंग . .

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं मुख्य मन्त्री से जानकारी चाहता हूं, क्या मैंने आपको पत्र नहीं लिखा, गृह मन्त्री जी को पत्र नहीं लिखा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं···

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या नोट कहीं करवाया ?

श्री अध्यक्ष : मैं आपको नाम से सम्बोधित कर चुका हूं। अब मुझको बाध्य होकर . . .

श्री विजयसिंह : पत्र लिखने से क्या होगा, पत्थर फेंको।

श्री रामचन्द्र आर्य : पत्र इसलिए लिखा जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। पर्याप्त हो चुका है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हल्ला मत करो।

+ + + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री **दौलतराम सारण** : अध्यक्ष महोदय, यह रामनारायण चौधरी हैं, यह बार बार प्रावोक करते हैं। यह अच्छा व्यवहार नहीं है। आप इनको समझाइये अच्छी तरह से यह माननीय मुख्य मन्त्री जी समझायें। इनका व्यवहार अनुचित है। यह बड़ा गलत तरीका है।

श्री **अध्यक्ष** : एक का ही नहीं है, औरों का भी गलत तरीका है।

श्री **दौलतराम सारण** : इससे दुर्घटना हो जायगी। मैं निवेदन करता हूं, इन माननीय सदस्य को समझाइये, इनका व्यवहार गैरवाजिब है, अनुचित है।

श्री **अध्यक्ष** : सदन में घटनायें होती हैं, दुर्घटनायें नहीं होती हैं। स्थान ग्रहण करें।

श्री **भगवान दास शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय....

श्री **अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें। अभी एक से निपट लेने दीजिये।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : इसका अर्थ यह निकलता है कि सदन....

श्री **अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : + + + +

श्री **अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : + + + +

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य !

श्री **रामचन्द्र आर्य** : + + + +

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप अच्छा हो कि थोड़े...

श्री **रामचन्द्र आर्य** : + + + +

श्री **अध्यक्ष** : थोड़े समय के लिए शांत मन होने के लिए सदन के बाहर चले जांय तो अच्छा है।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : चला जाऊंगा। इस तरह व्यवहार करते हैं, यदि मेरे चले जाने में लाभ है।

श्री **अध्यक्ष** : मन शांत हो जायगा, मस्तिष्क शांत हो जायगा।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : शांत नहीं होगा, जब तक न्याय नहीं होगा।

श्री **अध्यक्ष** : मैं बाध्य होकर....

श्री **रामचन्द्र आर्य** : इससे मेरा मन शांत नहीं होगा।

श्री **अध्यक्ष** : मैं बाध्य होकर, आपके व्यवहार से बाध्य होकर आगे का कदम उठाना नहीं चाहता। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री **मनोहर सिंह मेहता** : विराजो। आर्य साहब।

श्री **अध्यक्ष** : कोटा फायरिंग।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : मैं जानकारी चाहता हूं कि कितनी तारीख को....

+ + + + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : मै माननीय सदस्य को बाहर जाने के लिए आग्रह करता हूं, आप चले जायं।

श्री रामचन्द्र आर्य : बाहर से मैं आया हूं।

श्री अध्यक्ष : एक बार और चले जायं, नियमों के अन्तर्गत आप। माननीय सदस्य।

श्री एक माननीय सदस्य : पांच बजे चले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह खुद को सोचना है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह से···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : आये दिन कत्ल होते हैं, आये दिन गुण्डागर्दी होती है।

श्री अध्यक्ष : कृपया····

श्री रामचन्द्र आर्य : इस प्रकार का व्यवहार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : कृपया सदन छोड़ कर बाहर चले जायं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जा रहे थे, आपने बीच में रोका है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं नहीं रोकता हूं। बाहर चले जायं।

श्री नत्थी सिंह : जब तक आप खड़े रहेंगे जायेंगे कैसे।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माडंलगढ़) : नियम विरुद्ध कैसे करें, साहब।

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब यह हुआ (विराम) कि आप बराबर (विराम) कौनसा कड़े से कड़ा शब्द इस्तेमाल करूं (विराम) आप हुज्जत पर हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इस सरकार को लानत देने के लिए, कि इस प्रकार की सरकार गल्ती····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको कभी जनता बख्शेगी नहीं।

श्री अध्यक्ष : मार्शल माननीय सदस्य को बाहर जाने के लिए····

श्री रामचन्द्र आर्य : अच्छा, अध्यक्ष महोदय मैं आपका आदेश मानता हूं लेकिन सरकार को लानत देते हुए बाहर जाता हूं।

(श्री रामचन्द्र आर्य सदन से बाहर चले गए)

श्री अध्यक्ष : कोटा के संबंध में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा एक स्थगन प्रस्ताव बारां तहसील के 4 ग्राम पंचायतों के 10 गांवों के अन्दर करीब 10 हजार बीघा जमीन पार्वती कैनाल से लगातार पानी न मिलने के कारण जो फसल को नुकसान हो रहा है, उस बारे में है। गेहूं व चने की फसल खड़ी है, वह

Page No 38

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
लगातार सूखती जा रही है। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर राज्य सरकार व्यवस्था करना तो दूर रहा लेकिन वक्तव्य भी नहीं देना चाहती और सदन में····

श्री **अध्यक्ष** : इसको मैंने स्वीकार नहीं किया है।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : मैं नम्र निवेदन करता हूं। आपने इसको लोक महत्व का नहीं समझा।

श्री **अध्यक्ष** : मैंने स्वीकार नहीं किया।

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी के बोलने पर)

आर्डर प्लीज ! आप स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बारां तहसील की 4 ग्राम पंचायतों के 10 गांवों की 10 हजार बीघा जमीन में चने व गेहूं की खड़ी फसल सूखती जा रही है। किसानों के मासूम बच्चों के जीवन मरण का प्रश्न है, वे आजीविका कमाकर खाते हैं, पानी के अभाव में वे बरबाद हो जायं, इससे राजस्थान के अनोत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा ही लेकिन जिन गरीब किसानों ने कर्जा लेकर अच्छे बीज और खाद लेकर इस आधार पर कि पानी मिलेगा फसल बोई, उनके माथे पर बैंक का कर्जा हैं, बोहरे का कर्जा है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिससे किसानों का सीधा संबंध है····

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया।

श्री देवीदत्त गाडिया : यदि उनके लिए व्यवस्था नहीं करते तो वक्तव्य दिलायें मैं आशा करता हूं सरकार सदन में जानकारी देगी। राज्य सरकार को पत्र लिखे गए, किसानों द्वारा तार दिए गए··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : इसलिए मैं पुनः निवेदन करता हूं कि आप मेरे स्थगन प्रस्ताव पर विचार कर राज्य सरकार को बाध्य करें और इस पर वक्तव्य दिलायें।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : आपकी तरफ से व्यवस्था दी गई कि जानवरों की अस्पताल के डाक्टर जानी के बारे में सरकार की तरफ से जबाव आ गया तो फिर सुनाने में क्या दिक्कत है। एक राज्य कर्मचारी दूसरे महिला कर्मचारी को इस तरह धोखे से भगा ले जावे, उस महिला के 18 साल के बच्चे रो रहे हैं, वह 50 साल की औरत है, उसकी कोई सूचना नहीं कि कौनसी कार्यवाही की गई, गिरफ्तार किया गया या नहीं, सस्पेंड क्यों नहीं उसको किया ? यदि कर्मचारी ऐसे काम करेंगे तो जनता को क्या दोष देंगे। इसका मतलब राज्य सरकार का अपने कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं है, यह तो देश और राज्य राज्य सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है। एक हाई क्लास फैमिली की औरत जिसकी 50 वर्ष की उम्र है, उसको इस तरह भगाया जाए तो इसका मतलब राजस्थान में किसी औरत की इज्जत सुरक्षित नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भगवानसहाय शास्त्री : यह चरित्र-हीन जानवरों के अस्पताल का डाक्टर, उसने उसके घर पर जाकर कहा कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, धोखे से उसको ले गया, एक महीना और एक दिन हो गया, दुर्भाग्य की बात है।

श्री अध्यक्ष : जे. के. सिंथेटिक्स कोटा फैक्ट्री में पुलिस फयरिंग पर गृहमंत्री द्वारा वक्तव्य।

श्री हीरा भाई (कुशलगढ) : व्यवस्था का प्रश्न है। आपने वैसे तो मेरे स्थगन वास्तव में जानकारी मांगी है लेकिन जानकारी मांगने का इसमें कोई सवाल नहीं। सवाल लम्बा नहीं है और सरकार भी यहां मौजूद है।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर कल व्यवस्था दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसके पूर्व कि कोटा में जे.के. सिन्थेटिक फैक्ट्री में 24 फरवरी को जो पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई इस सम्बन्ध में गृहमंत्री की ओर से वक्तव्य दिया जाए, मैं आपको स्मरण कराऊं कि परसों जिस समय किशनगढ महाराजा श्री सुमेरसिंहजी, विधान सभा सदस्य स्वतंत्र पार्टी, की हत्या के सम्बन्ध में सदन में चर्चा हो रही थी, उस समय मैंने पेम्फलेट्स का जिक्र किया था जो कांग्रेस कमेटी द्वारा वितरित किए गए हैं और प्रचारित किया गया है सारी जगहों पर। मैंने बूंदी के सिलसिले में हवाला दिया था। मुख्य मंत्री महोदय ने उस समय चुनौती दी और कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है, नई कांग्रेस कमेटी की तरफ से ऐसा कोई पर्चा प्रसारित नहीं किया गया जिसमें किसी प्रकार से विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य महाराजा किशनगढ़ श्री सुमेरसिंह जी के चरित्र पर लांछन लगाया गया हो। मैंने उसी समय मेरे दल के माननीय सदस्य श्री केशरीसिंह हाड़ा से निवेदन किया और उसी समय वह बस से बूंदी चले गये और कल पर्चा लेकर वहां से आ गये। कल मैंने कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। दूसरा कारण था मुख्य मंत्री महोदय स्वयं नहीं थे। इसलिए इस संबंध में विवाद नहीं उठाना चाहता था लेकिन चूंकि मैंने इस सदन में कहा था, वह बात बिल्कुल सही थी। इस प्रकार से प्रचार किया गया है योजनाबद्ध तरीके से। जिस समय मैंने कोटा, झालावाड़ और बूंदी का 19 व 20 फरवरी को दौरा किया था और 21 तारीख को सीकर जिले में चला गया था, वहां श्री केसरीसिंह जी ने यह पर्चा दिखाया था। इसलिये मुझे इसका स्मरण था। इसलिए मैंने पर्चा मंगाया कि मुख्य मंत्री को जानकारी हो जाए। यह पर्चा जैन प्रिंटर्स ने छापा है और जिला कांग्रेस बूंदी ने छपवाया है....

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): अभी आपने छपवाया होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : मैं समझता हूं, मैं गंभीरता के साथ कह रहा हूं, क्योंकि सदन में बात कही थी, पर्चे छपवाने का धन्धा मैं नहीं करता, डबल अकाउन्ट्स रखने का धन्धा आपका होगा।

Page No 40

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात निवेदन करूं कि आप जो पढ़कर सुनायें उसमें कथानक न सुनायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हैडलाइन्स छोड़ देता हूं, केवल कहता हूं कि पुलिस सूत्रों से चाहे अखबारों के सूत्रों से कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है। विधान सभा सदस्य की दु:खद घटना है उस सिलसिले में किस प्रकार से तुरन्त शीघ्रातिशीघ्र [सारे राज्य भर में एक भी उदाहरण दिया हो, कोई तथ्य आया नहीं, सारे फैक्ट्स आए नहीं अभी कोई इन्वेस्टीगेशन कम्पलीट हुआ नहीं चालान पुटअप नहीं हुआ और उसमें सरकारी वक्तव्य नहीं, आप महाराजा की बात छोड़ दीजिए एक विधान सभा सदस्य जिसकी किसी कारण से हत्या हुई, कहीं का सहारा लेकर, चाहे पुलिस का सहारा लेकर चाहे गृह मंत्री का सहारा लेकर चाहे और सूत्रों का सहारा लेकर जनता के दिमाग में यह बात फैलाई गई योजनाबद्ध तरीके से, इसकी निंदा करनी चाहिए और मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसको आप उचित समझते हैं ? उन्होंने भी आबू रोड में भाषण दिया था, जो मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा एक व्यक्ति पकड़ा गया है, सारे रहस्य आयेंगे, केस चलेगा, सी.बी आई जांच करेगी। यह बात तो समझ में आती है। लेकिन यह सारे का सारा क्या क्या साबित करता है ? मैंने जो वायदा किया था उसको निभा रहा हूं। यह पर्चा जैन प्रिन्टर्स द्वारा छापा गया है जिला कांग्रेस बूंदी ने छपवाया है।

पूर्ण घटना पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि अभियुक्त ने पुलिस को बयान दिया है कि घटना वाले दिन 16 फरवरी को अभियुक्त की बहन, जो महाराजा किशनगढ़ के कुए पर काम करती है, को महल में बुलाने के लिए महाराजा सुमेर सिंह ने अभियुक्त से कहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद अभियुक्त ने फोन पर महाराजा को कहा कि उसकी बहन उन्हें उसके गांव परासिया में ही बुला रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अभियुक्त ने बताया है कि उसके गांव परासिया तक पहुंचने से पहले ही उसने महाराजा के सिर में टोपीदार देशी रिवाल्वर से गोली मार दी। अभियुक्त ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन का और महाराजा का नाजायज सम्बन्ध था।

श्री अध्यक्ष : कथानक हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे कहने का मतलब गृहमंत्री कहते हैं कि हमने किसी को कुछ नहीं कहा। यहां भी पुलिस के सूत्रों का हवाला है। अजमेर जिले में यह प्रसारित किया गया श्री मुकुटबिहारीलाल भार्गव किशनगढ महाराजा की चिता पर वोट की रोटी सेकने लगे। दूसरी तरफ लिखा है किस्सा इश्क का, चश्मा राजनीति का।

मुख्यमंत्री जी, राजस्थान में आपकी कांग्रेस पार्टी क्या करती है ? आपको या तो जानकारी नहीं और है तो आपका नियंत्रण नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और यदि आपका नियन्त्रण है तो आप जान बूझ कर भी इन सारी चीजों को रोकना नहीं चाहते। कोई भी आदमी मरे, विधान सभा का एक आदमी मरे और यह घटना होने के बाद भी आपकी कांग्रेस कमेटी, एक विधान बाद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सभा के सदस्य की गोली मार कर हत्या कर दी जाय, इस प्रकार का वातावरण को दूषित करने की हिमाकत करे इससे अधिक क्या कलंकित और निन्दनीय बात हो सकती है ? में यही कहना चाहता हूं।

आप चाहें तो यह पर्चा मैं आपको नजर कर देता हूं । मैं आपको वता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : मेरे देखने को भिजवा दीजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय ।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, पर्चा मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना यह है कि शायद न्याय के उद्धरण से इसको छपवाया गया है और ऊपर क्या लिखा है यह मुझे पता नहीं । कोई कांग्रेस कमेटी या और व्यक्ति इस तरह का छपवाये तो मैं इसको गलत मानता हूं और हमारी कांग्रेस कमेटी की ओर से निकला है तो मैं अफसोस ही जाहिर कर सकता हूं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): कौनसा ऐसा पुलिस अफसर था जिसने यह प्रसारित करवाया है ? 164 में मुल्जिम ने बयान दिये हैं । उसके बाद . . .

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । ऑर्डर माननीय सदस्य ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सिवाय तो और कोई हो नहीं सकता है यह कान्फिडेन्शियल रिकार्ड है । उनके पास कहां से आया ? सिवाय उनके . . .

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा, लेकिन यह कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि जगह जगह पर प्रचार किया गया और स्व. महाराजा सुमेरसिंहजी के चरित्र पर लांछन लगाया गया और राजनैतिक लाभ लेने के लिये यह किया गया इससे बढ़कर और क्या निन्दनीय और बुरी चीज हो सकती है । मैं विशेष तो नहीं कहना चाहता हूं । मुख्य मंत्री महोदय इस पर ऐसी बात भी कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है । ऐसी बात हुई है और मैने कानों से सुनी है ।

श्री देवीलाल (बुरासिया) : आपकी पार्टी से भी ऐसी बात हुई है ।

शासकीय वक्तव्य

जे. के. सिन्थेटिक फैक्टरी कोटा एरिया में, पुलिस फायरिंग के सम्बन्ध में

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मन्त्री गृह) अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल व श्री रामकिशन ने जे. के. सिन्थेटिक्स फैक्ट्री एरिया में पुलिस फायरिंग पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया । इसके तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

जे. के. सिन्थेटिक कोटा के प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच बोनस सम्बन्धी विवाद चल रहा था । सी. पी. एम. के नेतृत्व में संगठित श्रमिकों की मांग थी कि उनको बोनस पचास प्रतिशत की दर से दिया जाय जब कि प्रबन्धक नियमानुसार अधिकतम बोनस बीस प्रतिशत ही देना चाहते थे । इस विवाद पर श्रम विभाग की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

ओर से समझौते की कार्यवाही चल रही थी। सहायक लेबर आयुक्त ने जिलाधीश से इस सम्बन्ध में श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का समय देने का आग्रह किया। दिनांक 2 फरवरी की शाम को प्रबन्धकों, श्रमिकों के प्रतिनिधि सहायक श्रम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की मीटिंग जिलाधीश की अध्यक्षता में हुई और काफी विचार विमर्श के बाद जिलाधीश ने श्रमिकों के प्रतिनिधियों से यह अपील की कि चुनाव के दौरान यदि वे शान्ति बनाये रखें तो उचित होगा। प्रबन्धकों से भी यह अपील की गयी कि 10 मार्च तक बोनस का वितरण न करें। श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने यह आश्वासन दिया कि वे चुनाव की समाप्ति तक कोई कार्यवाही नहीं करेंगे।

इस आश्वासन के बावजूद उसी दिन रात को करीब साढ़े ग्यारह बजे 'बी' शिफ्ट से छूटे हुए श्रमिक फैक्ट्री से बाहर नहीं गये बल्कि केन्टीन के बाहर खड़े हो गये। नये श्रमिक जो 'सी' शिफ्ट में आये उन्होंने कार्य पर रहते हुए टूल डाउन स्ट्राइक कर दी जिससे फैक्ट्री का सारा काम बन्द हो गया। बाहर जो श्रमिक थे उन्होंने मीटिंग कर उत्तेजनात्मक भाषण देना शुरू कर दिया। प्रबन्धकों ने उसी वक्त पुलिस को सूचना दी कि वे शान्ति व्यवस्था के लिए इन्तजाम करें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व सिटी मजिस्ट्रेट फोर्स के साथ करीब दो बजे फैक्ट्री में पहुंचे और मुख्य मुख्य स्थानों पर जाप्ता मामूर कर दिया।

दिनांक 24 को सुबह साढ़े छः बजे मैनेजमेंट ने लॉक आउट घोषित करने का पत्र एडिशनल एस. पी. को दिया व माइक पर घोषणा की कि लॉक आउट कर दिया गया है। अतः मजदूर चले जायं। परन्तु मजदूरों ने जाने से मना किया। उन्होंने नारे लगाये "मरेंगे और मारेंगे।" थोड़ी देर बाद अगली शिफ्ट के मजदूर जो तीन सौ, चार सौ के करीब थे मैन गेट पर इकट्ठे हुए और उन्होंने नारे लगाये व पथराव शुरू कर दिया। इसी समय जो साइड गेट के पास मजदूर थे उन्होंने लाठियां, फरसे, लोहे की शलाकें व लोहे के टूटे हुए पाइप हाथ में लेकर गेट पर तैनात पुलिस जाब्ते पर हमला किया। स्थिति को गंभीर देख कर नगर दण्डनायक ने भीड़ का मजमा गैर कानूनी करार दिया और इसकी घोषणा माइक पर की। भीड़ को तितर-बितर होने के लिये आदेश दिया, परन्तु श्रमिकों ने हटने से मना किया और कुछ सदस्यों ने यह कहा कि पुलिस अगर गोली चलाती है तो हम बम चलायेंगे और पुलिस वालों को मार कर छोड़ेंगे, मगर तितर-बितर नहीं होंगे। वार्निंग के बाद भी जब भीड़ तितर-बितर नहीं हुई तो गैस का प्रयोग किया गया। इस पर भी भीड़ तितर-बितर न हुई फिर पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया। पथराव की अधिकता को देख कर एस. पी. साहब को फोर्स के साथ आने के लिये फोन किया गया।

इसी बीच जो भीड़ गेट के बाहर थी वह गेट तोड़ कर अन्दर घुस आयी और सिक्योरिटी रूम में घुस कर रिकार्ड्स,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

युनीफार्म, आर.ए.सी. गार्ड के बिस्तर व आग से बचाने का सामान जला दिया। फैक्टरी के सिक्योरिटी स्टाफ की बारह बोर बन्दूक निकाल ली और पुलिस पर मुखालिफ होकर कारतूस लोड करने लगे। स्थिति को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने वार्निंग देकर तीन राउण्ड फायर करने के लिये आदेश दिया। इससे बारह बोर बन्दूक वहीं गिर गयी और कमरे में घुसे हुए व्यक्ति भी भागने लगे। बन्दूकों व कारतूसों को अपने कब्जे में लिया गया लेकिन श्रमिक पेट्रोल का भरा हुआ जरीकेन अपने साथ ले जाने में सफल हुए।

स्थिति की गम्भीरता की रिपोर्ट देने सर्किल इन्स्पेक्टर श्री वधावा जब टेलीफोन करने पहुंचे तो पता चला कि भीड़ ने टेलीफोन के तार काट दिये हैं तथा साथ ही पानी की लाइन भी काट दी है पुलिस ने जब भीड़ का पीछा किया और बायें फाटक पर पहुंचे तो वहां भी भीड़ ने बायें फाटक को तोड़ दिया था और पोस्ट ऑफिस और लेबर ऑफिस की बिल्डिंग को आग लगा दी थी। जो पुलिस फोर्स उस एरिया में पहले से थी उसको बचाने के लिये लाठी चार्ज से भी जब सफलता नहीं मिली तो सिटी मजिस्ट्रेट ने वार्निंग देकर दो राउण्ड फायरिंग करने का आदेश दिया ताकि घिरे हुए पुलिस के जवानों को बचाया जा सके। इसी समय फैक्टरी के अन्दर के धमाके की आवाज हुई और उसमें से काफी आग और धुवां निकला। बाद में पता लगा कि यह आग फैक्टरी के गोदाम में लगाई जहां काफी माल पड़ा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और सिटी मजिस्ट्रेट जब उस तरफ जाने लगे तो उन पर भीड़ की तरफ से फायर हुआ। श्री वधावा सर्किल इन्स्पेक्टर व अतिरिक्त एस. पी. के कुछ छर्रे लगे सरदार देवेन्द्र-सिंह व परमेन्द्रसिंह पुलिस के आदमियों को मारने के लिये उकसाते हुए देखे गये। भीड़ ने फिर पत्थर फेंकना शुरू किया और पुलिस पार्टी पर घातक हमले को रोकने के लिये सिटी मजिस्ट्रेट ने दो राउण्ड और फायर करने के लिये आदेश दिया। इससे भीड़ बायें गेट से निकल कर पीछे हट गयी लेकिन कई श्रमिक फैक्टरी की छत पर गये और वहां से पत्थर, लोहे क छड़ें व पाइप फेंकना शुरू किया।

ठीक इसी समय जिलाधीश, डी. आई. जी., व एस. पी. अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुचे। जिलाधीश के कुछ फर्लांग आगे अश्रु गैस की पार्टी ट्रक में जा रही थी और उस पर भारी पथराव होने से ड्राइवर सन्तुलन खो बैठा और ट्रक ट्रेफिक आईलैण्ड से टकरा कर रुक गया। जिलाधीश आदि नीचे उतरे और लाठी चार्ज का आदेश दिया। परन्तु पुलिस फोर्स आगे न बढ़ सकी क्योंकि पथराव काफी तेजी से हो रहा था। इसी वक्त यह देखा गया कि भीड ने गैस पार्टी से गैस राइफल छीन कर ट्रक के बोनेट में डाल कर ट्रक को आग लगा दी। ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकाल कर पीटा जा रहा था। जिलाधीश आदि पर पास की झुग्गियों से तीन बार बन्दूकों के फायर किये गये। हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कोई भी रास्ता न था सिवाय इसके कि आत्म-सुरक्षा में फायर किया जाता। अतः एस. पी. को

Page No 44

(श्री हीरालाल देवपुरा)
फायरिंग का आदेश दिया गया। आठ राउन्ड फायर किये गये और इससे भीड़ तितर–बितर हुई और पथराव भी कम हो गया।

इस प्रकार अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंच सकी और सिटी मजिस्ट्रेट आदि की फोर्स जो काफी घिरी हुई थी उसको मदद मिली। अतिरिक्त फोर्स के पहुंचने व फायरिंग से स्थिति काबू में आयी।

इस प्रकार कुल पन्द्रह राउण्ड फायर किये जिससे पांच आदमी घटनास्थल पर ही मर गये। तीन व्यक्ति जो विशेष रूप से घायल थे अस्पताल पहुंचाये गये परन्तु बाद में वे मर गये। इसके अतिरिक्त 69 व्यक्तियों को और चोटें आई जो हॉस्पिटल में भरती कराए गये जिनमें से 57 को छुट्टी दी जा चुकी है। दूसरी ओर पुलिस पार्टी में गैस पार्टी के ट्रक का ड्राइवर बेहोशी की हालत में लाया गया और दो कोन्स्टेबल गम्भीर स्थिति में पाये गये। कुल मिलाकर 55 पुलिस कर्मचारी घायल हुए जिसमें एडीशनल. एस. पी., सी. आई. व दो सब–इन्सपेक्टर शामिल थे। इनमें से 14 पुलिस कर्मचारियों को अस्पताल में भरती कराया था जिसमें से तीन की हालत अधिक गम्भीर थी। स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिए 107 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और धारा 144 लगाकर जुलूस आदि पर रोक लगाई गई। अस्पताल से जो व्यक्ति छूटे उनमें से 42 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 12 बोर बन्दूक के तीन खाली कारतूस बरामद किये हैं।

इस प्रकार हिंसक भीड़ द्वारा आगजनी व तोड़ फोड़ से जे. के. सिन्थेटिक फैक्टरी का करीब 30 लाख का नुकसान हुआ जिसमें सेन्ट्रल मेल्टिंग यूनिट, वाटर फिल्ट्रेशन प्लान्ट, स्टोर आदि का नुकसान शामिल है परन्तु कोप्स के जलाने के नुकसान का मूल्यांकन जारी है। पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग जला दी जिसमें पोस्टल स्टेशनरी जो करीब 200 रु. की थी वह भी जल गई। इसके अतिरिक्त पुलिस की ट्रक व गैसगन जला दी तथा अन्य जीपों को भी नुकसान पहुंचा।

इस पूरे मामले की जांच करने हेतु राजस्थान राजस्व मण्डल के अध्यक्ष श्री जी. बी. के. हूजा को कमीशन ऑफ एन्क्वायरी एक्ट के अधीन दिनांक 26-2-71 को जांच करने के लिए नियुक्त किया था। परन्तु सी. पी. एम. ने इस जांच आयोग से सहयोग करने से इन्कार किया और न्यायिक जांच की मांग की। इस पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इस घटना की जांच उच्च न्यायाधीश के कराई जाय। न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की राय से की जावेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, . . .

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ही पूछे जावेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : 24 फरवरी को जे. के. सिन्थेटिक्स, कोटा में जो घटना घटी और जिसमें राज्य की पुलिस द्वारा निहत्थे असहाय मजदूरों पर जिस तरह से निर्ममता

Page No 45

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पूर्वक गोलियां चलाई गई और जिसके कारण दर्जनों व्यक्ति मौत के शिकार हुए उस सारी घटना के सन्दर्भ में यदि विचार किया जावे तो राज्य सरकार ने अपने वक्तव्य में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया है। सरकार ने बताया है कि वहां की लेबर यूनियन सी. पी. एम. द्वारा संचालित और नियन्त्रित है और जो नक्शा पेश किया है उससे ऐसा लगता है कि फैक्टरी के मजदूर बहुत पहले से ही इस प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही करने की तैयारियां कर रहे थे, इस प्रकार के फरसे, भाले, बम चाकू और पता नहीं क्या-क्या चीजें इकट्ठी कर रहे थे जिनका बहुत लम्बा चौड़ा विवरण सरकार ने पेश किया है।

मैं इस सन्दर्भ में माननीय गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब इस तरह की तैयारी इतने दिनों से मजदूर वहां कर रहे थे तो आपका गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था? क्या आपके कोटा के गुप्तचर विभाग ने कभी भी इससे पूर्व इसकी कोई इत्तला सरकार को दी? और अगर नहीं दी और इस कारण नहीं दी कि ऐसी कोई तैयारी बहुत अरसे से नहीं की जा रही थी तो क्या इस प्रकार के हथियार चार छः घंटे की अवधि में केवल उनको कहीं से उपलब्ध हो गये?

एक पारी समाप्त हुई, दूसरी आई इसलिये यह भी एक महत्वपूर्ण मसला है। दूसरी बात साफ नहीं होती है कि राजस्थान की पुलिस को कोटा की पुलिस को इस सम्बन्ध में हिंसात्मक कार्यवाहियों की, ट्रबल की, इस प्रकार की दुर्घटना की स्थिति फैक्टरी एरिया में होगी, इसकी जानकारी या सूचना पहले मिल चुकी थी? अगर मिल चुकी थी तो पुलिस ने फिर निष्क्रियता क्यों बरती, उसको उसी समय क्यों नहीं रोका? या शायद यह समझा हो कि हम ऐन मौके पर पहुंच कर इस सारी गड़बड़ी को अपनी बन्दूकों के बल पर समाप्त कर देंगे। बन्दूकें हमारे हाथ में हैं, लोगों को हम गोलियों से उड़ा देंगे।

क्या इस स्थिति को टाला नहीं जा सकता था? यदि पूर्व कदम उठाते और पूरी सावधानी बरतते तो मेरी निश्चित मान्यता है कि इस प्रकार की दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

पर एक भावना घर कर गई है पुलिस में कि हम कहीं पर भी जायज या नाजायज गोलियां चलावें हमें कोई कहने वाला नहीं है, हमारे ऊपर बैठे हुए मन्त्रिगणों का वरद् हस्त हमारे पर है और फिर यह जे. के. सिन्थेटिक्स फेक्टरी, इन कांग्रेसी नेताओं की एक प्रकार से अनआफिशियल भागीदारों की कम्पनी है। इसके बारे में अगर कभी गोलियां चलाने की बात आई तो हमारे पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। यह भावना पुलिस में जो काम कर रही है इसके दो कारण हैं।

(1) जयपुर में 7 मार्च 67 को गोलीकाण्ड हुआ, बेरी कमीशन की रिपोर्ट आई, इसमें जिन कर्मचारियों के खिलाफ चार्जेज थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, इसके कारण सारी पुलिस में यह भावना घर कर गई कि जब तक दामोदरलाल जी व्यास और मोहनलाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सुखाड़िया का वरद् हस्त उन पर है, वे जब तक उनके हिमायती हैं, जब तक हम उनके हुक्म को जां बेजा तरीके से बजाते रहेंगे तब तक हमारे पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ सकती। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे किसी पर भी कितनी ही बार गोलियां चलावें, अन्याय और अत्याचार करें।

(2) जे. के. सिन्थेटिक्स का मालिक है, उसके मेनेजमेंन्ट के लोग हैं और जो प्रजेन्ट रिजीम है वह इसके लिए जिम्मेदार है कि जिससे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई। क्या गृह मन्त्री महोदय आज दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें जो लोग मारे गये हैं वे कौन कौन हैं? क्या उन सबके नाम वे पढ़कर सुना सकते हैं और कह सकते हैं कि इनके सिवाय और कोई आदमी नहीं मरा है। यह विवाद का सवाल है। जयपुर में स्थिति बनी। संख्या घटती बढ़ती रही। आज आपने मृतकों की संख्या 8 बताई, वहां के एम. एल. ए. एवं प्रत्यक्षदर्शी लोग 23 बताते हैं, और उस इलाके के लोग अस्सी के आसपास कहते हैं। तो यह बहुत अलार्मिग है। तो इसलिए केटेगोरिकली मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि उन मृतकों के पूरे नाम हाउस में रखें जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उस सारे गोलीकान्ड में मारे गये। और फिर गृह मंत्री स्पष्ट कहें कि इनके अलावा एक भी अन्य व्यक्ति नहीं मरा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो बाकी के तथ्य हैं, वे मेरी पार्टी के सदस्य कोटा से आने वाले कहेंगे। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि जुडीशियल कमीशन से एन्क्वायरी कराने का आपने फैसला किया। पर सी. आई. एम. की यूनियन ने मांग की और लोगों ने भी मांग की कि जुडीशियल एन्क्वायरी कराई जाय, तब जाकर आपने फैसला किया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह फैसला किया है क्या राज्य सरकार इस हाउस में यह कमिटमेन्ट देने की स्थिति में है कि राजस्थान के उच्च न्यायाधीश द्वारा जिस किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त किया जायेगा उसकी फाइनल रिपोर्ट को और फाइण्डिग्स को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेगी, और क्या यह भी बताने की स्थिति में है कि हाई कोर्ट को आपने लिखा है वह कब लिखा, और आपके लिखने के बाद भी हाईकोर्ट का कोई जज काम करने को तैयार है? जजेज के दिमाग पर एडवर्स रिएक्शन रहा है। इस राजस्थान की सरकार ने बेरी कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार करने का तत्कालीन राज्यपाल ने आश्वासन दिया था, पर उस आश्वासन को पूरा नहीं करने के कारण बेरी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने के कारण, उसके फाइण्डिग्स को स्वीकार न करने के कारण, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने के कारण, मुझे आशंका है कि राजस्थान हाई कोर्ट का कोई भी जज इस प्रकार के कमीशन में आवेगा? यह नहीं चाहेगा कि केवल एक इन्वेस्टिगेशन अधिकारी की तरह रिपोर्ट दे दे और फिर डिप्टी सेक्रेटरी की मर्जी की बात है कि वह उसे स्वीकार करे या न करे। तो इस परिस्थिति में क्या सरकार इस स्थिति में है कि कोटा फायरिंग की जुडीशियल एन्क्वायरी बिठाने का जो सरकार ने निर्णय लिया है उसमें एन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट, हाई कोर्ट के जज की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिये वचनबद्ध है ? फिर यह एपॉइन्टमेन्ट जज का कब तक हो जावेगा ? किस तरह की आपने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है ? जुडीशियल कमीशन बिठाने का किस तरीके का निर्णय लिया ? इस सम्बन्ध में सरकार का क्या जवाब है ? जज अपॉइन्ट कब तक हो जावेगा ? कब तक कार्यवाही शुरू हो जावेगी क्या इन बातों का स्पष्टीकरण करके सदन को विश्वास में लेगी सरकार ?

एक बात और निवेदन कर देना चाहूँगा कि सरकार यह भी आश्वासन दे कि पहले बेरी कमीशन के समय की तरह इस कमीशन में ऐसे चुनाव में हारे हुए कांग्रेसी लोगों को वकील नहीं बनाया जावेगा और ऐसे लोगों को एक-एक दिन का हजार, ग्यारह सौ, पन्द्रह सौ रुपया देकर जनता के धन का अपव्यय नहीं किया जावेगा, और इस तरह से हारे हुए कांग्रेसियों को कम्पेन्सेट करने के लिये इस कमीशन का उपयोग नहीं किया जावेगा। मसलन जो चुनाव में हार गये हैं उनको आपने बेरी कमीशन में अपाइन्ट किया था और यह हो सकता है जिनको आप टिकट नहीं देना चाहते हों 72 के चुनावों में, उनको इस प्रकार की पैरवी में आप लगा दें। आपने किस प्रकार से इसकी पैरवी की समुचित व्यवस्था की है ? इस तरह की समुचित व्यवस्था आप को करनी चाहिये कि कम से कम खर्चा इस कमीशन में हो और यह आपको करना चाहिये कि डिफीटेड कांग्रेसमैन को आप इस कमीशन की पैरवी को संचालित कराने में नहीं लगायेंगे और क्या आपने इसके खर्चे का अनुमान लगाया है और गवर्नमेन्ट की तरफ से व्यवस्था करने की क्या व्यवस्था की गई है ? और उसका क्या खर्चा होगा ? कोई एस्टीमेट आपने लगाया है ? अध्यक्ष महोदय, ये सारे प्रश्न इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस सन्दर्भ में मैंने यह सारी बातें यहां पर उठाई हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। यहां हमारी सरकार कहती है कि राजस्थान में मार्क्सवादी कम्युनिस्टों का जाल फैलता जा रहा है और आप विधान सभा में यह गर्जना करते हैं कि राजस्थान में नक्सलवादी पनप रहे हैं। यह कह कर आप राजस्थान को भी बंगाल बनाना चाहते हैं। यह सारी बातें आपके भाषण में होती हैं। परन्तु वास्तव में यह स्थिति नहीं है। कोटा की स्थिति खराब है और आपने मजदूरों पर गोलियां चलवा कर, गोलियों से उनको भूना है और आप क्या उन मजदूरों को मार्क्स की आइडियोलॉजी बता कर बोनेट के पॉइन्ट पर दबाना चाहते हैं ? यह आपका भ्रम है। निश्चित रूप से राजस्थान सरकार इस आधार पर राजस्थान में चलना चाहती है तो यह निश्चित मानियेगा कि राजस्थान को भी आप बंगला बना देंगे। आपकी इन सारी हरकतों से ऐसा लगता है कि आप राजस्थान में अशांति और अराजकता का वातावरण पैदा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार की कोई श्रम नीति है ? क्या राजस्थान सरकार की कोई लेबर पॉलिसी है ? राजस्थान सरकार की एन्टी-लेबर पॉलिसी है और यह राज्य सरकार राजस्थान के कारखानेदारों और पूंजीपतियों के साथ मिली हुई है। बिड़ला सीमेन्ट फेक्टरी का मामला हो (समय-समाप्ति सूचक घंटी) यह सरकार, मजदूर विरोधी कार्य ही करती

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। चित्तौड़गढ़ में दो-तीन महिने तक मजदूरों की हड़ताल चली वहां पर भी इस सरकार ने मजदूरों पर अत्याचार किये। इसी तरह से जे. के. सिन्थेटिक्स में यह सरकार कर रही है। वर्तमान हुकुमत राजस्थान के कारखानेदार जो हैं उनकी गोद में बैठी हुई है और उसके साथ में इसकी सांठ गांठ है। मजदूरों की विरोधी है और उनको पूंजीपतियों के हितों के लिये गोलियों से भूनती रहती है।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और यह भयंकर स्थिति है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि राजस्थान में राज्य सरकार को अपनी नीतियों की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये और जो प्रश्न मैंने यहां पर उठाये हैं उन पर और अधिक विस्तार से न जाकर मैं आशा करता हूं कि सरकार की ओर से कोई उत्तर, जवाब इस सदन में देगी, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह निवेदन करूंगा माननीय सदस्य कि भाषण के रूप में नहीं प्रश्न के रूप में ही कहें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो प्रश्न ही करना चाहता हूं। क्या यह सही है कि जे. के. सिंथेटिक्स के अन्दर जब तक कि मेनेजमेन्ट ने लाक आऊट डिक्लेअर नहीं किया उसके पहले किसी भी प्रकार का झगड़ा जैसा कि सरकार बताती है नहीं हुआ? क्या यह सही है कि बोनस दिये जाने के सवाल का मामला श्रम विभाग की कन्सीलिशन प्रोसिडिंग्स के अधीन विचारार्थ था? क्या यह भी सही है कि वह कन्सीलिशन की प्रोसिडिंग्स फेल नहीं हुई है और न किसी प्रकार की फेल्योर रिपोर्ट ही दी गई थी? क्या यह सही है कि नियमानुसार जब तक कन्सीलिशन प्रोसिडिंग्स चल रही हो कोई भी चाहे मेनेजमेन्ट हो अथवा श्रमिक हो किसी प्रकार की ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकता है जो कि कानून के तहत उसका अधिकार हो? क्या यह सही है कि टूल डाउन करने का अधिकार मजदूरों को जब कन्सीलिशन प्रोसिडिंग्स चल रही हो उसके बाद भी वह करे तो कानूनी है और गैर कानूनी नहीं हो सकता है? क्या यह सही है कि कन्सीलिशन प्रोसिडिंग्स जब चल रही हो तो मनेजमेंट बिना पूछे, बिना स्वीकृति के, 24 घण्टे का बिना नोटिस दिये हुए फैक्ट्री के अन्दर लाक आऊट घोषित नहीं कर सकता है और अगर वह घोषित करता है तो वह इल्लीगल है। यह तथ्य सही है अध्यक्ष महोदय। पहले फैक्ट्री ने लाक आउट घोषित किया और जैसा कि आप ने यहां पर जो वक्तव्य गृह मंत्रीजी ने दिया है उसके बाद ही यह सारा झगड़ा पैदा हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी घटना जे. के. प्रीमीसेज में अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। एक ओर तो लॉक आऊट घोषित किया और दूसरी ओर साथ ही साथ फायरिंग कर दिया गया है और इस फायरिंग के द्वारा मजदूरों को कुचल दिया गया है—यह घटना समझ में नहीं आती है और सी. पी. एम. पर आप चार्ज लगाते हैं। सी. पी. एम. पर आप चार्ज लगावें, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन गृह मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

से जो यहां पर बैठे हैं, उनसे मैं यह एक सवाल करना चाहता हूं कि क्या सी. पी. एम. के एक जिम्मेदार नेता से आपने इस सम्बन्ध में बात नहीं की है, क्या आप उससे बात नहीं कर रहे हैं उसका नेता श्री परमेन्द्र जिनका कि आपने वक्तव्य के अन्दर हवाला दिया है जिनके कि खिलाफ 307 और 395 के केसेज पुलिस में रजिस्टर्ड हैं और जो फरार हैं। उसके साथ हमारे गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने बातचीत की है। मुख्य मंत्रीजी श्री परमेन्द्र ने आप के साथ बैठकर के इसके सम्बन्ध में बातचीत की है। आप एक आफेन्डर से बातचीत कर रहे हैं और इस तरह से आप राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं और जिनकी ओट में आप शांति व्यवस्था की बात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इसमें सी. पी. एम. का हाथ था। सी. पी. एम. का हाथ हो या न हो, इसमें सरकार का हाथ कितना है यह हम आप से पूछना चाहते हैं। इस परमेन्द्र के साथ जो कि फरार है वह आप से मध्यस्थता के लिए बातचीत कर रहा है और आप भी उसको मध्यस्थता के लिए बुलाते हैं और वह आप के बीच में बैठता है। यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। इसमें सी.पी.एम. का हाथ है यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह मेनेजमेंट और सरकार के बीच सांठगांठ के द्वारा फायरिंग हुआ है और बुरी तरह से मजदूरों को कुचला गया है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की फैक्टरी की व्यवस्था है–फैक्टरी में तीन शिफ्ट चलती हैं। पहली ए–7॥ से 3॥ तक, बी 3॥ से 11॥ बजे तक और सी 11॥ से 6॥ तक। इस तरह से शिफ्ट की व्यवस्था इस फैक्टरी में है। जिस समय बी–शिफ्ट 23 तारीख की बात है रात्रि में, आपका कहना है बी शिफ्ट में मजदूर टूल डाउन करके बैठ गये। हमने भी कहा है बैठ गये हैं। उसको अधिकार है टूल डाउन करने का, मजदूरों को टूल डाउन करने का अधिकार है चाहे कन्सीलिएशन प्रोसिडिंग्स चल रही हो। यह बाद में आता है। लेकिन वहां पर वे मजदूर बैठे हैं। आप कहते हैं कि बी के मजदूर निकल बाहर आते हैं और टूल डाउन कर देते हैं जब 6॥ बजे जैसा कि आप कहते हैं लेकिन मेनेजमेन्ट लाक आउट की घोषणा नहीं करता है। कोई नोटिस नहीं निकाला जाता है और जो फैक्टरी का गेट था चाहे वह अन्दर का गेट हो या बाहर का गेट हो–क्या यह सही है कि उन गेटों पर ताला लगा हुआ है, उनको नहीं खोला गया और मजदूरों से कहा गया कि वे बाहर चले जायें। वे कहां से जा सकते हैं? यह मेनेजमेन्ट के इशारे पर चलने वाली सरकार ने मजदूरों पर अत्याचार किया है। आपके गेट पर ताला लगा हुआ है और मजदूर अन्दर बैठे हुए थे यह वस्तुस्थिति है जिसे राजस्थान की जनता अच्छी तरह से जानती है। जे. के. सिन्थेटिक्स इन्डस्ट्री कभी की दिवालिया हो गई होती, परन्तु वह आज राजस्थान सरकार के रहम पर जिन्दा है। राजस्थान सरकार के लोन पर वह जिन्दा है। यह मानी हुई बात है। मुख्य मंत्रीजी अब भी कोटा जाते हैं वे जे. के. के मेहमान बन कर रहते हैं। और कोई मेहमान बन कर रहता है तो····

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह गलत है। मैं हमेशा सर्किट हाउस में ठहरता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपसे मिलने जब भी हम आये हैं आप जे. के. के यहां पर ही ठहरे हुए मिले हैं। वहीं पर हमने आप से भेंट की है। सिंघानिया आपको सी. एम. नहीं मानता है। उससे पूछे तो कहते हैं सुखाडिया सो रहा है। यह भाषा बोलता है आपका सिंघानिया।

तो अध्यक्ष महोदय, तालाबन्दी होती है और सभी मशीनें जो आटोमेटिक होती हैं, चलती हैं। एक दिन भी मशीन बन्द रह जाती है तो उनका लास हजारों-लाखों का हो जाता है। मजदूर टूल डाउन कर देते हैं तो यह उनको बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए यह सांठगांठ थी मेनेजमेंट और सरकार की और इसमें मजदूरों को बाध्य किया गया कि वे मशीनों पर काम करें और काम कराने के लिए उनको तालाबन्दी में रखा गया और मजदूरों ने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। तब मजदूरों को कहा गया कि वे प्रेमीसेज को छोड़कर बाहर चले जायं। मजदूरों पर लाठी चार्ज किया गया, टीयर गैस किया गया यह सब गलत है। टीयर गैस जरूर हुआ है और मजदूरों को धड़ाधड़ भूनना शुरू कर दिया और आज जो सख्या बताई जा रही है मैं कहता हूं यह नगण्य है। मजदूरों का कहना है कि उनको कोयलों में झोंका गया है आज मजदूरों का पता नहीं, मजदूर कहां है? पुलिस का आतंक केवल प्रिमिसेस में नहीं रहा बल्कि सड़क पार उनकी झुग्गी झोंपड़ियों में, जहां बिजली और रोशनी की व्यवस्था नहीं, उन मजदूरों के घरों में जाकर इस पुलिस ने ताले तोड़े और उनके जेवर वगैरह लूट ले गये। और जो वहां मां, बहिनें बैठी थी, मैं अपने शब्दों में कह नहीं सकता हूं क्या हुआ? झुग्गियां खाली हो गई। झुग्गियों में आदमी मिलते नहीं है। आज हजारों आदमियों का पता नहीं है। एक भी मजदूर वहां पर नजर नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न से कह दीजिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हां, प्रश्न के रूप में ही कह रहा हूं। क्या यह सही है कि मजदूरों के नेता बनने वाले समाजवाद का नारा लगाने वाले . . .

श्री गिरधारीलाल व्यास : भूमिका बना रहे हैं। यह भूमिका चलने वाली नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : श्री नाथूलाल जैन, जो वहां से कांग्रेसी उम्मीदवार थे उनके लिए उनसे चन्दा लिया गया था और उनके चुनाव काम आया है पैसा। आपको तो कुछ पता ही नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है यह।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मजदूरों पर रहम रखिये आपको . . .

श्री गिरधारीलाल व्यास : आंसू बहा रहे हो, आपको क्या मतलब है उनसे ?

(दोनों माननीय सदस्य आपस में बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न के रूप में करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको तो लापड़िया, बिड़ला, डालमिया, सौमानी से मतलब है।

श्री देवीदत्त माडिया : सुखाड़िया जी सबकी चमचागिरि करते हैं। बहुत एक्सपर्ट हैं। आपको पता भी नहीं चलता है। ये लाखों रुपया चन्दे का लाकर डकार जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं करते हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय आसीन्द क्षेत्र में गया तो वहां बड़ा आतंक फैला रखा था।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको तो बड़े प्रेम से भाषण देने दिया था।

श्री देवीदत्त गाडिया : ये तो जन्म से कसाई हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपका तो मैंने स्वागत किया था, बड़े प्रेम से भाषण देने दिया था फिर भी आप कहते हैं। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो ये 8 लाशें बताई गई वे सड़क पर बाजार में पाई गई हैं, वे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में जो लाशें थीं उनका तो पता ही नहीं है। मजदूरों का नेतृत्व करने वालों का कहना है बीसों मजदूरों को तो बायलर में फेंक दिया गया और कम से कम वहां 100 गोली के राउन्ड किये गये हैं। किसी की हिम्मत नहीं थी बल्कि प्रयास यह किया गया था कि जो मजदूरों का नेतृत्व करने वाले हैं वे अगर पकड़ में आ जायं तो उनको भी भून दिया जाय। गोली चलाई गई, मरने वाले मर गये, घायल होने वाले घायल हो गये। कितने मरे यह तो सब आगे जाकर पता चल जायगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या जो लोग गिरफ्तार हैं, जिनके खिलाफ मुकदमें बनाये गये हैं क्या राज्य सरकार उन मुकदमों को वापिस लेने को तैयार है ?

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

(12.45 म.प.)

आप मान लीजिये पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तार किया है और पुलिस ने जिनको लाठी-गोली से भूना है, चकनाचूर किया हैं उन मजदूरों को आप जब तक छोड़ेंगे नहीं, उनके छोड़ने के आदेश जब तक नहीं करेंगे तब तक यह ज्युडिशियल इन्क्वायरी पूरी कैसे होगी ? कौन देखने वाला है उसको ? कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। मैंने स्वयं ने सारे वाकिये को नहीं देखा है और मेरे यहां बैठने वाले किसी साथी ने पूरा वाकिया नहीं देखा होगा। जो झुग्गी झोपड़ियों में हैं उनको पहले छोड़िये और फिर उनकी एन्क्वायरी कराइये। अगर इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेंगे तो आपकी यह ज्युडिशियल एन्क्वायरी फाड बन जायगी इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। हो सकता है आपने समझौता किया हो लेकिन आप यहां घोषणा करें जितने मुकदमें बनाये गये हैं वे विथड्रा करें, जितने गिरफ्तार किये हैं उनको रिहा कर दिया जाय और इसके अलावा जो टर्म्स आफ रैफरेन्स है जो हूजा कमीशन को

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

दिये हैं वे सीमित है उन्हें आगे बढ़ाना होगा। पुलिस का आतंक केवल प्रिमिसेस तक ही सीमित नहीं रहा है झुग्गी झोंपड़ियों तक में जाकर बुरी तरह से आंतक फैलाया है। वहां जाकर लोगों को मारा है, पीटा है, गोलियां और लाठियां चलाई गई है और न जाने वहां पर क्या क्या हुआ 354 और 306 तक के केसेज हुये हैं। इसलिये आप इसको आगे बढ़ाये–टर्म्स आफ रैफरैन्स को आगे रखें और इसके बाद जो लोग मरे हैं उनकी तुरन्त क्षतिपूर्ति की जाय, उनको तुरन्त मुआवजा दिया जाय और जो लोग घायल पड़े हैं उनकी चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, 28। तारीख को तीन बजे तक मैं हास्पिटल में था तब तक वहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। वहां पर मजदूरों पर आंसू बहाने वाला कोई नहीं था। न उनके घर के सम्भालने वाले थे उनसे पूछा गया तो बताया गया कि उनका भाई गया, किसी का पति गया, किसी का कोई गया। घर के सब सदस्य चले गये। किसी का कोई पता नहीं था। इस प्रकार से भंयकर आतंक फैला हुआ था। कौन कौन मर गया, कौन जीवित है इसका कोई पता नहीं था। सब जगह हा हा कार मचा हुआ था। यह मैं जरूर कहुंगा कि अस्पताल में दूध की व्यवस्था अवश्य की गई थी लेकिन मेनेजमेंट की ओर से मजदूरों पर आंसू बहाने वाले कोई नही थे। किसी पूंजीपति ने उनके खाने पीने की, फल–फूल की, दवा वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है कि उनके मुकदमे वापिस लिये जायं, मजदूरों को वापिस झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचाया जाय, टर्म्स आफ रैफरैन्स के स्कोप को वाइड किया जाय, जो मरे हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाय, जो घायल हुये हैं, उनको मुआवजा दिया जाय। समाचार पत्रों में आया है कि 20 परसेन्ट से ऊपर मुख्य मन्त्रीजी ने जो मध्यस्थता स्वीकार की है, अब वह मध्यस्थता क्या रंग लायेगी। मरने वाले तो मर गये। न उनकी मरहम पट्टी करने वाले रहे और न उनकी कोई देखभाल करने वाले ही रहे। उनके सारे घर बुरी तरह से बरबाद हो चुके हैं। आज उनके लिये सेन्ट परसेन्ट व्यवस्था की जाय इतना ही मेरा निवेदन है।

इस भीषण कान्ड की मैं समझता हूं राजस्थान के अन्दर कोई अन्यत्र मिसाल नहीं मिल सकती है। किस प्रकार उनको चकनाचूर किया गया है। जैसे मेरे साथी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा आपके पुलिस आफिसर, आपके अधिकारी उन पर घोर अत्याचार कर रहे थे और आप तमाशा देख रहे थे और कह रहे थे कि चुनाव तक किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाये क्योंकि जनता से वोट लेने हैं। आपने पहले ही क्यों नहीं कदम उठाया, बोनस की बात तो कई दिनों से चल रही थी लेकिन आपने वोट के खातिर कोई कदम नहीं उठाया। एक तरफ तो आप नेताओं से मिलकर मजदूरों का हनन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप उनसे वोट लेना चाहते हैं। दोनों प्रकार के स्टेप्स को लेकर आप जस्टीफाई नहीं कर सकते। इसलिये मेरा निवेदन है जिन मजदूरों को गिरफ्तार किया गया है उनको तुरन्त रिहा कर दिया जाय, जो मजदूर मर गये हैं अथवा घायल हुये हैं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उनको तुरन्त मुआवजा दिया जाय, टर्म्स आफ रैफरैन्स को बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं आपसे एक मिनिट के लिये प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं विशेष नहीं कहूंगा ...

श्री दामोदर लाल व्यास : एक मिनिट के लिये मैं अर्ज करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय द्वारा जब ऐडंजोर्नमेंट मोशन को डिसअलाऊ कर दिया जाता है तो उस पर फिर बहस नहीं होनी चाहिये। क्लेरीफिकेशन के लिये कुछ बात पूछी जा सकती है। अभी तक दो माननीय सदस्य बोलें हैं। दोनों माननीय सदस्यों ने आधा आधा घन्टा लिया है। अगर भाषण दिये जाते हैं तो फिर ऐडजोर्नमेंट मोशन को डिस अलाऊ करने का मतलब ही समाप्त हो जाता है–उसको अलाऊ कर देना चाहिये ताकि उस पर फुल डिबेट हो जाय। किन्तु ये दोनों बातें नियम विरुद्ध हैं।

श्री उपाध्यक्ष : केवल प्रश्न पूछे जायेंगे।

महाराल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दो मिनट से ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा तो यही निवेदन है कि मेरा कोई सम्बन्ध मजदूरों से नहीं है लेकिन आखिरकार मैं भारत का एक नागरिक हूं, मुझे कोई पूंजीवादियों से सम्बन्ध नहीं है, न उनके साथ सहानुभूति है और न मैं कोई राजनैतिक दृष्टिकोण से इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार का जो अनाउन्समेन्ट है कि कमिशन आफ इन्क्वायरी अपाइन्ट किया जायेगा मैं समझता हूं कि वह एक पंगु अनाउन्समेन्ट है। अगर "इन्क्वायरी कमिशन प्रिसाइडेड ओवर बाई सो एण्ड सो" हो तो मैं समझता हूं कि वह पूरा अनाउन्समेन्ट है। अगर यह अनाउन्समेन्ट केवलमात्र इस लक्ष्य से है कि लीपा–पोती की जावेगी, लाखों रुपया खर्च किया जायेगा, यही पता नहीं है कि कमिशन आफ इन्क्वारी के अन्दर कौन व्यक्ति छानबीन करेगा, सरकार के लिए मेरे ख्याल में यह अशोभनीय व्यवस्था है और इससे मुझे घोर असन्तोष है। घोर असंन्तोष क्यों है उसका कारण भी स्पष्ट है कि बेरी कमिशन के ऊपर जैसा माननीय सदस्य मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि लाखों रुपया खर्च किया गया, गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च किया गया और उसका रिजल्ट क्या है जीरो, और उसमें लाभ कौन उठाये, यह सरकार। मेरे ख्याल में यह सरकार जनतांत्रिक सरकार नहीं कही जा सकती। अगर यही लक्ष्य है कि बेरी कमिशन के परफार्मेन्स को यहां रिपीट किया जाये तो यह पुलिस की सरकार और लाठी गोली की सरकार है और एक अत्याचारी सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जिम्मेदार आदमी जिसका कोई स्वार्थ नहीं है उसके मुंह से मैंने यह सुना है कि 55 आदमी जो सरकारी वक्तव्य में था कि 55 आदमी घायल हुए और 8 ही आदमी मारे गये–मैंने बहुत जिम्मेदार आदमी से सुना है और दो व्यक्तियों से सुना है कि घायल लोग पेट में गोलियां लगी हुई और उनकी 6–7 आंतें बाहर निकली हुई सवा, सवा और डेढ़, डेढ़ मील की दूरी पर जाकर वह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मरे हैं और मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि उनको भट्टी के अन्दर भून दिया गया और उसके ऊपर कहते हैं कि 8 ही गोलियां चलाई गयीं पुलिस के द्वारा और दूसरी तरफ सरकार का वक्तव्य यह है कि 55 पुलिस के आदमी घायल हुए, यह राजस्थान की पुलिस और यह मिनिस्ट्री दोनों पैनीकी मिनिस्ट्री और पैनीकी पुलिस और 55 आदमी घायल हों और 8 गोलियां चलाये, पुलिस का अपने आप में बहुत कयास है...

श्री कृष्णकुमार गोयल : महारावल साहब, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकारी गोली से घायल हुए उनकी हालत यह है कि एडीशनल एस. पी. ने कहा कि बुशशर्ट में छेद होकर रह गया और दूसरे के पैर में गोली लगी तो ऐसी जैसे कोई मामूली फुन्सी हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे तो राजनैतिक फायदा उठाना नहीं है लेकिन मैंने यह भी सुना है कि पुलिस ने अपनी बचत के कारण अपने हाथों से ट्रक को जलाया और कहा कि मजदूरों ने जलाया है। मैं यह नहीं कह सकता कि यह कहां तक ठीक है ...

श्री दामोदरलाल व्यास : सुनी हुई बात को आप बहुत इत्मिनान के साथ कह सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप यह मालुम करते कि यह सही है या नहीं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपको खुली छूट है आप जो कहें। आप आधा-आधा घंटे तो दूसरों की बात सुन लें और मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं हैरत में हूं बल्कि आपका रवैया हैरतअंगेज है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि यह पंगु अनाउन्समेन्ट है और एक अनाउन्समेन्ट मात्र है, लीपापोती है। इसमें कोई तथ्य नहीं है और मेरे खयाल में आपकी इमानदारी में भी फर्क है क्योंकि मुझे आशंका है कि बेरी कमिशन में जो कुछ हुआ वह इस कमिशन के सम्बन्ध में भी होगा ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : लेकिन आपको सुनी सुनाई बात नहीं कहनी चाहिए ...

(विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा 'बैठ जाओ', बैठ जाओ' भोंपू बैठ जाओ' की अनवरत जोर जोर से आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल व्यास : विरोधी पक्ष के नेता को ...

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री आइदानसिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना है कि विरोधी दल के नेता बोल रहे हैं तो फिर इस प्रकार से व्यवधान नहीं डालना चाहिए और मैं मुखाड़ियाजी से निवेदन करूंगा ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : विरोधी दल के नेता को सुनी सुनाई बात नहीं कहनी चाहिए।

(विरोधी दल के सदस्यों द्वारा बैठ जाओ, बैठ जाओ की जोर जोर से आवाजें)

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के लिए मुख्य सचेतक समस्या हैं।

(शोरगुल अधिक होने के कारण अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री आईदानसिंह : आपको बोलने का अधिकार है लेकिन बाद में बोल सकते हैं। आपका अधिकार किसी ने छीना नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने यह निवेदन किया था...

(भारी शोरगुल के कारण अश्रव्य)

आप सुनी सुनाई बात पर ध्यान मत दीजिए।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे और कोई विशेष नहीं कहना है। मैं कभी यह नहीं चाहूंगा कि राजस्थान में शांति भंग हो। मैं चाहूंगा कि शान्ति भंग करने वालों को सख्त से सख्त सजा हो लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी चाहूंगा कि सरकार की नेकनीयती और ईमानदारी की परख तभी हो सकती है जब कि इस तरह के लूले अनाउन्समेन्ट न हों। लीपापोती करना और इस तरह के पंगु अनाउन्समेन्ट करना यह सरकार का आचरण हीन और निम्न स्तर का तरीका है जिसके द्वारा आप जो भी करें हम सन्तुष्ट नहीं हो सकते। आपकी कथनी और करनी क्या है? आपके परफार्मेन्स से आप साबित कीजिए कि आप ईमानदार और इन्साफी हैं वर्ना मैं समझता हूं कि यह जो कुछ आप करने जा रहे हैं यह लाखों रुपया अपनी बरीयत पर आप खर्च करना चाहते हैं। आपको जो कुछ कहना है कहें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

भाषण नहीं होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : भाषण नहीं दूंगा, मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। क्या यह सही है कि इस घटना से लगभग तीन–चार महीने पहले जे. के. सिन्थेटिक के मेनेजमेन्ट और यूनियन के प्रतिनिधियों के बीच माननीय मुख्य मन्त्रीजी के सामने रिट्रेन्चमेन्ट के सवाल को लेकर एक समझौता हुआ जिसके तहत मुख्य मंत्री जी के सामने मेनेजमेन्ट ने यह स्वीकार किया कि वह तीन–चार सौ आदमियों को रिट्रेन्च करने वाले थे उनको रिट्रेन्च नहीं करेंगे और क्या यह सही है कि इस एग्रीमेन्ट के बावजूद 72 लोगों को रिट्रेन्च इस मेनेजमेन्ट ने किया जो कि इस ऐजीटेशन में उनकी एक मांग थी? और एग्रीड बातों का उन्होंने वायोलेशन किया है इसलिए वह इसके दोषी हैं और इस कारण से प्रोवोक किया। इस प्रकार का डिस्प्यूट है?

दूसरे क्या यह सही है कि वर्दी के संबंध में जो फैक्ट्री इन्सपेक्टर के माध्यम से यह तय हुआ कि फैक्ट्री इन्सपेक्टर जिस किस्म की वर्दी के लिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहेंगे दे दी जायेगी। फैक्टरी इन्सपेक्टर ने अपना फैसला दे दिया और उस फैसले को मेनेजमेन्ट ने नहीं माना और यूनियन की ओर से इस बात के लिए इसरार किया गया कि अपने एग्रीमेन्ट से बाहर मेनेजमेन्ट जा रहा है जो कि डिस्प्यूट का एक कारण है।

तीसरा क्या यह सही है कि बोनस के संबंध में जब कन्सीलिएशन प्रोसीडिंग्स हो रही थीं तो यूनियन की तरफ से यह कहा गया कि यदि 20 परसेन्ट बोनस का पेमेन्ट कर देते हैं और 20 परसेन्ट के अलावा पेमेन्ट के बारे में क्या हो, कब हो और कितना हो, इसका बाद में फैसला कर लिया जायेगा तो यह एश्योरेन्स भी अगर मेनेजमेन्ट की तरफ दे दिया जाये तो यूनियन उसको एग्री करने के लिए तैयार थी लेकिन मेनेजमेन्ट की तरफ से यह इसरार होता रहा कि कानूनन 20 परसेन्ट से ज्यादा लिया ही नहीं जा सकता जब कि वास्तविकता यह है कि 20 परसेन्ट से ज्यादा कलेक्टिव बारगेनिंग के जरिये लिया जा सकता है, कानून मना नहीं करता इसलिए नैगोसियेशन टूटे। नम्बर 4, क्या यह सही है कि ए शिफ्ट ने टूल डाउन स्ट्राइक की और मेन प्लाण्ट के अन्दर सुबह तक रहे और मेंन प्लाण्ट में कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ ? क्या यह सही है कि बी शिफ्ट जो बाहर से चलकर उसमें आ रही थी उसको मैनेजमेन्ट ने बाहर नहीं निकलने दिया और ताला नहीं खोला और उनकी यह बात थी कि इस तरह से मजदूरों को मजबूरी से रखकर उन से काम कराया जाय ? क्या यह सही है कि इस तरीके के टैक्टिक्स पहले भी एक हड़ताल के समय की गई थी ? बहुत सी बातें हैं जो जरूरी नहीं समझता इसलिए उन पर क्वेश्चन नहीं करूंगा। लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों जब यूनियन के लीडर्स मिले हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से और अब ये दुबारा कारखाना चालू करा रहे हैं तो क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस मध्यस्थता को स्वीकार किया है कि 20 पर्सेन्ट बोनस तो मैनेजमेन्ट उन लेबरर्स को दे देगा और 20 पर्सेन्ट से कितना अधिक देना चाहिए इसका आर्बिट्रेशन माननीय मुख्य मंत्रीजी पर छोड़ दिया गया है और वे इसका फैसला करेंगे ? क्या यह ठीक है ? क्या यह सही है कि लेबर लीडर्स को यह आश्वासन दिया गया है कि मजदूरों के खिलाफ चूंकि जुडिशियल एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करने के आर्डर्स दे दिये गये हैं कोई एक्शन नहीं लिया जायगा, कोई चार्जशीट नहीं दी जायगी, किसी किस्म का उनके साथ विक्टीमाइजेशन नहीं किया जायगा, इस किस्म का एश्योरेन्स माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने जो बातचीत लीडर्स और मैनेजमेंट के बीच में हुई है उनको दिया गया है या नहीं दिया गया है ? मेरी जानकारी के अनुसार इन दोनों बातों के बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मध्यस्थता स्वीकार की है और उनका विक्टीमाइजेशन नहीं किया जायगा इसका मैनेजमेन्ट की तरफ से जो मैनेजर हैं उन्होंने मीटिंग बुलाकर मजदूरों से इन्कार किया है कि इस प्रकार की शर्तों को हमने कभी स्वीकार किया है, तो वास्तविकता क्या है ? इसके बारे में इस प्रकार का एश्योरेन्स दिया गया है या नहीं दिया गया है ?

मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि अब भी जैसा कि बयान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में बताया गया काफी मजदूरों पर—करीब 175 मजदूरों पर—मुकद्दमें चल रहे हैं, और जब आपने जुडिशियल एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट करना मन्जूर कर लिया तो यह सब बात बहस तलब हो गई कि किसने आक्रमण किया और किस ने नहीं किया, किस का दोष था, गोली-काण्ड जस्टिफाइड था या नहीं, मजदूरों का डिफेन्स में एक्शन था या आफेन्सिव एक्शन था, ये सब मामले सब-जुडिस हो गये जब कि जुडिशियल एन्क्वायरी का तय हो गया तो क्या सरकार इसको उचित नहीं समझती कि इन तमाम केसेज को या तो वापिस ले ले या वापिस नहीं लें तो सब को सस्पेण्ड कर दिया जाय, और तमाम मजदूर जो भी गिरफ्तार किये गये हैं उनको रिहा कर दिया जाय? वर्ना उनको ऐसा नहीं करने का मतलब यह है कि आप नेगेटिव कर रहे हैं जुडिशियल एन्क्वायरी को और आप सजा दे रहे हैं। संगरिया और गंगानगर में जो गोलीकाण्ड हुए हैं तो सेम कारोलरी है। जुडिशियल एन्क्वायरी मानली हैं तो लोगों पर केसेज न चलायें और लोगों को जेलों में नहीं रखें और उन लोगों को काम पर जाने दिया जाय। जो भी इसमें मजदूर हैं उनको काम पर जाने दिया जाय। यह सामान्यतया बात होना चाहिए। अगर उनको काम पर नहीं लिया जाय तो या काम पर नहीं जाने दिया जाय तो इसका मतलब यह है कि जुडिशियल एन्क्वायरी को आप प्रिजज कर रहे हैं और पहले से ही उनको आप सजा दे रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप दोहरा रहे हैं। यह आप पहले कह चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अन्त में, क्या यह सही है कि सी. पी. एम. यूनियन की तरफ से जो शहीद हुए व्यक्ति हैं, मजदूर, उनके नाम आपको दिये गये हैं। उन्होंने यह कहा है कि कम से कम 19 आदमी हैं जिनके मरने की आशंका है, और ये 13 नाम आपको दिये हैं नामजद मैं उनको पढ़कर सुनाता हूं—

(1) श्री कमरूद्दीन
(2) श्री जमना शंकर,
(3) श्री दौलतराम
(4) श्री लालाराम
(5) श्री मनोहर श्री वास्तव
(6) श्री रामचन्द्र
(7) श्री राम पाण्डे
(8) श्री बाबूलाल
(9) श्री नाथू धोबी
(10) श्री मोहन कीर
(11) श्री रामनारायण
(12) श्री सुरेन्द्रकुमार
(13) श्री लालचन्द

ये 13 नाम आपको दिये हैं। आपने आज ही स्वीकार किये हैं तो क्या आप बता सकेंगे कि इन 13 में से 8 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको कि गोलियों का शिकार होना आप स्वीकार करते हैं और 5 व्यक्ति कौन से हैं जिनको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं? क्या आपने जांच-पड़ताल की है और यह साबित कर सकते हैं कि वे आदमी जिन्दा हैं, वे आदमी मौजूद हैं और गोलियां से नहीं मरे हैं? उनके बारे में आप जो यह स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उसका आधार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
क्या है ? यह प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं और मैं यह चाहता हूं कि उनका उत्तर आप देंगे ।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (मुख्य मंत्री): दूसरे प्रश्नों के बारे में तो गृहमंत्री जी कहेंगे लेकिन अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सवाल जो मेरी मौजूदगी से सम्बन्ध रखते हैं उसके बारे में उठाये हैं, उनके बारे में मै यह निवेदन करूंगा कि वह तारीख तो मुझे ठीक से याद नहीं है या उन्होंने बताई है वही हो··

श्री **कृष्णकुमार गोयल** : म्युनिसिपल इलेक्शन का टाइम था और आपकी आम सभा होने वाली थी ।

श्री **मोहनलाल सुखाडिया**: रिट्रेंचमेंट के बारे में मुझ से एक डेप्यूटेशन मिला था । उस मौके पर कोई स्क्रीनिंग कमेटी उसको एक्जामिन कर रही थी कि उसकी स्ट्रेन्थ क्या होनी चाहिए उसके पहले ही उनको रिट्रेन्च किया जा रहा था तो उस वक्त में मैंने यही कहा था और दोनों पक्षों ने उसको माना था कि जब तक वह एन्क्वायरी होकर कि कितनी स्ट्रेंथ रहना चाहिए इसका फैसला नहीं हो जाता है तब तक इन लोगों को रिट्रेन्च नहीं समझा जाकर इनको वेतन जो अभी मिल रहा है वह मिलता रहे, क्योंकि बाद में अगर कमेटी ने कहा है कि इतना रिट्रेन्च नहीं करना चाहिए और इस बीच में बहुत से लोग बाहर चले जायं और नुकसान उठायें इतने दिन का वह वाजिब नहीं होगा । यह समझकर उसका फैसला किया गया है ।

फैक्ट्री इन्सपेक्टर यूनियन के बारे में कोई निर्णय किया है ऐसा कुछ दिनों पहले जब मुझसे मजदूरों के प्रतिनिधि मिले थे तब उन्होंने कहा कि एक ऐसा फैसला हुआ है, लेकिन उसका वायोलेशन हुआ तो मैंने लेबर कमिश्नर को कहा था कि उसको एक्जामिन कर लें, क्योंकि यह आर्बिट्रेशन मेरी जानकारी में तय नहीं हुआ था । यह मैंनेजमेंट और लेबर के बीच आर्बिट्रेशन का फैसला हुआ था ।

दूसरी बात जो 20 परसेन्ट बोनस के सम्बन्ध में जो मेटर मुझे एक तरह से आर्बिट्रेशन का दिया गया है और 20 परसेन्ट जो देने वाली बात कही गई है उससे ज्यादा किस प्रकार से क्या हो सकता है वह सोचने का अधिकार भी उसमें निहित है, ऐसा मानकार के मैं चलता हूं ।

विक्टोमाईजेशन के सम्बन्ध में जो बात हुई उसमें प्रश्न यह था कि मजदूरों के प्रतिनिधियों ने यह सवाल उठाया था, जिन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है या फैक्ट्री चालू की जाय तो जिस जिस लेबर की रिपोर्ट करें तो उसको सस्पेन्ड कर दिया जाये या डिस्चार्ज तो नहीं कर दिया जायेगा। तो उस वक्त यही निर्णय लिया गया था । जब तक नियम से किसी को कोर्ट में सजा नहीं हो जाये, उन सब को काम पर ले लिया जाये ।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : विड़ावल··

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** : ऐसी बात नहीं हुई है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल**: और रिट्रेचमेंट के बारे में ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैं बता रहा हूँ ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अजी आपका सम्बन्ध तो डण्डे से है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : पिछली बार मिलने आये थे। अग्रवाल के यहां मैंने यह कहा था कि दो तीन दिन में ले आयेंगे। तो मेरे सामने रिट्रेंचमेण्ट नहीं करने की बात हुई थी। उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित होने को थी। नेशनल प्रोडक्टिविटी कौंसिल कमेटी का गठन हो गया है। नुमाइन्दे होंगे।

(विराम)

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके बाद भी 172 आदमी रिट्रेंच कर दिये गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य दिया गया है वह वाक्यात पर आधारित है। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा और माननीय नेता महोदय को एतराज है कि उसमें जज का नाम नहीं दिया गया है। इस विषय में मैं निवेदन करूं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा गया है कि वे किसी भी माननीय न्यायाधीश को इस कार्य के लिए नोमिनेट करें।

Judge of the High Court is to be nominated by the Chief Justice High Court.

चीफ जस्टिस पर ही यह कार्य हम छोड़ सकते हैं। माननीय न्यायाधीश को और रजिस्ट्रार हाईकोर्ट को सरकार की तरफ से पत्र लिखा जा चुका है कि वे माननीय न्यायाधीश को नोमिनेट करें ताकि उसके नाम का नोटीफिकेशन निकाल दिया जाये। इसलिए शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय विरोधी दल के नेता खुद ध्यान देंगे तो देखेंगे कि सरकार को जो करना चाहिए था वह सरकार ने किया है। मैंने यही नहीं किया है कि चिट्ठी ही लिख दी हो बल्कि एडीश्नल एडवोकेट जनरल को भेजा है कि वे इस मामले में शीघ्रता करें जैसे ही हमारे पास नाम आया तो नोटीफिकेशन जारी कर दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कब तक?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बता दूंगा।

एक माननीय सदस्य : सब झूठ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बेरी कमीशन की फाइण्डिग्स पर क्या हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नेता महोदय, मैं जानता हूँ बेरी कमीशन से आपको बहुत तकलीफ हो रही है।

एक माननीय सदस्य : आपको नहीं हो रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अब तक किसी हाईकोर्ट के जज ने कमीशन का चेयरमेन होने से एतराज नहीं किया है। सांगरिया, भादरा और चूरू वाले केसों में हाईकोर्ट के जज इन्कवायरी कर रहे हैं। यह आपका कहना महज भ्रम है कि वे नाराज हैं। जो बेरी कमीशन ने निर्णय लिये हैं, उन पर जो करना है वह हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : हाई कोर्ट के जज जानते हैं कि यह गूंगी बहरी सरकार है।

(शोरगुल व्यवधान)

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : हाईकोर्ट के जज....

श्री **देवीदत्त गाडिया** : आपने क्या किया ?

श्री **दामोदरलाल व्यास** : मैं महसूस करता हूं कि हम एक दूसरे की बात में दखल न दें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आगे काम नहीं चल पायेगा।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : माननीय विरोधी दल के नेता....

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज़ !

श्री **दौलतराम सारण** : यह मुख्य सचेतक का व्यवहार आपत्ति जनक है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : यह तो जो वाकया हुआ है, वह बहुत गम्भीर है। उससे सम्बन्धित सी. पी. एम. के लेबर हैं जो नक्सलवादी हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : सी. पी. एम. और नक्सलवादी की तो आपस में ही नहीं बनती है।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : दोनों में मेल है।

श्री **सतीशचन्द्र अग्रवाल** : यह तो आप कह रहे हैं।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : पुलिस पर लेबर ने पत्थर फेंके। ट्रक में आग लगा दी। स्टोर में आग लगा दी।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आप सब गलत कह रहे हैं।

श्री **विजयसिंह** : पब्लिक की तरफ से ऐसा होने लगेगा तो न आप मिलेंगे और न ही आपकी पुलिस मिलेगी।

श्री **दामोदरलाल व्यास** : अगर पब्लिक की तरफ से जो कोटा में हुआ है, वही किया जावेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

(भारी शोरगुल : व्यवधान)

श्री **देवीदत्त गाडिया** : गोलियां चलवाते हैं....

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : (अश्रव्य)

श्री **दामोदरलाल व्यास** : (अश्रव्य)

श्री **देवीदत्त गाडिया** : यह न्याय करायेंगे....

श्री **दामोदरलाल व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह था.....

(शोरगुल, व्यवधान)

माननीय सदस्य ने यह कहा कि अभी तक मजदूर ऐसा करते हैं। अब पब्लिक भी ऐसा करेगी।

श्री **रामचन्द्र आर्य** : आप भी तो ऐसा करते हैं।

श्री **देवीदत्त गाडिया** : वहां चोपड़ पर गोलियां चलाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब जुडिशिल इन्क्वायरी कराना स्वीकार कर लिया है····

श्री उपाध्यक्ष : इसे चर्चा में नहीं लाया जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास : गृहमंत्री तो वही कह रहा है। आप सभी बोल रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह आपकी भाषा बोल रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : वह भाषा नहीं जाने तो अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : (श्री गोयल से) आप भी यही कह रहे हैं।

(शोरगुल, व्यवधान)

आप तो नाराज इसलिए हैं कि उनको कुचला क्यों नहीं है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौन कितने पानी में है, यह समझ लिया है।

श्री दामोदरलाल व्यास (श्री गोयल और श्री रामानन्द जी से) : आप दोनों बाहर जाकर निपट लेना। यहां तो काम करने दें।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ व्यवधान होने पर) माननीय सिंघवी जी, आपस में बातचीत नहीं होगी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हम सरकार का सहारा नहीं लेंगे। जवाब देना जानते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं कि स्थिति ऐसी पैदा हो गई थी।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसका इन्टेलीजेंस को पहले मालूम क्यों नहीं हुआ जब कि काफी अर्से पहले तैयारी कर रहे थे ? आपने सरकार की तरफ से जो बयान दिया गया है उसको गौर से सुना है उसके अन्दर है कि जो हथियार लेकर आये हैं वह लास्ट पाली के लोग आये हैं जो फैक्ट्री के बाहर थे। पहली पाली और दूसरी पाली के पास नहीं थे। दूसरी पाली ग्यारह बजे जाकर खत्म हो गई, वह निकल कर बाहर नहीं गये। केण्टिन के बाहर खड़े होकर फैक्ट्री के कम्पाउण्ड में शोरगुल ही नहीं किया, बल्कि प्रोवोकेटिव भाषण भी दिये जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता था जो सैकिण्ड पाली के लोग अन्दर गये तब टूल डाउन स्ट्राइक कर दी गई। दो बजे पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुँची, सिटी मजिस्ट्रेट भी गये। उन्होंने समझाने की कोशिश की। समझाते रहे, लेकिन वह समझाने में नहीं आये। तीसरी पाली के लोग आगे गये उन्होंने बाहर शोरगुल शुरु किया कि मरेंगे मारेंगे। इससे हिंसा की प्रवृत्ति की शुरुआत हुई। लोग हिंसा पर उतारू हो गये। इसके अलावा वक्तव्य में जो बातें कहीं, इतनी बातें होने के बाद पुलिस ने गोली चलाई। मैं समझता हूं कि आपको जो कुछ भी आपत्ति है। जो कुछ भी दृष्टिकोण आपका है, ज्यादा अच्छा हो, बमुकाबले इसके कि वह सदन में रखें, वह कमीशन के सामने उपस्थित होकर पेश करें। वैसे मैं जानता हूँ कि आप कमीशन के सामने पेश जरूर होंगे, क्योंकि आप होते रहे हैं।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

यह दूसरी बात है, जैसा रामानन्द जी कहते है कि आपका इरादा दूसरा है मैं कह नहीं सकता, मैं एण्टीसिपेट नहीं कर सकता ।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इनको रिकगनाईज करेंगे गवाह के तौर पर ?

श्री **दामोदर लाल व्यास** : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ बातें जाननी चाही थीं, और वह चाहते हैं कि कमिटमेंट किया जाय कि कमीशन की जो फाइंडिंग होगी उन्हें सरकार ज्यों की त्यों मंजूर कर लेगी । जब भी ऐसा मौका आया है, हमने बराबर यह कहा है :

Commission of Enquiries Act is a self contained Act.

उसके रूल्स हैं उनको आप देख लीजिये । जो पाबन्दी सरकार पर है उससे वह पाबन्द है । परन्तु हाई कोर्ट के जज की राय को सरकार ड्यू वेट और रैस्पेक्ट देगी यह मैं विश्वास दिलाता हूं ।

दूसरी बात रही, वकील उनको रखा जाय या इनको रखा जाय । उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं जहां तक वकील को रखने का सम्बन्ध है, हम किसी पार्टी के बगैर लिहाज के कि वकील इस इस पार्टी का है या उस पार्टी का है–मेरिट के आधार पर वकील को एंगेज करते आये हैं । जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी खुद जानते हैं, उनको सरकार ने कई केसेज में अपना वकील बना रखा है । इसलिए यह नहीं कह सकते कि कांग्रेसी वकील को ही सरकार अपना वकील बनाती है । जो अच्छा वकील होता है, जिसको सरकार उपयोगी समझती है, जो अच्छी पैरवी कर सकता है उसको वकील बनाती है । इसलिए अभी किसको बनायेंगे, किसको नहीं बनायेंगे––अभी कोई इरादा नहीं है, जो अच्छा होगा, काबिल होगा, योग्य होना––उसे बनाया जायगा । हो सकता है, आपका नाम शामिल कर लें यदि आप चाहें तो ।

दूसरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूं, कुछ कानूनी मुद्दे इस सम्बन्ध में उठाये गये हैं, जब कन्सीलियेशन प्रासीडिंग्स चल रही थीं उसके पहले लोक आउट नहीं कर सकते जब कन्सीलियेशन प्रोसीडिंग्स चल रही थीं उस समय टूल डाउन नहीं कर सकते । ये प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में जज को ही डिटरमिन करना पड़ेगा कि किसकी कार्यवाही नाजायज है और किसकी जायज है । मैं समझता हूं कि मेरे लिये इस समय राय जाहिर करना मुनासिब नहीं है ।

इसी तरह से विथड्राअल आफ केसेज का सवाल है । मैं कैटेगरीकली कहना चाहता हूं कि गलत फहमी में नहीं रहें, किसी केस को विथड्रा करने का सरकार का इरादा नहीं है । इस तरह से वायलेन्स हो, इस तरह से हिंसा हो, इस दर्जे की हिंसा हो कि पुलिस पर हमला किया जाय, फैक्ट्री को आग लगाई जाय, हर तरह की गलत हरकत हो तो जुडिसियल इन्क्वायरी के कारण सरकार केसेज विथड्रा कर ले ? केसेज को विथड्रा कर ले तो इसका मतलब यह होगा कि इस तरह की प्रवृत्ति को सरकार प्रोत्साहन देगी । आपको यह जानना चाहिए, जिसका जुर्म है उसको कानून से, अदालत से सजा मिलेगी । केसेज को विथड्रा करने का कोई सवाल नहीं है–– आप इस गलतफहमी में न रहें ।

जहां तक मुलजिमों के छूटने का सवाल है, कुछ लेबर लीडर मेरे पास आये थे ।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैंने कहा था कि अदालत से जमानत करवा लीजिये, छुड़वा लीजिये। जहां तक पुलिस का सवाल है, जिसने भी जुर्म किया है उसका चालान किया जायगा। उनको छुडाना है तो जमानत पर, मुचलके पर छुड़ाना पड़ेगा। यह अदालत का काम है, पुलिस का नही है। पुलिस की निगाह में तो जिसने जुर्म किया है उसको सजा मिलेगी।

बेरी कमीशन के लिए, खैर; मैंने आपसे अर्ज कर दिया है।

आपने यह कहा कि आठ आदमी नहीं मरे, कुछ को चिमनी में झोंक दिया गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि वहां की जो लेवर यूनियन है, उसने कम से कम यह एलेज नहीं किया है कि चिमनी में झोंक दिया गया। इस वास्ते दर्ख्वास्त देकर गये हैं वह मेरे पास है...

श्री मोहनलाल मोरी : जनसंघ वाले हमेशा झूठ बोलते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

यह कहा गया कि बीस आदमी मर गये। मैं जानता हूँ कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्यों को क्या तकलीफ है। वह खुद भी उस बात को कह गये हैं कि म्यूनीसिपैलिटी के इलेक्शन में आपस में फंसवा हुआ था। मतलब है कि उन्होंने इनके खिलाफ वोट दिये थे और उसका म्यूनीसिपेलिटी चुनाव में नतीजा निकला था—उससे आप नाराज हैं। यह हो सकता है दूसरी बात रामानन्द जी ने कही वही हो कि यह यूनियन का सफाया करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। इनका क्या इरादा है, क्या बात है। सी पी एम की है, आपकी है या सी पी आई की। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कानूनी दृष्टि से जो व्यवस्था करनी चाहिए...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : नौ सो चूहे खा कर बिल्ली हज को चली!

श्री दामोदरलाल व्यास : और जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए वह सरकार करेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सौ सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली!

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक मुख्य मंत्री का ताल्लुक है, उन्होंने बता दिया है कि विक्टीमाइजेशन का सवाल हो चाहे किसी का, इसका सवाल नहीं है। कानून से शहादत से जिनको मुलजिम पाया जायगा—उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

आपने तेरह आदमियों के लिए, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने तेरह नामों के लिए पूछा कि जो तेरह नाम दिये थे उनकी क्या हालत हुई। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि तेरह नामों में से सात आदमी तो मरे हैं, एक बाडी अनआईडेंटीफाईड है, यानि आठ, और जो आप तेरह नाम बता रहे हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : 15।

श्री दामोदरलाल व्यास : दो पुलिस ने गिरफ्तार किये हैं, एक अस्पताल के अन्दर मौजूद है। फिर सुरेन्द्र कुमार यह जे. के. सिन्थेटिक की सर्विस में मौजूद है। All the thirteen names have been accounted for.

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौन कौन से गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बाबूलाल का नाम दिया है। ऐसे बाबूलाल फैक्ट्री में तीस है और तीसों मौजूद है। इसलिए अर्ज करता हूं कि तेरह नामों की सूची है वह मैंने बता दी है और रहा सवाल इस बात का कि इसके अलावा हमें यूनियन ने और कोई नाम नहीं दिये हैं। रही यह बात जो चिमनी वगैरह की जो कुछ कहते हैं, विरोधी दल के माननीय नेता की हर बात हर लफ्ज को मैं बहुत इज्जत से देखता हूं सुनता हूं। यह मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं। परन्तु अर्ज करना चाहता हूं कि आप जिस पोजीशन में हैं, आपके ऊपर बडी जिम्मेदारी आती है इस बात की कि जो कुछ कहें, यह न कहें कि मैंने यह सुना है, सही है या गलत है। मुझे···

श्री देवीदत्त गाड़िया : धमकी दे रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय नेता को मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं मैं धमकी वमकी नहीं देता।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जोर से क्यों बोल रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इनको ऐतराज हो सकता है, आप क्यों बोल रहे हैं। आप फिक्र मत करिये। आपके इरादे और नीयत मैं जानता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सुन सुनाकर प्राइमा फेसी केस की जांच कर लिया करें क्योंकि जो कुछ आप फर्माते हैं उसका वजन हम पर पड़ता है, जनता पर पड़ता है···

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसीलिए दुबले हो गये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए आपसे यह प्रार्थना है।

रहा सवाल···

श्री रामचन्द्र आर्य : धर्मराज कहना चाहिए आपको क्योंकि आप न्याय करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप क्यों चिन्ता करते है।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि मेरिट पर ज्यादा बात कहना नहीं चाहता हूं। जो कुछ वक्तव्य दिया गया है माननीय राज्य मंत्री द्वारा, उसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि यह प्रोसीडिंग्स भी उस जुडिशियल इन्क्वायरी के सामने पेश हो सकती है, इसलिए जो कुछ माननीय सदस्यों ने यहां बातें कहीं हैं, उनके सम्बन्ध में सिर्फ इतनी अर्ज करता हूं कि जहां तक मेरी सूचना आफिसियली है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जो एलीगेशन लगाये गये हैं वे सही नहीं हैं।

रहा सवाल, जुडिसियल इन्क्वायरी से डिटरमिन···

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : टर्म्स आफ रेफरैन्स क्या दिये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य बहुत काबिल वकील हैं कोटा के,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

और माने हुए हैं, उनको पता होना चाहिए कि जब नोटिफिकेशन इश्यू होगा उसमें यह दर्ज किया जायगा...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उसमें यह कुछ नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह इश्यू नहीं हुआ है। अभी जज का नाम नहीं आया है, तो टर्म्स आफ रेफरेन्स कैसे बता दूं! टर्म्स आफ रेफरेन्स जिस वक्त नोटिफिकेशन छपेगा आप पढ़ लेना। नोटिफिकेशन बाकायदा गजट शाया में साथ होगा। इस वक्त नहीं बता सकता।

यह बात अर्ज करके मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि आप किसी उत्तेजना में न आवें। जो आठ मजदूर मरे हैं, घायल हुए हैं उसका हमें भी दुःख है। हम भी खुश नहीं हैं। परन्तु यह काम हमें करना पड़ता है, ला एण्ड आर्डर को स्टेट में मेन्टेन करना पड़ता है, करना पड़ेगा और करेंगे, अवश्य ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, जो गृह मन्त्री जी ने...

श्री रामानन्द अग्रवाल : केसेज के विदड्राअल के बारे में आपने नहीं कहा न मैंने यह इनसिस्ट किया था लेकिन क्या पेरेलल दो जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे। दो तरफ पेरेलल इन्क्वायरी कैसे चलेगी। और यह दो इन्क्वायरी एक इसी इन्सीडेन्स की एक उद्योग के बारे में होगी तो क्या मुनासिब होगा? क्या न्याय होगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कानूनी मसला है। इसको अदालत तय करेगी कि आया एक जुडिशियल इन्क्वायरी के साथ साथ दूसरी इन्क्वायरी चल सकती है या नहीं। इसके बारे में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता हूं। जुडिशियल वेल्यू और लीगल वेल्यू तो यह ट्रायल कोर्ट को तय करना है, मुझे नहीं। वह यह समझे कि जुडिशियल इन्क्वायरी का ट्रायल पर असर नहीं पड़ता है और उसकी फाइंडिंग्ज इस प्रकार की बाईन्डिंग नहीं होंगी तो मैं समझता हूं कि ट्रायल चलती रहेगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह गृह मन्त्री ने जो अपना स्पष्टीकरण और वक्तव्य दिया है मुझे बड़ा दुःख है कि जिस गम्भीरता से इस प्रश्न को लेना चाहिये था उन्होंने सिवाय इसके...

श्री दामोदरलाल व्यास : आप क्या जवाब दे रहे हैं मैं उपाध्यक्ष महोदय...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री दामोदरलाल व्यास : यह परम्परा ठीक करिये उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरा निवेदन है...

श्री उपाध्यक्ष : इनकी बात सुनलें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आज गृह मन्त्री जी ने जो स्टेटमेन्ट दिया, कहीं पर उससे मुझे ऐसी झलक नहीं आती कि मरे हुए व्यक्तियों, घायल व्यक्तियों पर फायरिंग हुए है उनके लिये उन्हें पश्चाताप है और वह उन्हें कुछ राहत देना चाहते हैं। आपने

Page No 66

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कहा कि जुडिशियल इन्क्वायरी की घोषणा की है यह शब्द वही है जो बेरी कमीशन के वक्त दिये गये वक्तव्य में यूज किये थे। वे ही आज यूज कर रहे हैं हम इसको व्यू वेट देंगे जो इन टोटो रिपोर्ट आयेगी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह इन्क्वायरी रिपोर्ट लूली लंगड़ी आवेगी वह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक होगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप कह चुके हैं। गृह मन्त्री जी उत्तर दे चुके।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आपने यह भी कहा जो मुलजिम गिरफ्तार हैं उनके केस आप विद्ड्रा नहीं करेंगे जब तक इन कैसेज को विद्ड्रा नहीं करते तब तक यह इस पर जुडिशियल इन्क्वायरी एक फ्रॉड होगी, धोखा होगी। क्योंकि फायरिंग का और किसने देखा है रामानन्दजी भी वहां नहीं थे और मैं भी नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर दुबारा चर्चा नहीं होगी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जो गिरफ्तार हुए हैं वे ही वहां उपस्थित थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गृह मन्त्री जी ने स्टेटमेन्ट दिया है यह सीधे सीधे सौदेबाजी का परिणाम है और आप मजदूरों का शोषण करते है इस आधार पर जो वक्तव्य गृह मन्त्रीजी ने दिया है व पढ़ कर सुनाया है उसके विरोध में मैं अपने दल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किया गया)

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय· · ·

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा ?

श्री दौलतराम सारण : भाषण नहीं देना चाहता हूं एक मुद्दे की बात के बारे में गृह मन्त्रीजी ने जो नहीं कही कि जो घायल हुए हैं, मर गये हैं उनके परिवार को राहत देने, सहायता देने के सम्बन्ध में उन्होंने प्रकाश नहीं डाला, राज्य सरकार द्वारा उनको तात्कालिक क्या राहत पहुंचाई जा रही है यह नहीं बतलाया है वह अब आप बतलाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : (रामानन्द के खड़े होने पर) इस पर दुबारा चर्चा नहीं होगी जैसे दौलतरामजी ने प्रश्न पूछा वैसे ही नया प्रश्न हो और उससे नई बात निकल सकती हो, तो पूछें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने न अभी जुडिशियल कमीशन मुकर्रर किया है और केसेज के बारे में जो रुख लिया है· · ·

श्री उपाध्यक्ष : उसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा दल भी इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करता है।

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किया गया)

श्री उपाध्यक्ष : (रामानन्द के खड़े होने पर) इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसी के प्रति प्रोटेस्ट करता हूं और सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री केदारनाथ: क्या इस बात की आपने स्टडी करली है ला कोर्ट में केस देने से पहले कि मजदूरों की जो शिफ्ट फैक्ट्री के अन्दर थी उस समय कोई तोड़ फोड़ की बड़ी घटना नहीं हुई थी।

श्री उपाध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया है। इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री केदारनाथ : जो पुलिस के आदमी जख्मी हुए हैं क्या उनमें कोई नुमाइन्दा है तीसरे होस्पीटल में जो एडमिटेड है...

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा चर्चा नहीं होगी।

श्री केदारनाथ : उनमें बच्चे और औरतें कितनी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह नया प्रश्न है डिबेट में नहीं आया।

श्री केदारनाथ : यह मेरे तीन प्रश्न हैं जिनको आप स्टडी करलें।

श्री दामोदरलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सहायता देने का प्रश्न है, मुआवजा देने का सवाल पैदा नहीं होगा। मुआवजे का इम्पलीकेशन तब होता है जबकि फायरिंग अनजस्टीफाइड हो, कोर्ट के जजमेन्ट से। एक्सग्रेशिया ग्रान्ट हम बराबर देते हैं। मैं दौलतराम जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो मृत हैं उनके आश्रितों को जिनको आवश्यकता होगी उनको रिलीफ सरकार जरूर देगी।

श्री दौलतराम सारण : आवश्यकता है या नहीं इसका सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा नहीं होगी इसका उत्तर दे दिया गया है उन्होंने कहा कि मुआवजे का प्रश्न है वह जुडिशियल इन्क्वायरी की फाइंडिंग पर निर्भर करता है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने कहा फोरी सहायता के सम्बन्ध में। यह मुआवजे के बारे में कहते हैं वह ठीक है लेकिन सहायता की आवश्यकता होगी या नहीं यह न कह कर यह बताना चाहिये कि आपने क्या तजवीज की है। इस मामले में डेली वेजेज पर जिन्दा रहते हैं क्या आप नहीं मानते हैं कि उसके परिवार या आदमी मर गया, घायल हो गया था और उस परिवार में कमाने वाला नहीं हो कोई दूसरा...

श्री उपाध्यक्ष : यह कन्सीडरेशन किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : इसलिये राज्य सरकार ने क्या ऐसा इन्तजाम कर लिया है कि कितने लोगों को कितनी तात्कालिक सहायता देनी चाहिये और इसका क्या निश्चय किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दूसरी बात रही जो गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि कितने बच्चे थे और कितनी औरतें थीं इसकी तफसील मेरे पास नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री दौलतराम सारण : गृह मन्त्री जी सारी बातों को लाईटली ले रहे हैं।

Page No 68

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात का उत्तर दे चुके हैं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की मजदूरों की नृशंस हत्या की है....

श्री उपाध्यक्ष : आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि उस तरह के लोगों को सहायता दी जावेगी।

श्री दौलतराम सारण : ऐसे गम्भीरता से आपकी बातों को सुना है बड़ी गम्भीरता से आपकी बातों को लिया है मुझे लगा माननीय गृह मन्त्री, विपक्ष की तरफ से जो बातें कही गई हैं उनको बड़ा लाइटली लेते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैं लाइटली नहीं ले रहा हूं।

श्री दौलतराम सारण : आप धमकी भरे शब्दों के साथ बोल रहे हैं यह करेंगे वह नहीं करेंगे कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दे दिया है।

श्री दौलतराम सारण : आप इस धमकी भरी भाषा में बोल रहे हैं और जिस प्रकार के व्यवहार को इसमें पेश कर रहे हैं वह आपत्तिजनक है। बेगुनाह लोगों का खून किया जाय और उनको राहत नहीं पहुंचाई गई और वाजिब मांगों पर गौर नहीं किया गया है और जानबूझ कर मैनेजमेन्ट के साथ हाथ मिलाकर साजिश की गयी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह गलत है।

श्री दौलतराम सारण : मै कहता हूं कि जो व्यवहार आपका उत्तर देने में रहा है और एक्शन लेने में राज्य सरकार ने गैर-जिम्मेदारी दिखायी है उसके विरोध में मैं मेरे दल के साथ बहिर्गमन करता हूं।

(भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन (श्री हीराभाई के खड़े होने पर) आपका वाक आउट मान लिया जायेगा।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : गृह मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है मजदूरों का शोषण करने के लिये फैक्ट्री के मालिकों को प्रोत्साहन देने वाला है आपने अभी एक तरफ कहा कि जुडिशियल इन्क्वायरी कायम की जावेगी दूसरी तरफ कहा कि हम किसी भी तरह कन्ट्रोल करेंगे, मारेंगे, जेल भेजेंगे और सजा भी देंगे। यह आप क्या कह रहे हैं? बिना जांच का नतीजा निकले मन्त्रीजी ने जो यह कहा इससे लोगों को न्याय मिलने के बजाय मिल मालिकों को प्रोत्साहन मिलता है इसलिये सरकार के ऐसे काले कारनामों के खिलाफ मैं मेरी पार्टी के साथ सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री हीरा भाई द्वारा सदन से बहिर्गमन)

(याचिकाओं का उपस्थापन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य, याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कैनाल की 116 आर. डी. से खेदासरी गांव तक माइनर का काम पूरा कराने के संबंध में दो-याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूँ।

(2) उपाध्यक्ष महोदय, मैं बाइया से टी. बी. व सांगरिया को पूरा कराने के सम्बन्ध में एक याचिका देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूँ।

विधायी कार्य

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य-मन्त्री, समाज कल्याण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1970 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को 15 मई 1971 तक बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1970 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को बढ़ा दिया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो रही है। अभिभाषण की एक से 17 पैराग्रों तक, पूरी आधी किताब 11 पेजेज से भी ज्यादा जो लिखा गया है वह यह कि राहत कार्यों पर सरकार ने काफी ध्यान दिया है। पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ा है और यह सरकार धन्यवाद की पात्र है कि एक भी आदमी अकाल के कारण बाहर नहीं गया और अपने घर पर बैठे हुए सहायता दी गई।

श्री उपाध्यक्ष : बाहर जाने का बहुत सा खर्चा बताया है कि कितना आटा दिया गया, वह किसको दिया गया ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान के बाहर गये है।

श्री गोकुलप्रसाद : हमेशा जाया करते थे पुराने जमाने में और उस जमाने की हालत यह थी कि घरों पर बाल बच्चों का पता नहीं कहां निकल जाते थे और फिर कब वापस आते थे और कब अकाल खतम होता था, कितने बच्चे और पशु मर जाते थे, किस हालत में आते थे किसान जानते हैं। वे कहते हैं कि हमने ऐसा राज नहीं देखा। घर के आसपास कपड़ा नहीं रहता था, खाना नहीं रहता था, जानवर नहीं रहते थे और आज स्थिति यह है कि एक चीज की भी कमी नहीं है, और हमें बराबर खाना मिला, कपड़ा मिला, जानवर और जमीन नहीं बिकी न गिरवी रखी। इसलिए काफी राहत सरकार की

(श्री गोकुल प्रसाद)
तरफ से मिली। इससे ज्यादा धन्यवाद प्रस्ताव हो नहीं सकता। हम समझते हैं कि सरकार ने काफी काम किया है . .

श्री लाभचन्द बैद : आपको घर गृहस्थी का क्या पता ?

श्री गोकुलप्रसाद : आपको क्या पता कि अकाल क्या होता है ? उसके बाद दूसरी बातें सामने आती हैं कि इस वर्ष वर्षा बहुत अच्छी हुई और खाद्यान्न को बाहर भेजने की इजाजत दे दी गई है, यह राज्यपाल महोदय ने फरमाया है। उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न कभी भी गांव का गरीब किसान या मजदूर इतना पैदा नहीं करता कि बाहर भेज सके। जरूरत से ज्यादा जिन्होंने पैदा किया है वह बड़े बड़े किसान हैं। सीलिंग अभी लागू हुई नहीं है और इस कारण बाहर भेजने से क्या होगा। जो जरूरतमंद कामगार हैं उनका हमें खयाल नहीं। हम वास्तव में समाजवाद की नीति नहीं अपनाना चाहते है। जिनको कम मजदूरी मिलती है उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार ने एक बात कही है। ऐसी हालत में मोटा अन्न बाहर भेजने से नुकसान होगा, इसलिए फौरन इसको बन्द किया जाना चाहिए। उन किसानों को राजी करना जिनके पास बहुत अन्न पहले ही इकट्ठा है या मजदूरों के काम करवाकर इकट्ठा करवाया है, यह सही नहीं है। सरकार अपने चपरासियों को 140) वेतन देती है लेकिन दूसरी जगह किसान अपने मजदूर को दो-ढाई रुपये रोज देता है। ऐसी क्या मुश्किल हो रही थी कि बाहर भेजने की इजाजत दी। इससे उन लोगों को लाभ मिलेगा जिन्होंने हजारों मन अनाज पैदा किया है। यह तो जब तक सीलिंग लागू हो तब तक बन्द किया जाना चाहिये। नहीं तो सीलिंग लागू होने के बाद यह इजाजत दी जा सकती है। इसलिए बाहर भेजना ठीक नहीं है। गरीब कामगारों के फायदे के लिए कुछ सस्ता अनाज मिल सकता हो, बाजरी 80) के बजाय 60) मिले लेकिन गरीबों को खाने की वही तकलीफ होगी, यह ठीक नहीं है।

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़) : बाजरा 48) है।

श्री गोकुलप्रसाद : लोग कहते हैं कि अनाज सस्ता हो गया। ग्रामों को छोड़ बाहर का आदमी कहता है कि सस्ता होना चाहिए।

श्री नाथूलाल करोल : और कपड़ा।

श्री गोकुलप्रसाद : आप चिंता क्यों करते हैं ? आप अपनी पार्टी की बात करें। तो मैंने निवेदन किया कि विकास कार्य कहां-कहां हो रहे हैं। छोटे कृषकों के लाभ के लिए सरकार ने कदम उठाये। बैंकों को गारंटी देकर ऋण दिलवाये इसके लिए तो धन्यवाद लेकिन एक ही नजर से सबको देखना चाहिए। जिन किसानों के पास पशु हैं, जमीन है, काम करने के लिए रोजगार है, उनके लिए सरकार गारंटी दिलाये लेकिन वह लोग जिनके पास न जमीन है न पशु है जो सुबह से शाम तक मेहनत करके पेट भरते हैं ऐसे लोगों के लिए कोई सवाल नहीं। बैंकों के पास शहर का गरीब गया तो कहते है कि मकान का पट्टा नहीं है। अरे, मकान नहीं

(श्री गोकुल प्रसाद)

तभी तो तुम्हारे पास आया है। कहा जाता है कि क्या भरोसा है कि तुमको उधार दें ? इसलिए मैं मानता हूं कि गांवों के लोग ज्यादा चुनकर आते हैं विधान सभा में, आखिर ज्यादातर गांवों की कान्स्टीट्यूएन्सीज के लोग हैं इसलिए शहरों की अवहेलना होगी। प्रजातन्त्र है जिसके पास पावर होगा वह काम में लेगा और शहर वालों को समझना चाहिए कि हमारे पास पावर नहीं है। इसलिये हर बात पर टैक्स लगेगा। यह मानते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसी धारणा नहीं फैलानी चाहिए नहीं तो लोगों में भावना फैलेगी कि शहरों का एक गरीब दो रुपये मजदूरी करने वाला है, उसको सरकार राहत नहीं देना चाहती और गांवों में यदि किसान 25 हजार साल की साख पैदा करता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। फिर भी सरकार उसको फायदा पहुंचायेगी और शहर का हर आदमी, शहर के लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। शहर में 90 प्रतिशत लोग गरीब हैं। एक दो प्रतिशत हवेली वाले कभी भी उनका नेशनलाइजेशन कर दें सारी सम्पत्ति का कोई बुरा नहीं लगेगा। इसके बदले में सारे लोगों को क्यों मारा जाता है। इसमें एक बात कही गई··

श्री विजयसिंह : आप किसको सुना रहे हैं ? एक मन्त्री भी नहीं है आपका भाषण सुनने के लिए। केवल 10 कांग्रेस सदस्य हैं।

श्री गोकुलप्रसाद : मैं सदन को सुनाना चाहता हूं क्योंकि आप उनमें आते हैं। पूंजीवाद की बात पर आपको चिढ़ आती है।

श्री विजयसिंह : अगर पूंजीवाद मिटाना है तो पहले सुखाड़ियाजी को चेंज करना चाहिए।

श्री देवीदत्त गाडिया : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो उस समय इतने भारी भरकम मन्त्री मण्डल में से एक मन्त्री भी उपस्थित नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मन्त्रियों को आदेश दें और जब तक मन्त्री उपस्थित न हों तब तक भाषण प्रारम्भ न हो। इस तरह से मन्त्री लोग उठकर चले जाते हैं। इस सम्बंध में अध्यक्ष महोदय के आदेश पहले भी हो चुके हैं। यह सदन की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप जारी रखें, मंत्री आ जायेंगे।

श्री दौलतराम सारण : आखिर इस सदन की कार्यवाही चलाने का और माननीय सदस्यों का यहां अभिव्यक्ति करने का उद्देश्य क्या है ? सरकार की तरफ से कोई हाजिर नहीं रहे।

श्री देवीदत्त गाडिया : मन्त्रीजी सोते हुए आये हैं।

श्री गोकुलप्रसाद : उसके बाद विकास एजेंसियां बनाई गई है। यह राज्यपाल महोदय ने फरमाया। कहां कायम की गई हैं ? जहां अविकसित जिले हैं : अलवर, भरतपुर और उदयपुर। ये तीन जिले तो अविकसित हैं बाकी सारे जिलों में विकास हो चुका है। इन जगहों में विकास ऐजन्सियां हैं। विकास करने वाले अलवर से आये बैठे हैं, भरतपुर उसके पडोस में हैं

(श्री गोकुल प्रसाद)

और उदयपुर का कब्जा जरूरी है। जो अविकसित हैं, पीने के पानी बिना तरसते पशु पालन नहीं कर सकते उन जिलों की अवहेलना करके विकास एजेंसियां तीन जिलों में कायम कीं। उसके साथ बड़े पैमाने पर मार्जिनल पैमाने पर भीलवाडा और अजमेर में विकास एजेंसियां तैयार की जा रहीं है डेढ डेढ करोड की। मतलब पांच जिले हैं। दूसरे दस ऐसे जिले जिन पर सूखा पड़ा रहता है हमेशा, उन पर क्या किया जावेगा कि यदि सड़के अधूरी रह जावेंगी, अकाल राहत में काम नहीं थे तो उन सड़कों पर मिट्टी डलवायी। वहां क्या करना चाहते हैं ? राहत कार्यों में यह चाहते हैं कि लघु सिंचाई योजना। सिंचाई क्षेत्र में हो, पीने के लिये पानी। कौनसा इसमें विकास हो जावेगा ? पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में यदि कृपापूर्वक पीने का पानी उपलब्ध कर देते हैं, उसका इन्तजाम कर देते हैं, सिंचाई के लिये, तो यही विकास है क्या ? वहां तक सड़कों के लिये पैसा खर्च किया जावेगा और विकास के लिये अलवर और भरतपुर में किया जावेगा।

इसके बाद बेकारी की बात आयी। राज्यपाल महोदय ने कृपापूर्वक फरमाया कि बड़ी भारी बेकारी है। एक जिले में एक हजार आदमियों को रोजगार दिया जावेगा। यह गांवों में जो बेरोजगार है, उनको मिलेगा। शहरों में भी रह सकते हैं बेकार। आप यह कहते हैं कि एक जिले में एक हजार लोगों को रोजगार दिलायेंगे। अन्दर ही अन्दर आदेश कर देते हैं। राज्य सरकार पहले से ही कहती है लेकिन सर्वे कराओ तो पता चलेगा कि मजदूरों को न तो यहां मजदूरी है और कह देते हैं कि शहर में बड़े मालदार हैं। एम्प्लोयमैन्ट एक्सचेन्ज में नामावली ले लीजिये कि कितने लोगों ने नाम दर्ज करवाये हैं। कितने परसेन्टेज शहरों के हैं और गांवों के कितने हैं। आपको 90 प्रतिशत शहरों के लोग मिलेंगे जो बेकार है। काम धन्धा नहीं है। बी. ए. और एम. ए. करके चपरासी की जगह के लिये मिन्नते करते हैं। आप रोजगार दिलायें गांवों में, मुझे उससे खुशी है लेकिन आप शहर वालों की अवहेलना मत कीजिये। शहरों के यहां कम चुनकर लोग आते हैं और गांवों से ज्यादा आ जाते हैं।

मैं एक किस्सा बता देना चाहता हूं। उज्जैनी नगरी का राजा था और उसको शौक था मींढा पालने का। महलों के किनारे पर उसने उसको रख दिया था, आता जाता उसको देखता, सहलाता। उस राजा की एक दासी थी उसको भी मीढे से चाव होगया। वह भी आती जाती उसको सहलाती। दीपावली के दिन दासी दीपक लेकर जा रही थी और मीढे के पास गयी तो उसने मेठी मारी तो उसके दीपक नीचे गिर गये और उसके ऊपर गिरने से उसके आग लग गयी। वह मींढ़ा वहां से तुड़ाकर घास के ढेर में चला गया और उससे आग लग गई। शहरों की हमेशा अवहेलना करेंगे तो बैठेगा नहीं। गवर्नमेन्ट का कोई कागज निकलेगा तो कहेंगे कि फलां गांव। शहर के आदमी को धोखा नहीं दे सकते। शहर के आदमी को यदि खेती चाहिये तो कहते है कि खेती नहीं है तुम्हारे लिये, शहर के निवासी हो। पशुपालन करना चाहते हैं तो कहेंगे कि गांव के नहीं हो। हम क्या किसी विदेश के निवासी हैं,

(श्री गोकुल प्रसाद)

क्या इस देश के वाशिन्दे नहीं हैं ? गांव के आदमी कुछ भी धन्धा करो आप मना नहीं करेंगे। गांवों के बहुत लोग शहरों में आते हैं। बहुत बड़ा अन्तर है। उनको रोजगार करने की छूट है, धन्धा करने की छूट है। शहर के आदमी को गांव में जाना पाप हो जाता है। पढ़े लोग खेती करना चाहते हैं किन्तु वह काम भी शहर वालों के लिये नहीं है। पशुपालन ले लीजिये। तो कहते हैं कि शहर वालों को नहीं। आज हमने यह देख लिया है कि हर जिले में एक हजार आदमियों को रोजगार दिया जावेगा और शहर वालों के लिये ध्यान ही नहीं है। पूरे भाषण में कहीं नहीं है। राजस्थान की शहरी जनता के पास सिवाय नौकरी करने के और कोई साधन नहीं है। इतनी नौकरी आप दे नहीं सकते। बेकारी में लोग फंसे रहते हैं। आप यह तो देखिये कि लाखों आदमी क्या करते हैं ? कौनसा कल कारखाना शहरों में आपने खोल रखा है, प्राइवेट सेक्टर में कौनसा कारखाना खोल रखा है। कोई परवाह नहीं आपको। आप यह सोचते हैं कि शहर के पांच पचास आदमी जीत कर आ जावेंगे तो उससे क्या गांव से डेढ सौ आदमी आवेंगे। इसको हम बरदाश्त नहीं करेंगे।

इसके बाद सहकारिता पर आता हूं। इनके द्वारा आप गांवों को लाभ पहुंचाते हैं। ग्रामीण हमारे भाई हैं, उनको लाभ पहुंचाये अच्छी बात है। लेकिन सहकारिता के नाम पर गावों में कोई कार्य नहीं हो पाया है। सहकारी समितियां खोली जाती हैं। डेयरी को ही ले लीजिये। पशुपालन वगैरा के ऋण की व्यवस्था नहीं रखी है। बीकानेर में 15 हजार पशुओं की डेयरी हो सकती है। अपनी मरजी से कोई उसको चलाये। सरकार की तरह से कोई राहत नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह अमीर सरकार है।

श्री गोकुल प्रसाद : हमने आपको देख लिया है।

श्री दौलतराम सारण : इसीलिये छोड दी।

श्री गोकुल प्रसाद : आपने कुछ नहीं किया इसीलिये तो गये।

श्री दौलतराम सारण : देहात और शहर में भेद पैदा कर रहे है।

श्री गोकुल प्रसाद : आपका भाषण यह होता है कि गांव में यह होना चाहिये। एक मैं हूं जो शहर की बात करता हूं तो नाखुश होते हैं।

श्री विजयसिंह मकराना : गांधीजी कहते थे, बापू कहते थे गांव गांव।...

श्री गोकुल प्रसाद : बापू तो आपके हो गये। वे तो लीडर थे। नेता थे।

शहरों में भी लोग खाने पीने के लिये इच्छुक है। वे भी सस्ता दूध पीयें और अच्छा खायें। आप इसकी व्यवस्था नहीं करते हैं। दिल में दुख होता है। जोधपुर में आपने डेयरी खोली है। लेकिन बीकानेर शहर और दूसरे शहरों के आस पास कोई व्यवस्था नहीं करते और हम स्वयं कर रहे हैं उसमें सहयोग नहीं देना चाहते हैं।

(श्री गोकुल प्रसाद)

और एक ही काम उनका है शहरों में जन्म लिया है, मरदुमशुमारी में नाम लिखावे।

सहकारिता के बारे में निवेदन करना है। राजस्थान केनाल, कुए खुदवाने आदि के लिये कहा गया। आप गांवों में कुए खुदवाए, किसानों को फायदा करिये। पर शहरों में आप पेयजल की कहां कहां व्यवस्था कर रहे है ?

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे कौनसे शहर है जिनमें आपके अनुसार पानी की बड़ी समस्या है ? जहां जल स्रोत नजदीक नहीं है कुए बड़े गहरे हैं, इस हिसाब से बीकानेर से बड़ा कोई शहर नहीं जहां पर कुए से 300 चार सौ फीट नीचे से पानी निकालना पड़ता है। इस शहर का आपकी स्कीम में कहीं नाम नहीं है। नाम है उदयपुर का उदयपुर में पानी की बड़ी कमी है। चितौड में बहुत कमी है, जहां नदी बह रही है। जहां पांच सात फीट नीचे ही पानी है अटूट पानी के भण्डार भरे हैं, वहां तो आप इन्तजाम करें, पर बीकानेर में नहीं करेंगे जहां चार सौ फीट नीचे से पानी निकलता है।

इसके बाद आपने कहां जयपुर में पानी की कमी हो रही है लेकिन बीकानेर बहुत अच्छा शहर है, वहां पानी की कमी नहीं है। जोधपुर में पानी की कमी नहीं है ? तो आप ऐसा मत कहिये। ठीक मे जांच करिये। बीकानेर पानी के बिना प्यासे मर रहे हैं। वहां पर आपने पानी के लिये पैसा न पिछले वर्ष दिया न इस साल। कहां लगावेंगे पैसा, उदयपुर में दौसा में। दौसा पता नहीं यह बीच में कहां से आ गया। तो इनमें पैसा लगेगा जलप्रदाय योजना में करोड़ों रुपया लगेगा पर बीकानेर में नहीं लगेगा। वहां तो लोगों को पानी बहुत है, अजमेर में स्कीम लागू हो चुकी है। आप इनमें व्यवस्था करते हैं, पर बीकानेर जैसे शहरों में नहीं करते। यह आपका सौतेला व्यवहार है।

राज्यपाल ने कहा गांवों के लोगों का जीवन स्तर उठावेंगे, वहां पानी पहुचावेंगे, करिये आप, पर शहर वालों को भी नीचे मत गिराइये।

शिक्षा के मामले में। मानता हूं मैं कि जब यह राजस्थान बना था तो एक करोड़ साठ लाख रुपया खर्च होता था। आज तो चालीस करोड़ से भी ऊपर चला गया। काफी तरक्की हुई है। गावों में आपने प्रारम्भिक पाठशालाएं खोली तो ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। पर जहां पहले से ही पढ़ाई का अच्छा विस्तार था उन जगहों को भी तो आप न भूलें। बीकानेर में उस समय मैट्रिक की पढ़ाई होती थी, हाई स्कूल थे, कालेज थे जब कि बहुत कम जगहों पर थे बीकानेर राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे था। जो एक करोड़ साठ लाख रुपया खर्च होता था पहले उसमें 90 लाख अकेले बीकानेर में खर्च होता था आज राजस्थान में यूनीवर्सिटियां हैं पर बीकानेर आज भी वंचित है और जगह हाई स्कूल कालेज और यूनीवर्सिटियां तक नई खोली जावेंगी पर बीकानेर मे कुछ भी नहीं होगा। उदयपुर में कालेज और यूनीवर्सिटियों की भरमार है, जोधपुर में है, जयपुर में है। अब अगर कहीं कालेज और यूनीवर्सिटी खोलेंगे भी तो कहां खोलेंगे ? नाथद्वारा में खोलेंगे क्या।

(श्री गोकुल प्रसाद) और स्कूटर के कारखाने वहां खोल सकते हैं।

बीकानेर में मेडिकल कालेज खोला। पर हाई स्कूल और हायर सेकण्डरी स्कूल में बायोलोजी नहीं पढ़ाई गई। वहां सभी बाहर से आये। अब पढ़ाने लगे हैं चार पांच साल से। जहां कालेज थे पहले वहां तो कालेज ही रहने दिये जावें। आज लड़कियों का पोस्ट ग्रेजुएट कालेज नहीं है बीकानेर में। मांग करते हैं तो हां हां कर दी जाती है। लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक मेडिकल, वैटेरिनरी कालेज हैं, प्राइवेट और एक सरकारी कालेज है। इसके सिवाय लड़कों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। सब जगह यूनिवर्सिटियां है बड़े बड़े शहरों में तो वहां क्यों नहीं ? इस पूरे डिविजन का अपमान क्यों किया जाता है।

अभी उपाध्यक्ष महोदय, शहरों की कुछ बात आई। शहरों में फैक्टरियां खोली जावें। क्या खुलेंगी। स्कूटरों और ट्रेक्टरों की। कहां खोली जावेंगी ? वनस्पति घी की खोली गई जयपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़ में। वनस्पति घी की तो आप यहां एक नहीं दस खोलें। हमें कुछ नहीं कहना। पर जहां स्कूटर और ट्रेक्टर की बात है खुलासा नहीं है कहां खोले जावेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : जोधपुर में।

श्री गोकुलप्रसाद : मैं अर्ज कर दूं। पश्चिमी राजस्थान में हम रहते हैं। हमारे यहां जमीन की कमी नहीं है, नहरों के कारण आज पानी की भी कमी नहीं है। राजस्थान कैनाल आने वाली है। पानी की कमी नहीं रहेगी, और ट्रान्सपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा। इकोनोमिकल भी होगा कोई भी उद्योग लगाना। आप ट्रेक्टर और स्कूटर के कारखाने वहां खोल सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : जोधपुर में खोल लेंगे।

श्री गोकुलप्रसाद : आप अन्दाज लगाइये दो लाख आदमी बीकानेर शहर में रहते हैं। वहां सरकार का कौनसा कारखाना है। एक बहुत पुराना वर्कशाप रेलवे का है या एक आध छोटा मोटा कारखाना और है 156 आदमी काम करते हैं सरकारी कारखानों में, और दो चार हजार आदमी प्राइवेट वालों में काम करते हैं। हालत खराब है इस दृष्टि से वहां की। लोगों को रोजगार देना होगा। कभी आप भरतपुर में कारखाना खोलते हैं, कभी अजमेर में तो कभी गंगानगर में और उदयपुर में। कोटा में तो पता नहीं क्या हो गया है, जो आता है वह कोटा में जाता है। कोटा के पास पानी है चम्बल का अच्छी बात है। पर हम भी आपके साथ हैं। आप यों क्यों मानते हैं कि हम दूसरे प्रान्त के हैं। इस पूरे इलाके की आप उपेक्षा करते हैं, करते आये हैं। जालौर, में चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर जिलों की। इस इलाके को तो ऐसा समझ लिया गया है कि ये हमारे आश्रित है, इनको थोड़े दाना डाल दो। दस बारह रुपया महीना दे दो। ये गुजारा कर लेंगे। यह मत समझिये, हमें धन्धा दीजिए।

श्री विजयसिंह मकराणा : बीकानेर का रसगुल्ला प्रसिद्ध हैं।

श्री लाभचन्द वैद : आपको चूरू याद तो आया।

श्री गोकुलप्रसाद : मुझे तो सब याद है।

श्री लाभचन्द वेद : वहां एक बूंद पानी नहीं है सुजानगढ़ में, वहां इसका प्रबन्ध होना चाहिए।

श्री गोकुलप्रसाद : वहां करोड़पति हैं। वे प्रबन्ध कर सकते हैं।

श्री लाभचन्द वेद : वहां गरीब नहीं रहते हैं क्या ?

श्री गोकुलप्रसाद : मेरे शहर में कोई करोड़पति नहीं है।

श्री लाभचन्द वेद : गरीब भी हैं, उनकी व्यवस्था कौन करेगा ?

श्री गोकुलप्रसाद : अब अगर मैं गलत बोलता हूं, किसी जगह बोल गया हूं तो आप भी तो कुछ कहें। आप यह आशा क्यों करते हैं कि आपके इलाके के लिए भी मैं ही कहूं। आप भी कुछ बोलें, आप उनके प्रतिनिधि होकर आये है।

मैं बोलूंगा तो आप क्या कहेंगे। आप भी तो कुछ बोलो भाई। लोग सुनेंगे, कहेंगे कि लाभचन्दजी भी बोलते है बीदासर के लिये।

मैं फेक्टरी के लिए जहां बात आती है यह चाहूंगा कि रेगिस्तानी इलाका कह कर उसे छोड़ न दिया जायं। और वहां पर अकाल सहायता कार्य किया जाता है इसलिए छोड़ दिये जाये और वहां पर फेक्टरी न लगाई जाये तो यह उचित नहीं होगा। उस क्षेत्र के साथ न्याय होगा। राज्यपाल महोदय ने उसे बड़ी कृपा कर के अपने अभिभाषण में यह कहा है ...

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री गोकुलप्रसाद : मैं अपने भाषण में सारे इलाके की बात कह रहा हूं, एक ही जगह की नहीं कह रहा हूं। राज्यपाल महोदय ने बड़ी कृपा की है कि शहरों में लोगों को आवास की तकलीफ है, उनके पास अपने घर नहीं हैं इसलिए उनके लिए छोटी और अल्प आय वालों के लिए 8, मध्यम आय वालों के लिए 428 इस तरह से कुल 513 मकान बनाये जायेंगे, और कहां राजस्थान में ? और इसके लिए एक निगम कायम किया गया है, पता नहीं है क्या है यह निगम ? लेकिन यह निगम जहां पर मकान बनाने की बात करता है, उससे तो कोई आवास की समस्या पूरी तरह से हल होती नजर नहीं आती है और वह कहां पर यह मकान बनायेगा अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर और कोटा में। बीकानेर इसमें भी रह गया है। बीकानेर इसमें भी साथ नहीं है और जो मकान गरीबों को दिए जा रहे हैं उसमें बीकानेर को नहीं दे रहे हैं।

श्री नाथूलाल करोल : आपने भीमसेन जी को हरा दिया है इसलिए छोड़ दिया गया है।

श्री गोकुलप्रसाद : यह छोटी बात आपके ख्यालात को बताती है। हार जीत तो होती रहती है। अबके जो जीता है वह कल हारेगा। आप ऐसी छोटी छोटी बातों को कैसे उठा लेते हैं। काम की

(श्री गोकुल प्रसाद)

जगह काम की बात करना चाहिए। कहां हार की बात ले आये हैं। कौन हारता है और कौन जीतता है, जीतने के जो परिणाम हैं उनको तो अभी मैंने गाया ही नहीं है, वह तो मैंने कहे ही नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग के बारे में थोड़ा सा कहूंगा। सरकार समाज कल्याण के छात्रावास चलाती है उसमें तो 100/- रुपया एक लड़के पर खर्च करती है और जो ऐच्छिक संस्थाएं हैं, जो ऐच्छिक संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उनमें आप 40/50 रुपया प्रति छात्र के हिसाब से देते हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वे संस्थाएं ठीक तरह से काम कर सकती हैं। यह तय हो चुका है और आपकी प्रोसीडिंग्स में भी लिखा है कि यह रकम 60/- रुपया तक कर देंगे, वह आज तक उनको नहीं मिल रहा है और इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के अधिकारी जो छात्रावास चला रहे हैं, जो छात्रावास वे स्वयं चलाते हैं, वे तो उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं बनस्पित ऐच्छिक संस्थाओं के। वे अपने यहां के छात्रावासों में 100 रुपया प्रति छात्र खर्च करेंगे और संस्थाओं को 50 रुपया भी नहीं देंगे और कहेंगे कि संस्थाएं काम नहीं कर रही हैं। इस तरह से सार्वजनिक कार्यकर्ताओं नेताओं को बदनाम करने का एक तरीका सरकारी मशीनरी ने यह निकाल रखा है। इसमें तो समाजवाद होना चाहिए। यह छात्रावास हरिजनों और आदिवासियों के लिए हैं, व्यक्तिगत प्राईवेट संस्थाएं जो छात्रावास चलाती है और जो सरकार छात्रावास चलाती है उन दोनों में बराबरी होनी चाहिये, यहां तो समाजवाद जल्दी से आना चाहिए।

मैं भाषा के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। सिन्धी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कई भाषाएं हैं और उनको हम मान्यता देते हैं। मैं तो चाहता हूं कि द्विभाषा होनी चाहिए, यह किया जा सकता है। इसमें राजस्थानी भी एक भाषा है और जितनी संस्कृति इसमें छिपी हुई है वह हमारे पास में नहीं है। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन हमारी राजस्थानी भी भाषा है और यह क्या गुजराती, सिन्धी, उर्दू और पंजाबी के बराबर क्या हमारे यहां पर नहीं मानी जा सकती है। राजस्थानी को इनके बराबर भी नहीं माना जाय तो दुख होता है इसलिए इन भाषाओं के साथ राजस्थानी को भी जोड़ा जा सकता है। सरकार में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो यह समझते हैं जैसे कि राजस्थानी भाषा गौण है और तो और हमारे राज्यपाल महोदय पंजाबी भाषा बोलते हैं, राजस्थानी भाषा को वे जानते तक नहीं हैं, हिन्दी भी कम बोलते हैं। हमारे यहां पर राजस्थानी भाषा काफी लोकप्रिय है और यह आवश्यक है कि और दूसरी भाषाओं के बराबर तो इसको हमारे राज्य में दर्जा दिया जाये। क्या यह उर्दू, सिन्धी, पंजाबी का बराबरी नहीं कर सकती है, उनका मुकाबला भी नहीं करे अपने घर में ?

मैं अब गांवों में जिनके पास में रहने के मकान के लिए जमीन नहीं है उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उनके बारे में सरकार ने यह रियायत दी थी कि उनको मकान के लिए सरकार जमीन देगी, और

Page No 78

(श्री गोकुल प्रसाद)

कृषि भूमि पर मकान बनाने के लिए उनको छूट होगी। इसके लिए मैं राज्य की सरकार को धन्यवाद देता हूं। शहरों में जो गरीब परिवार हैं, जो यहां पर रोजी के लिए आकर बस गये हैं उनके पास में भी जमीन नहीं है और वे शहरों में झोपड़े बना कर के रहते हैं। वर्षों से यहां पर जमे हुए हैं और बार बार उनकी इन झोंपड़ियों को तोड़ा जाता है। नगर की आवास समस्याओं को मिटाने के लिए यू. आई. टी. बनाई गई है। इसके पहले नगर विकास योजना थी। अब यू. आई. टीज. काम कर रही है लेकिन इन यू. आई. टीज. ने आज कोई स्कीम नहीं बनाई है। हजारों आदमी बेघरबार बैठे हुए हैं। प्लान काट दिया है स्कीमें सरकार के पास भेज दी है यह यू. आई. टी. के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी स्कीमें सरकार पास नहीं करती है। तीन-चार चैयरमैन बदल गये हैं और दस-बारह साल का अर्सा हो गया है लेकिन कोई स्कीम पास नहीं होती है फिर लोगों को जमीनें कहां से मिलें? लोग कच्ची झोपड़ियों को बनाते हैं और सरकार के कारिन्दे उनको आकर तोड़ जाते हैं। इन पर सरकार का बस चलता है और जिन्होंने नाजायज बंगले बना कर रखे हैं उनको कोई नहीं तोड़ता है ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, ऐसी लिस्ट भी यहां पर दी गई है जो कि नाजायज बंगले बनाकर बैठ गये है। उनको तोड़ने की हिम्मत सरकार के पास में नहीं हैं। पास की झोपड़ी को आप तोड़ रहे हैं। यह आपका दिखावा ठीक नहीं है। इसलिये आप यू. आई. टी. की स्कीम को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करो और यह तय कर लीजिये कि 100/- रुपये या 135/- —136/- रुपये, क्लास फोर्थ सरवेन्ट तक के जो लोग है उनको मकान के लिये शहरों में जमीन मुफ्त में दी जायेगी। इसके लिये राज्य सरकार को शहरों के आस पास छोटी छोटी कोलोनी की स्कीमें बनानी चाहिये। अगर आप यह नहीं करेंगे तो गरीब जनता दब जायेगी। बड़ी बड़ी फैक्टरियों को आप जमीनें मुफ्त में देते हैं और जो गरीब हैं, चपरासी हैं उनको कहेंगे कि तुम आओ और नीलामी में जमीन लो तो यह उचित न्याय नहीं होगा। आप उनको जमीन देंगे ऐसी आशा करता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं अब थोड़ा सा निवेदन और करना चाहूंगा। मैं यह जो पशु पालन विभाग है उसके बारे में कहना चाहता हूं . . .

श्री विजयसिंह : आप के यहां तो कान्ता नगर बस रहा है।

एक माननीय सदस्य : क्या कोई पंडित नहीं बस रहा है।

श्री गोकुल प्रसाद : पंडित कोई माया नगर नहीं बसाते हैं। यह प्रवृत्ति तो मायावी लोगों की होती है जिनको लोग निशाचर भी कहते हैं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे यहां पर एक वेटेरनेरी कालेज हैं। वेटेरनेरी कालेज में जो लोग पढ़े हैं उनको नौकरियों नहीं मिल रही हैं। राजस्थान में उनकी कोई प्राइवेट प्रेक्टिस नहीं चल सकती है। राजस्थान के लोग इतने खुस-हाल नहीं है कि वे अपने जानवर, कुत्ते, पक्षी का इलाज प्राईवेट तौर पर करा सकें।

(श्री गोकुल प्रसाद)

इसलिये इन डाक्टरों को कोई प्राईवेट प्रेक्टिस नहीं हो सकती है। वेटरेनरी तक जब आपने अपने खर्च से पढ़ाया है तो आप उनको काम भी दें क्योंकि ये लोग बेकार में घूम रहे हैं जो जानवरों की डिस्पेन्सरी चल रही है उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है है इसलिये उनकी भी संख्या को आप बढ़ाइये और इन पशुपालन के डाक्टरों को नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी आप की है, जनता की यह हिम्मत नहीं है कि वह उनको अपने यहां पर बुला सके। इसलिये अधिकार में आप यह समझ लीजिये कि आप का यह कर्तव्य है।

मैं थोड़ासा एक और निवेदन करना चाहता हूं। बीकानेर शहर में एक मेडिकल कालेज है और मेडीकल कालेज की हालत यह है कि वहां पर 650 शैय्याऐं हैं और बीकानेर के मेडिकल कालेज में सारा स्टाफ आपका ही रहता है और वहां पर अब 1250 शैय्याए कर दी गई हैं। अब वहां पर इस तरह 600 शैय्याओं के लिये कोई स्टाफ नहीं वहां का स्टाफ घटता जा रहा है।

वहां बड़ा असन्तोष है, रोगियों में असन्तोष है। हजारों रोगी हैं वे कहते हैं हमारा काम पूरा नहीं होता है। स्टाफ कहता है हमारे पास पूरा स्टाफ नहीं है। साढ़े बारह सौ शैय्या वाले हास्पिटल में छः सौ शैय्या का स्टाफ है इससे क्या होता है 13 घन्टे काम लिया जाता है। किसी दिन का अवकाश नहीं मिलता है। बहुत असन्तोष है। मै समझता हूं स्ट्राइक हुई तो रोगी दुख पायेंगे और आप कह देंगे ऐसी जगह स्ट्राइक हुई जहां बीमार हैं तो मै कहता हूं क्या स्टाफ भी बीमार पड़ेगा? उपाध्यक्ष महोदय, उनके खाना खाने की कोई जगह नहीं है। बीकानेर में साढ़े बारह सौ शैय्या वाले हास्पिटल में स्टाफ खाना कहां खाते हैं—सड़क पर। बड़ी शर्म महसूस करते हैं अपनी अपनी रोटी लेकर बैठते है अच्छे-अच्छे लोग-बाग, बीच सड़क पर।

एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि हम अपनी सर्विसेज के मामले में कोई भेद नहीं रखते है लेकिन यहां पर पुरूष और महिलाओं में इतना फर्क है—एक ही समान पढ़े लिखे होने पर, एक ही समान सेवा होने पर एक नर्स को 150 रु. और एक कम्पाऊन्डर को 110 रु. यह महिलाओं और पुरूषों में भेद किया गया है और फिर जब पदोन्नति होगी तो महिला कर्मचारी की पहले होगी पुरूष कर्मचारी की पदोन्नति नहीं होगी। यह भेद क्यों रखा जाता है ये नर्स हैं और दूसरे कम्पाऊन्डर हैं। रोगी महिलायें भी आती है तो पुरूष रोगी भी आते है किन्तु दोनों की तनख्वाहों में इतना अन्तर है। कोई कोर्ट में चला जायगा तो सब धरा रह जायगा। महिलाओं को पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाती है—पहले महिला कर्मचारी की पदोन्नति होगी . . .

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं समाप्त करता हूं। मेरे अपने इलाके का एक मसला है, मैं निवेदन कर दूं—पुरुषों और महिलाओं की सीनियोरिटि से पदोन्नति होनी चाहिये। बिजली और नल विभाग के कर्मचारी हैं जब वे अलग अलग हुये तो जो बीकानेर हास्पिटल में

(श्री गोकुल प्रसाद)

रहे उनको आज तक मस्टर रोल पर तनख्वा दी जाती है और कोई उनकी पदोन्नति नहीं हुई और जो नल बिजली के कर्मचारी दूसरी जगह चले गये हैं उनकी तरक्कियां हो चुकी हैं। 20 वर्षों के बाद भी आज बीकानेर हास्पिटल में वे मस्टर रोल पर तनख्वा लेते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। रोज बेचारे नोटिस देते है लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है और आज भी मस्टर रोल पर हाजरी देते हैं। इसलिये मुझे ऐसा लगता है सरकार की इन नीतियों के खिलाफ कि स्टाफ को अवकाश न दे, ज्यादा घंटे तक काम ले, पदोन्नति अपनी इच्छा के अनुसार करे, पुरुषों की पदोन्नति न करें, महिलाओं को करें, 15 साल तक मस्टर रोल पर हाजिरी करते रहे—अगर बीकानेर में स्ट्राइक हो गई तो हजारों बीमारों को तकलीफ होगी और बेबस होकर उनको कोई कदम उठाना ही होगा तब फिर हम क्या करेंगे इसलिए मेरा निवेदन करना है जिस प्रकार सरकार ग्रामीण लोगों के लिये जागरुक है उसी प्रकार शहर के लोगों के लिए जागरुक रहे। जिस प्रकार ग्रामीण पूंजीपति पर सीलिंग लगाते हैं तो उसी प्रकार अरबन ऐरिया के लोगों पर भी सीलिंग लगाइये ताकि अरबन पूंजीपति हैं उनमें कमजोरी आयें। शहर के लोगों को बदनाम क्यों करते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ही समाजवाद लायेंगे तो अरबन ऐरिया में करोड़पति बैठे रहेंगे और इस तरह से आपका समाजवाद सफल नहीं होगा। दोनों पर ही सीलिंग लागू करें, शहर के लोगों को रोजगार दें। इतना ही मेरा कहना है—जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परसों से यह देखता आ रहा हूं उधर से जो माननीय सदस्य बोलते हैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देकर बोलते हैं। इधर से उनका विरोध करते हैं। मैं राज्यपाल महोदय को कुछ बातों के लिए तो धन्यवाद दूंगा और कुछ बातों के लिए उनका विरोध करूंगा। सबसे पहले तो मैं उनको इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि साल भर में कम से कम एक बार पधार कर अपनी शकल नसीब करवा देते हैं। साल भर तक करोड़ों रुपया खर्च करवाते हैं उसके लिए उनको धन्यवाद और यहां पधार कर जो ये कापी बांटते हैं तो इस किताब में कहीं भी समाजवाद के बारे में उल्लेख नहीं है। किस प्रकार का समाजवाद आयेगा क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इन्दिराजी ने जोरदार शब्दों में हिन्दुस्तान में हेलिकोप्टर द्वारा भ्रमण करके बताया समाजवाद आ रहा है तो जब हम यह आशा लेकर आये कि राज्यपाल महोदय न जाने अपने भाषण में कितना समाजवाद के बारे में कहेंगे परन्तु एक भी शब्द उनके भाषण में समाजवाद के बारे में नहीं है, उसके लिये भी धन्यवाद है कि उन्होंने जनता के सामने इस कांग्रेस की इलेक्शन जीतने की नीति को साफ तौर से बताया है। उपाध्यक्ष महोदय आकाशवाणी पहले तो हुआ करती थी सही बात पर, इमानदारी पर, सत्यता पर, किसी धर्म की वजह से परन्तु आजकल आकाशवाणी—जो रेडियो स्टेशन है वह तो हम ऐसा समझते हैं मानो हमारे कांग्रेसी नेताओं का पीपा है। जब ये चाहें तब बजा लेते हैं...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आकाशवाणी सेन्ट्रल लिस्ट में आती है। आप राज्य की बात करिये।

श्री विजय सिंह : रेडियो स्टेशन इस प्रकार बोलता है जैसे इनका पीपा बोलता है। एक बात आज मंत्री महोदय ने यह कही, फलां मंत्री महोदय ने यह कहा परन्तु विरोध पक्ष का कोई भी व्यक्ति कटु आलोचना सरकार की करे और किसी तथ्य और फैक्ट्स के आधार पर करे··

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज आपका भी नाम आयेगा।

श्री विजय सिंह : मैं इस नाम का भूखा नहीं हूं कि मेरा नाम रेडियो स्टेशन पर आये। मेरे में क्षमता होगी तो रेडियो स्टेशन तो क्या आप (कांग्रेस पक्ष की ओर इशारा करके) खुद बोलेंगे और जगह जगह नाम बोल कर कहेंगे और बड़े बड़े मंत्रियों ने मेरे क्षेत्र में आकर मेरा नाम पुकारा है इसलिये मेरे को परवाह नहीं है। परन्तु एक बात है और खास तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे हिन्दुस्तान के लिये पत्रकारिता है वह एक सफल पत्रकारिता के हिसाब से हिन्दुस्तान के सामने आनी चाहिये परन्तु दुर्भाग्य की बात है आजकल पत्रकार बन्धु भी न जाने किन कारणों से सरकार से अपना हाथ मिला कर जनता को गुमराह करते हैं। अगर किसी प्रकार के तथ्य हों तो उसको छिपाना नहीं चाहिये। अगर सरकार की ओर से किसी प्रकार की गलती हो तो उसको छिपाना नहीं चाहिये। मैं इतना ही कह सकता हूं कि वे हिन्दुस्तान की प्रगति में बाधक हो रहे हैं, वे हिन्दुस्तान के भाग्य के साथ में खिलवाड कर रहे हैं, वे हिन्दुस्तान की जनता को धोखा देते हैं। मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूं चाहे अखबार वाले कुछ भी लिखें, मैं डरता नहीं हूं। यह तो आप लोग हैं जो उनकी चापलूसी करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ इस जमाने में चापलूसी नहीं होनी चाहिये। वह तो अंग्रेजों के समय में··

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जब आप किया करते थे।

(दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजय सिंह : पहली बात तो यह है कि मैंने कभी चापलूसी नहीं की और अगर करता····

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : तो आज मिनिस्टर होता।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण में बाधा नहीं पहुंचावें।

श्री विजयसिंह : मैं किसी की चापलूसी नहीं करता। चापलूसी आप लोग करते हैं और जा-जा कर मुख्य मंत्रीजी से कहते हो कि मुझे मंत्री बना दो, मेरे एरिया में फलां मास्टर को भेज दो, मेरे एरिया से फलां एस. पी. को बदल दो। यह आप लोग ही करते हो। हम मंत्रियों के बंगलों के चक्कर नहीं लगाते। यह तो आप ही लगाते हो। अगर हमारे अन्दर दम है तो हम

(श्री विजयसिंह) एस पी. को भगा सकते हैं और जो भला आदमी है उसकी हम सराहना भी कर सकते हैं। हम क्यों चापलूसी करें ? यहां चापलूसी करने नहीं आये हैं। चापलूसियों ने हर चीज की मंहगाई बढ़ा दी है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से यह बात बताना चाहता हूं कि मैंने यह सोचा कि शायद राज्यपाल महोदय एक औद्योगिक नगर जो मकराना है उसके बारे में भी कुछ कहेंगे लेकिन उसका नामोनिशान नहीं है और केवल उदयपुर, उदयपुर और भीलवाडा, भीलवाडा क्योंकि वह मुख्य मंत्री जी का चुनाव क्षेत्र है। इसके अन्दर भी ऐसा सौतेला व्यवहार रखा जाये यह बहुत ही खराब बात है। आज हम सब जानते हैं कि जापान ने कितनी तरक्की की है और जापान ने तरक्की इसलिए की कि उनके उद्योग धन्धे पनपे और आज उनके घरों में यहां तक है कि छोटी कील से लेकर बडे से बडे औजार तक घरों में बनते हैं और वह किसी पर निर्भर नहीं करते और जो चीज बनाते हैं वह सालिड बनाते हैं और इसी से जापान देश की तरक्की हुई। एक छोटा सा देश इतनी तरक्की कर सकता है लेकिन मकराना जो कि औद्योगिक नगर है और जहां 125 से अधिक फैक्ट्रीज हैं और उसमें 25-30 फैक्ट्रीज तो छोटी छोटी हैं, वह आप जैसे बडे बडे सेठ साहूकारों की फैक्ट्रीज नहीं हैं उनको आज किसी तरह का लोन नहीं मिलता, उनको बिजली नहीं मिलती। वहां पर बिजली के लिए दो-दो और तीन-तीन हजार रुपया मांगते हैं ! पहले तो बडी मुश्किल से कोई फैक्ट्री लगती है और वह यदि बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो दो-दो हजार रुपया मांगते हैं तो आप खुद ही सोचो कि किस प्रकार से और कहां से वह देंगे, यह आपकी दुर्व्यवस्था है उसका मैं घोर विरोध करता हूं और आपने आज दिन तक उन उद्योगों के लिए पानी की समस्या को हल नहीं किया जब कि सन् 67 में आपने वादा किया था कि वहां पर 28 लाख की योजना शुरू कर दी जायेगी। आपने योजना तो सैंक्शन कर दी लेकिन वहां पर पाइप लाइन लगेगी तो कांग्रेसी नेता चिल्लाने लगेंगे कि कहीं विजय सिंह का नाम हो जायेगा। यदि इस एरिया में पानी आ जायेगा तो उस पाइप को वहीं पटक दिया। मैं अपना नाम नहीं करना चाहता। आप लोग अपना नाम करा लें लेकिन हमको पानी चाहिए, हमारी फैक्ट्रीज को चलाने के लिए पानी चाहिए, हमारे आदमियों को पिलाने के लिए पानी चाहिए और उद्योग धन्धों को पनपाने के लिए पानी चाहिए। हमें पानी की आवश्यकता है। हमें नाम की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मरते हैं नाम के लिए। मैं तो कहता हूं कि जो काम करेगा उसका नाम होगा और जो काम करेगा ही नहीं तो उसका नाम कैसे हो जायेगा। उसके बावजूद हमारे यहां पर गामशिया गांव है जिसके आसपास 23-24 गांव ऐसे हैं कि जहां का पानी पीने से लोगों के शरीर बल खा जाते हैं। किसी का हाथ बल खा जाता है, किसी का पैर बल खा जाता है और किसी की कमर बल खा जाती है। मैंने इस समस्या को कई बार दोहराया और इसके लिए भारत सरकार ने योजना भी बनाई लेकिन

(श्री विजयसिंह)

जब चुनाव होते हैं तब तो चले जाते हैं और वहां जाकर सीमेन्ट बता देंगे, पाइप बता देंगे और मंत्रीजी कहेंगे कि देखो हम तुम्हारे लिए स्कीम बना रहे हैं, हम तुम्हारे लिए यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। ठीक है यह सरकार का फर्ज है परन्तु सरकार की नींद कौन उडाता है यह देखना है। हम लोग इनको नींद उडाते हैं। हालांकि ऐसी निकम्मी सरकार को कुछ भी कहें इनके तो जू भी नहीं रेंगने वाली है और यही कारण है कि बजट सेशन में भी किसी की बात ये बैठ कर नहीं सुन सकते, हमारी समस्याओं को नहीं सुन सकते और फिर लोगों को गुमराह करते हैं और गांव गांव में जाकर भीख मांगते हैं और कहते हैं हमें वोट दो हम आपके लिए समाजवाद ला रहे हैं और विधान सभा में बैठ कर प्लानिंग करते हैं लेकिन आपको मालूम होगा कि क्या किसी भी मंत्री ने किसी समस्या को हल किया जिससे कि राजस्थान का विकास हो सके। वह मिनिस्टर या तो कारों में बैठ कर बीबियों के पास चले गये खाना खाने के लिए या फिर ऊपर टैलीफोनों पर लोगों से वार्तालाप कर रहे होंगे या कोई इस प्रकार का प्लान बना रहे होंगे कि किस तरह से पैसा खाना चाहिए। आप लोग समाजवाद की बात कर रहे हैं और राजा महाराजाओं को कहते हैं कि वह ऐसे हैं वैसे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं और सदन के सामने कहना चाहता हूं कि आप तो समाजवाद की बात कर रहे हो मैं आपको चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि हमारे बाप दादाओं ने तो राज्य किया और हजार वर्ष राज्य किया और हमारी सोलह पीढियों ने राज्य किया मैं अपनी सारी प्रापर्टी मुख्य मन्त्रीजी की प्रापर्टी से चेन्ज करने के लिए तैयार हूं। अगर हिम्मत हो तो मुख्य मंत्री जी मेरी प्रापर्टी को अपने नाम रजिस्ट्री करालें और अपनी प्रापर्टी की मेरे नाम रजिस्ट्री करा दें, तब आपको मालूम हो जायेगा।...

श्री उपाध्यक्ष : चीफ मिनिस्ट्री भी प्रोपर्टी मानते हैं या नहीं। आप एक्स-चेन्ज की बात कर रहे हैं तो चीफ मिनि-स्ट्री भी प्रापर्टी में मानते हैं क्या ?

श्री विजयसिंह : मैं इसकी बात नहीं करता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : राजाओं की चाप-लूसी करते थे।

श्री विजयसिंह : आपके पिता जी श्री दामोदरलाल जी करते हैं मुख्य मंत्री की और कहते हैं कि मेरे से गृह मंत्रित्व मत छीनो। लोगों के डंडे पड़ गए, गोलियां चल गयीं, राज्य में ला एण्ड आर्डर नहीं है और अव्यवस्था हो रही है और गुलामी करते हैं मुख्य मंत्री की कि मुझसे गृह मंत्रित्व नहीं छीनना। सन् 62 में दामो-दर जी हार गए तो रातों को चौंकते थे और कहते है कहां है बंगला, कहां है कार कहां है मेरे सिपाही..

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप व्यक्तिगत हैसियत से बात कीजिए। आप मेरे लिए बात कीजिए।

श्री विजयसिंह : आप जागीरदारों के लिए कहते हैं। यह क्या बात है कि

(श्री विजयसिंह)
दामोदरजी का बेटा एम. एल. ए. बनेगा और बेटे का बेटा एम.एल.ए. बनेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : यह तो जनता के हाथ में है। जनता वोट देती है। आपने बहुत भूठे ख्वाब दिलाये इसलिए जनता ने आपको साफ कर दिया।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ : दामोदरजी का हवाला मत दो। आप तो अपनी बात कहो।

श्री विजयसिंह : आप क्या बात कर रहे हैं ?

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य।

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह : आप तो दलबदलू हैं। दो दो बार दल बदलकर मेरे सामने बोलते हैं।

श्री **जगन्नाथ :** हम दलबदलू नहीं हैं। हम तो सी. आई. डी. करने आये थे और तुम्हारे राज्य को हमने खतम किया और तुम्हारा राज्य नहीं बनने दिया।

श्री विजयसिंह : आपने बहुत अच्छा किया। आपने अपने घर का फायदा कर लिया।

श्री जगन्नाथ : आप साबित कर दें मैंने एक पैसा भी लिया हो तो।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री विजयसिंह।

श्री **विजयसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो आज 23 गांवों में पीने के पानी की समस्या है वह खत्म होनी चाहिए। इसके बारे में हर पार्टी का व्यक्ति कहता है, और जनता का भला चाहने वाले मंत्रियों से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप जनता का भला चाहते हों, अगर आप जनता के बारे में चिन्तित हों तो आप ऐसे गांवों की समस्याओं को सबसे पहले लीजिये जहां कि इस प्रकार से पीने के पानी की समस्या हो, वहां के पानी को पीने से लोगों का शरीर खत जाय और लोगों के शरीर में छोटी उम्र से ही इस प्रकार का नुक्स बैठ जाय कि आगे जाकर किसी प्रकार का काम-धन्धा नहीं कर सकें। एक गांव है जहां पर एक छोटा सा उद्योग भी है और वह उद्योग है जूतियां बनाने का। वहां के जूती बनाने वाले जो लोग हैं वे इतने कुशल हैं कि कुछ न पूछिये, लेकिन वे लोग मारे मारे फिरते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, लेकिन उनको लोन नहीं मिलता है। बैंकों के अन्दर जाते हैं वहां पर कई प्रकार की समस्याएं रखते हैं उनके सामने और उन समस्याओं के कारण उनको घर लौटना पड़ता है। हर प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। इन्दिराजी ने बैंको का राष्ट्रीयकरण करके सारी दुनियां को एक थोथा नारा देकर लोगों को यह बताया कि न जाने हिन्दुस्तान

(श्री विजयसिंह)

में क्या कर देगी, पर हुआ क्या ? गरीब लोग आज तक बैंकों के चक्कर लगाते फिरते हैं उनको लोन नहीं मिलता है, लेकिन मिनिस्टर के भाई-भतीजों को मिल जाता है, मिनिस्टर के गुर्गों को लोन मिल जाता है, जो चापलूस हैं उनको लोन मिल जाते हैं। वास्तव में जिन लोगों को जरूरत है, जो धन्धा करने वाले हैं जो खेती करने वाले हैं, जो व्यापार करने वाले हैं, उनको लोन नहीं मिलता है। जो राजस्थान का विकास कर सकते हैं ऐसे लोगों को लोन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है इसकी जांच आप लोगों को करना चाहिए कि किन किन बैंकों में कितने कितने व्यक्तियों की अर्जियां पडी हैं जिनको लोन दिलाया है। वास्तविकता क्या है ? उन लोगों को आप लोन दिलायेंगे तो राजस्थान का कल्याण होगा।

मैं एक बात और बताना चाहता हूं। सीमा-सुरक्षा के हिसाब से मैं इतनी बात नहीं कह सकूंगा कि जिससे बहुत असर पड़े, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान की सीमाएं पूर्णत: सुरक्षित नहीं हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर राजस्थान सरकार यह चाहती है कि हमारी सीमा में किसी प्रकार के राष्ट्र विरोधी तत्व पाकिस्तान से न आए तो सीमा-सुरक्षा के बारे में ध्यान देना पड़ेगा और सीमा-सुरक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। सीमा-सुरक्षा के अन्दर किसी प्रकार की नेतागिरी नहीं चलेगी। आप लोग सीमा-सुरक्षा के अन्दर अपना हस्तक्षेप करते हैं, लोगों को दबाते हैं और लोगों के ऊपर इस प्रकार का दबाव लाते हैं कि वे कुछ नहीं कर पाते हैं। जहां हमारे देश का सवाल है, जहां हमारी सुरक्षा का सवाल है वहां आप लोगों को इस प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपका हस्तक्षेप तो एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर भी नहीं होना चाहिए।

(2.43 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रमोशन और पोस्टिंग मिनिस्टरों के हाथों में से हटा लिया जाय तो मैं आप से कह देना चाहता हूं कि 90 परसेन्ट भ्रष्टाचार कम हो जायगा। इसके अन्दर लोग-बाग लाइन में खड़े रहते हैं कांग्रेसी एम. एल. एज. के बंगलों पर और कहते हैं कि हमें यहां से वहां ट्रांसफर करवा दो, पोस्टिंग करवा दो, उस पोस्ट से इस पोस्ट पर प्रमोशन करवा दो। भूले भटके लोग हम लोगों के पास भी आते हैं कि यह हमारे हाथ की बात नहीं हैं और न हम लोग इस प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहते हैं। जिसका जिस हिसाब से होगा, होगा। परन्तु वे क्या करें मजबूर हैं। रिश्वत का बाजार गर्म है। गरीब आदमी कहीं जाकर खड़ा होता है तो उसकी सुविधा नहीं होती है, क्योंकि उसके पास रिश्वत देने को पैसा नहीं होता है।

मैं एक बात और आप से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर क्या सिक्योरिटी है ? कहां पर ला एण्ड आर्डर मैन्टेन हो रहा है ? छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर लोगों पर गोलियां चलाते

(श्री विजयसिंह)

हैं। आप सांगरिया और भादरा का केस ले लीजिए। गोलियां जयपुर में चलाई गईं और पब्लिक पर जुर्म रखना चाहते हैं कि पब्लिक ने इस प्रकार का आतंक फैलाया, पब्लिक ने इस प्रकार किया, हजारों सिपाही ट्रकों में भर-भरकर पब्लिक पर दौड़ाते हैं और जनता का जो आज जन-जीवन है उसमें बाधा फैलाते हैं और फिर लाठी और गोलियां बरसाते हैं। उसके बाद में कमीशन बिठाते हैं। उसमें क्या होता है कि अपने वकीलों को लाखों रुपये देना चाहते हैं। कमीशन के मारफत आप लोगों पर भार बनाकर किसी प्रकार से किन्हीं व्यक्तियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। वकीलों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं कमीशन के मारफत...

श्री मोहनलाल मोदी : अजमेर में उन्हीं को आपने अपना प्रतिनिधि बनाया था।

श्री विजयसिंह : अजमेर के किसी व्यक्ति को आपने दिये, मैं इस बात को अच्छी बात नहीं मानता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : उनको सपोर्ट क्यों दिया अगर अच्छा आदमी नहीं मानते हैं तो ?

श्री विजयसिंह : न सपोर्ट करने के लिए आया हूं और न विरोध करने के लिए आया हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सपोर्ट हम नहीं करते हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : दल बदल कर आप में बैठे हैं।

श्री विजयसिंह : आप लोग उनको फायदा देने के लिए यह करते हैं। कांग्रेस का एम. एल. ए. कोई हार गया तो उसका क्या करते हैं कि अलग अलग महकमों में उनको खपाते हैं। किसी को रोडवेज का चैयरमैन बनाते हैं, किसी को खादी बोर्ड का और किसी को होटल सम्हलाया जाता है। आप उनको राजनैतिक लाभ देना चाहते हैं। यह समाजवाद का आपका तरीका है, ढंग है। आप लोगों को गुमराह करते हैं। आप थोथे नारे देकर पब्लिक को गुमराह करते हैं। जनता जो निर्णय देगी उसको मानना पड़ेगा। आप लोग नहीं मानते हैं। राजस्थान में 23 में से 14 सीट कांग्रेस को मिली तो हमें खुशी है। कोई बात नहीं जनता का निर्णय है, लेकिन जनता के निर्णय को 67 में आपने नहीं माना जबकि कांग्रेस के 95 एम. एल. एज. थे। आप में सबसे पहले जाकर मिल गये माननीय हरिसिंहजी बेगू जो कि मंत्री मंडल में बैठे हुए हैं। उनको आपने अजमेर के अन्दर रैवेन्यू बोर्ड में उनका एक केस अटका हुआ था उसमें 80-85 हजार का आपने लाभ दिलवाया है। उनकी जागीर का केस था। आप जागीरदारों के खिलाफ बोलते हैं और जागीरदार को 80-95 हजार रुपया देते हैं। आपके एक जागीरदार माधोसिंहजी मेरे पास आये थे, आपके मुख्य मंत्रीजी के चमचे ही नहीं बहुत बड़े चमचे माधोसिंहजी मेरे पास आये थे और कहा था कि मुख्य मंत्री जी से हाथ मिला लो तो आपको जमीन दिला देंगे, लेकिन मैंने ठोकर मारी है जमीन को। जब इतनी बड़ी जागीर के ही ठोकर मारी है तो इतनी जमीन से क्या फर्क पड़ता है। मुख्य मंत्रीजी से किस बात

(श्री विजयसिंह) ... के लिए हाथ मिलाना। मुख्य मंत्रीजी से तो केवल एक बात के लिए हाथ मिला सकते हैं कि वे राजस्थान को खुशहाली दें और राजस्थान की जनता के मन में शान्ति हो तो मैं उनके साथ हाथ मिला सकता हूँ। राजस्थान पर 36 मिनिस्टरों का भार डालकर अपने पद को कायम रखना चाहते हैं उनसे हाथ नहीं मिला सकता हूं ...

एक माननीय सदस्य : इन चुनावों में जनता ने ठोकर मारी है।

श्री विजयसिंह : वोट लेने के लिए क्रिश्चियन बन गये। क्यों पोल खुलवाते हैं अपनी।

एक खास बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ वह यह बात है कि पेपर्स में सरकार की तरफ से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। यदि आप सारे पेपर्स को एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो सारे पेपर्स को बराबर देना चाहिए ताकि पेपर्स में इस प्रकार की भावना न हो कि हमें सरकार एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी अगर सरकार के खिलाफ लिखेंगे तो।

श्री दौलतराम सारण : एडवटाईजमेंट फोटो छापने वालों को दें या गाली निकालने वालों को ?

श्री विजयसिंह : आप जो फर्मा रहे हैं वह सही है। आपके जैसा त्याग ये नहीं कर सकते हैं। ये मिनिस्टर की कुर्सी पर चिपके हुए नहीं बैठे रहे, परन्तु आपने क्या किया आप लोग तो कुर्सी से चिपकना चाहते हैं और चिपकना भी सिर्फ थूंक लगाकर। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एडवर्टाइजमेंट देने का जो तरीका है वह समान रूप से देना चाहिये। गलत परम्परा नहीं डालनी चाहिए। यह तो उनको अपनी ओर झुकाने की परम्परा है। जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने फैमिली प्लानिंग में लाखों रुपये खर्च किये हैं। लेकिन हम इलेक्शन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वोटर्स बढ गये हैं। आप का फैमिली प्लानिंग है तो यह कहां से बढ़ गये हैं। एक और बात भी है ? जो विरोधी पक्ष को वोट देने वालों के नाम थे, वोटरलिस्ट में उनके नाम पर लाल स्याही फेर दी गई है। लोग वोट देने के लिये गये तो उनको यह मिला। कहा अच्छा वोट दंने गये। नागौर के अन्दर आप के कर्णधार श्री नाथूराम जी मिर्धा जो आपके प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वह वहां गुण्डागर्दी का नंगा नाच करा रहे थे। पांच पांच सौ आदमियों की टोली एक एक गांव पर चढ़ा दी। एक श्री भागीरथसिंह चौधरी, जिन्होंने फार्म भर दिया था, उनको जीप समेत गायब करा दिया। उनका आज तक पता नहीं है। उसकी कोई सुनवाई नहीं है। कौन करे ? सुनने वाले आप, फैसला करने वाले आप ? सब कुछ करने वाले आप। फिर किसको कहें। कई गांवों में ऐसा हुआ। मेडता के पास एक स्थान है। वहां स्वतन्त्र पार्टी के एक वोटर को ताले में बन्द कर दिया। यही जनतन्त्र है ?

श्री मोहनलाल मोदी : आप को यह क्या पहचान है कि वह स्वतन्त्र पार्टी का वोटर है ?

श्री विजयसिंह : हमें तो आप की भी पहचान है।

श्री मोहनलाल मोदी : इसमें तो धोखा खा गये हो।

श्री विजयसिंह : लोगों को चलाते हैं कि हम सेठों के साथ नहीं हैं। वह बात मैं बाद में बताने वाला हूँ। तो सभापति महोदय मैं बताना चाहता हूं कि वहां स्वतन्त्र पार्टी के लोगों को नंगा करके पीटा गया। उनके कपडों में आग लगा दी गई और उनको लेजाकर 30 मील पर छोडा गया। जैसा कि रैलवे में होता है जो जेब कट होता है वह कहता है, सावधान हो जाओ जेबकट आ गये हैं। तो लोग अपनी जेबों को संभालने लगते हैं। उसे लोगों की जेबों का पता लग जाता है।

श्री मोहनलाल मोदी : यह भी अनुभव है क्या ?

श्री देवीदत गाडिया : यह आप के ही तो हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या यह नहीं जानते हैं कैसे जेब काटते हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह तो चोर की दाढ़ी में तिनका है कोई बात नहीं है।

श्री विजयसिंह : इसी प्रकार हमारे कांग्रेस के नेता कहते हैं, सेठ साहूकारों से सावधान। 20 साल हो गये हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : पूंजीवाद का सही सफाया हो गया है।

श्री विजयसिंह : 10 दफा हो उनका सफाया। पूंजीवाद का सही सफाया तो उस रोज होगा जिस रोज आप लोगों के मंत्रियों की सम्पत्ति लेकर पब्लिक भागेगी।

श्री मोहनलाल मोदी : आपने भी बनाया है।

श्री विजयसिंह : मैंने तो अपने को पीढ़ियों से बनाया है।

श्री मोहनलाल मोदी : उसी की नकल करने के लिये यह चुनाव चिन्ह लिया है क्या ?

श्री विजयसिंह : इस तरह से लोगों को गुमराह करते हो। सेठ कौन हैं ? साहू जैन जिसकी सीमेंट फैक्ट्री है। उसके मजदूरों ने हडताल की तो उसको दबाने के लिए गुमानसिंह एस. पी. को भेजा। पुलिस लोगों को बाहर से गाडियों में काम करवाने के लिए ले गयी। आप सेठ साहूकारों के साथ हैं। सेठों को प्रोत्साहन देने के लिए आप हैं मजदूरों को मरवाया है।

श्री दौलतराम सारण : यही कहते हैं।

श्री विजयसिंह : कोई बात नहीं है। प्रजातन्त्र में दोनों का ही हक है। सेठों को भी हक है राजा महाराजाओं को भी हक है। कुछ नए राजा महाराजा हो गये हैं। 20 साल तक रुपया कमाया है। यह राजा महाराजा से कम नहीं हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं शीघ्र ही बन्द करता हूं।

श्री दौलतराम सारण : इनको तो जहां दूध दिखता है, वहीं जाते हैं।

श्री विजयसिंह : महाराज सुमेरसिंह जी की जो अकस्मात मृत्यु हुई ....

एक माननीय सदस्य : अकस्मात ?

श्री विजयसिंह : हां, जो अकस्मात मृत्यु हुई, उस मृत्यु के अन्दर क्या रहस्य था क्या राज था ? वह राज था गोली । इसका मतलब मृत्यु नहीं हुया । और गोली किधर से ? यह तो टाइम बतायेगा । समय बतायेगा ।

श्री मोहनलाल मोदी : यह बहस हो गई है ।

श्री विजयसिंह : उन्होंने अखबारों के अन्दर प्रचार करवाया । वोट लेने के लिए उनको समाप्त किया गया । इसलिए कि उनके क्षेत्र में उनका प्रभाव था । जब कि 15 हजार से जीते । उसी क्षेत्र में से 4 हजार से हमारा आदमी जीता ।

श्री मोहनलाल मोदी : (अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : इसका मतलब यही है ....

श्री मोहनलाल मोदी : आपने काम तो किया नहीं है । जनता चाहती नहीं है ।

श्री विजयसिंह : जनता चाहती नहीं है तो आप धोली टोपी लगाकर मदनगंज की चौपड़ पर बोलो तो पता चल जायगा कि जनता आप को चाहती है । अखबारों में यह भी बताया गया है कि उन्होंने अपनी जमीन किसी के लिए बताई है । कुआ किसी के लिए बताया है यह सारी बातें झूठ थीं उन्होंने किसी को कुआ नहीं बताया । किसी को जमीन नहीं बताई । यह प्रोपागण्डा किया गया । मैं एक और बात सभापति महोदय बताना चाहता हूं । अखबार वालों से उनका कोई झगड़ा नहीं था । इस प्रकार करने के लिए उनको कहा गया । उनको लालच दिया गया । इसीलिए उन्होंने इस बात को छापा । और इस बात के लिये मैंने अभी कुछ रोज के पहले चौपड़ पर जो मीटिंग हुई उसमें पौन घण्टे इस रहस्यमयी हत्या के बारे में बातें कहीं, लेकिन एक लाइन भी अखबार वालों ने नहीं दी । यह षड़यंत्र नहीं था कि जो राज्य सरकार बात कहती है वह अखबार वाले छापते हैं और हम जो बात कहते हैं, हमने जो कहा उसकी एक लाइन भी नहीं छापी ? क्या यह नहीं कह सकते कि यह षड़यंत्र है । इससे साफ है कि अखबार वालों को दबाया जाता है कि विरोधी दल वाले जो कुछ कहें उसको नहीं छापना चाहिये । इस सम्बन्ध में हम जो विधान सभा में बोले, जो फैक्ट दिये, वह भी कुछ अखबार वालों ने तो दिये और कुछ ने नहीं दिये ..

श्री मोहन लाल मोदी : अखबार वालों को कह दिया जायगा ।

श्री विजय सिंह : मैं यह राजनीति साबित करने के लिए कह रहा हूं ।

श्री मोहन लाल मोदी : साबित करो, आपका नाम जरूर आयेगा ।

श्री विजय सिंह : तो क्या यह साजिश नहीं थी । नाम जरूर आता है ।

तो हत्या उन व्यक्तियों की की जाती है जो कांग्रेस का विरोध करते हैं । यह मैं दावे के साथ में कह सकता हूं । शीशराम जी पूनियां, 29 तारीख को हमारे साथ थे और वह कांग्रेस सरकार को पलटने में

(श्री विजयसिंह)

शामिल थे। बाद में उनको दबाया गया और क्योंकि वह कांग्रेस के विरोध में थे इसलिए उनकी हत्या की गई, उन्हें इस बात के लिए दबाने के लिए कि यह कांग्रेस में से जाकर विरोध में न बैठ जांय। झालावाड़ के नरेश थे, उन्होंने चुनाव में कांग्रेस को पछाड़ा था। उस वक्त के लिए मैं कह नहीं सकता लेकिन उनकी भी रहस्यमय हत्या हुई। विजय सिंह जी रावत हमारे दल के थे, जिन्होंने इस सरकार के नाकों में दम कर दिया था, उनका पता नहीं किस तरह से एक्सिडेंट हुआ। उनके पीछे कोई बोलने वाला नहीं था इसलिए असली राज को छिपा लिया और कह दिया कि एक्सिडेंट हुआ और उसको सबने मान लिया और कह दिया कि एक्सिडेंट हो गया। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वह जीप टकराई नहीं थी फिर जो लोग उसमें थे, उन सबके सिर में कैसे चोट आई और कैसे खत्म हो गये। इसका मतलब है कि जो भी विरोध करे उसको षड्यंत्र करके मार दें। आप राजनैतिक कारणों से लोगों को मारना चाह रहे हैं तो आप चैलेंज करके आयें। जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर आप देखिये कि कितने सामने आते हैं। परन्तु इस प्रकार आप लोगों को गुमराह करके दूसरे लोगों को कहते हैं कि गाली मत निकालना और खुद छुरा और लाठी लेकर पहुंचते हैं। इस प्रकार मैंने यह दिखाया है कि किस प्रकार राजनैतिक हत्या होती है।

अब मैं ज्यादा न कहते हुए···

कई माननीय सदस्य : सभापति महोदय...

श्री विजय सिंह : कहां है सभापति महोदय, मुझे खत्म करने दीजिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सतर्क रहे। वह सारी बातों को सुलझाने के लिये वचनबद्ध है, कर्मबद्ध है इसलिए सरकार जनता का सहयोग ले करके पूरी कार्यवाही करे। इस बात से किसी को ऐतराज नहीं होगा।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर जितनी बातें कही हैं, यदि पुराने समाचार पत्रों को उठा कर देखा जाय, तो सभी समाचार पत्रों में राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो आंकड़े दिये हैं, वह सब के सब उनमें दिखाई देंगे। मुझे ऐसा दिखाई देता है, राज्य सरकार ने सभी समाचार पत्रों की कटिंग काट कर उनके द्वारा आंकड़ों का मायाजाल अभिभाषण में दिया है। इसके अन्दर मुझे कोई नवीनता दिखाई नहीं देती।

मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि राज्यपाल महोदय ने चुनाव के कुछ माह पूर्व दिल्ली के अन्दर हुए राज्यपाल सम्मेलन के अन्दर राजस्थान के सीमावर्ती इलाका होने के नाते जो चिन्ता प्रकट की थी, कि पाकिस्तान किसी भी समय राजस्थान पर आक्रमण कर सकता है, पाकिस्तान के जासूस, पाकिस्तान के लोग आये दिन जो राजस्थान की सीमा के अन्दर घुसपैठ करते जा रहे हैं—इस विषय में राजस्थान के राज्यपाल महोदय अपने

Page No 91

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

भाषण के अन्दर प्रेस कांफ्रेन्स के अन्दर दिल्ली में चिन्ता प्रकट की थी लेकिन बड़ा अफसोस है, उन्हीं राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा। इससे मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान के अन्दर चाहे पाकिस्तान किसी भी समय आक्रमण कर दे, पाकिस्तान के हवाई जहाज अपने राजस्थान के सीमावर्ती इलाके, जैसलमेर के अन्दर हवाई अड्डे तक हवाई उड़ान करते रहें—उस सबकी चिन्ता राजस्थान सरकार को नहीं है। पाकिस्तान के सी. आई. डी., पाकिस्तान के तस्कर आये दिन घुसपैठ करके तस्करी करते हैं, पाकिस्तानी सैनिक दूसरे भेष के अन्दर हमारे सीमावर्ती गांवों में आकर हमारे मवेशियों को उठा कर ले जाते हैं और आदमियों को मार कर चले जाते हैं, और आये दिन इस प्रकार की हरकतें करते रहे हैं, तस्करी हर तरह की करते रहे हैं, वह हमारे हवाई अड्डे के नक्शे ले जायं, हमारे यहां के नक्शे ले जायं लेकिन राजस्थान की सरकार को उस सबकी चिन्ता नहीं है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय ने स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, अन्य अन्य ऐसी ऐसी बातों को कहा है, जिनके बारे में राजस्थान की जनता पहले से ही परिचित है। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर एक वह बात नहीं कही है जो बहुत ही अनिवार्य थी। हमारे राजस्थान के अन्दर देवली केम्प में बंगाल से आये विस्थापित हैं, जिनकी संख्या एक दो नहीं है, जिनकी संख्या सौ–दो सौ नहीं है, देवली कैम्प में साढ़े चार हजार बंगाली विस्थापित रहते हैं—उनके बारे में राज्य सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये, उनको बसाये जाने के लिये क्या निर्णय लिया है—इस बारे में इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। मुझे बड़ा दुःख है, इस सरकार की बुद्धि के ऊपर, राजस्थान के राज्यपाल महोदय का अभिभाषण देखकर बड़ा दुःख होता है कि जिन गम्भीर समस्याओं की ओर राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहिये था, उनको ओझल किया है। इसका क्या कारण है? राजस्थान सरकार आज तक यह बता नहीं पाई है कि साढ़े चार हजार बंगाली विस्थापितों को, जो देवली केम्प में हैं, कब तक बसा दिया जायेगा? किस स्थान पर बसाया जायगा? क्या रोजगार दिलाया जायगा? कितने बंगाली विस्थापित मर गये हैं? मेरा निवेदन है कि सैकड़ों की संख्या में बच्चे और औरतें भूख के कारण कड़कड़ाती सर्दी के कारण मर गये हैं लेकिन इसकी राजस्थान सरकार को चिन्ता नहीं है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जीवन पर्यन्त क्या यह इसी तरह से पड़े रहेंगे? यदि किसी व्यक्ति को इस प्रकार से निष्क्रिय किया जाय तो वह जीवन को कभी उज्ज्वलित नहीं कर सकता है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जहां यह कहा है कि राजस्थान की पुलिस ने इतने डाकू मारे और इतने डाकू पकड़े, उन्होंने डेढ सौ की संख्या दिखाकर बताया है, उसमें जिन

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

डाकुओं को मारना बताया है, मैं राजस्थान सरकार को और माननीय गृह मंत्री जी को चुनौती देता हूं यदि उनमें हिम्मत है तो वह आज सदन के समक्ष यह आश्वासन दें कि मैं इस प्रकार जो बात आपके माध्यम से इस सदन को कहना चाहता हूं उसकी वह निष्पक्षता से जांच करेंगे, तो यह डाकू मारे गये हैं, उनमें से अधिकांश व्यक्ति डाकू नहीं थे, वह सहरिये, शाहबाद के इलाके में रहने वाले गरीब थे, उनको मारा है और उनको डाकू बताया है, उनमें से ही 102 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। मैं गृह मंत्री जी को चेलेंज देता हूं, जो डाकू के रूप में आप दिखा रहे हैं वह डाकू नहीं हैं, वह गरीब व्यक्ति हैं। मैं जेल का निरिक्षण करने के लिये गया था, तो मुझे पता लगा। जिन व्यक्तियों को डाकू बताया गया था, उनसे मैंने पूछा, तो मालूम हुआ कि वह गरीब सहरिये हैं। केवल आंकड़े इकट्ठे करने के लिए यह गृह मंत्री जी ने षडयंत्र रचा है। इतना ही नहीं, कस्वा थाना के बारे में कहा गया है कि दो डाकू मारे गये। मैं गृह मंत्री जी को आज चुनौती देता हूं, उनमें यदि हिम्मत हो तो वह इस चुनौती को स्वीकार करें। इन जो दो डाकुओं को मारा है, इन्हें कोटा के डी. आई. जी. गुमान सिंह भाटी, एस. पी. ने, या थानेदार ने नहीं मारा है। वह मारने वाला दूसरा व्यक्ति है, जिसका मैं नाम बताता हूं, वह हिम्मतसिंह है जो इस इलाके का है। उस व्यक्ति ने इन दो डाकुओं को मारा और मार कर थानेदार को सूचना दी। थानेदार ने इसका लाभ लूटने के लिए डी. आई. जी और एस. पी. को कहा। एस. पी. वहां पर गये और जाकर जबर्दस्ती झूंठी गोलियां चला कर उन्होंने कहा कि हमने डाकुओं को मारा है। अगर गृह मंत्री जी में हिम्मत है, तो वह जांच कमेटी नियुक्त करें। वह हिम्मतसिंह जिन्दा है और वह यह कहने के लिए तैयार है कि मैंने डाकुओं को मारा है। इस इलाके का चप्पा चप्पा और हर व्यक्ति इस बात को जानता है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह नहीं बताया कि मुख्य मंत्री ने 14 फरवरी के आस पास राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम राहत के लिए..

श्री **प्रेमसिंह सिंघवी** : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। कोरम नहीं है।

श्री **दौलतराम सारण** : कुर्सी सो रही है।

श्री **फतहसिंह** : कोरम उधर नहीं है, इधर है।

श्री **बालसिंह सोढा** : छुट्टी पर गये हैं इन्दिरा जी को बधाई देने।

श्री **सभापति** : कोरम है।

श्री **देवीदत्त गाड़िया** : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 24 फरवरी के आस पास माननीय मुख्य मंत्री जी का जब राज्य कर्मचारियों ने हड़ताल करने की धमकी दी उस समय चुनाव निकट था इसलिए उन्होंने राज्य कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने की घोषणा की थी।

Page No 93

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में अन्तरिम राहत के बारे में क्यों नहीं कहा है ? क्या राज्य सरकार ने अन्तरिम राहत देने का निर्णय किया था या नहीं ? क्या मुख्य मंत्री जी ने राज्य कर्मचारियों को आश्वासन दिया था या नहीं ? लेकिन सरकार इस ओर सजग नहीं है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया, 1 फरवरी, 69 से उनको राहत दी जायगी। जब उनको राहत देने का निर्णय किया था तो यह राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में क्यों नहीं कहा ? क्या यह महत्वपूर्ण चीज नहीं है ? यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन राज्यपाल महोदय का और सरकार का इस ओर ध्यान नहीं था...

श्री रामचन्द्र आर्य : पाइन्ट आफ आर्डर ! कोरम नहीं है, सदन के अन्दर कोरम नहीं है, सभापति महोदय, क्या आप सो रहे हैं ?

(गणाभाव सूचक घण्टी)

यह है हालत समाजवाद की ! देखते हैं, ये किस तरह से समाजवाद लाते हैं ? धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस हो रही है, उसे सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुहाई दे रही है समाजवाद की और इन्दिरा के नाम पर जीतना चाहते हैं। यह हालत है इनकी।

(गणपूर्ति के पश्चात्

श्री सभापति : जारी रखिये !

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर सरकार की असफलता को प्रत्यक्ष रूप में नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है कि यदि राजस्थान के अन्दर अच्छी वर्षा नहीं होती तो राजस्थान की सरकार अन्न की समस्या को हल करने में असफल रहती। राजस्थान सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है कि यदि राजस्थान के अन्दर वर्षा अच्छी नहीं होती है तो अन्न उत्पादन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने आज तक चाहे वह ट्यूब वैल के द्वारा हो, चाहे नहर के द्वारा हो, चाहे छोटे तालावों के द्वारा हो—ऐसी व्यवस्था नहीं की है कि किसी वर्ष वर्षा अच्छी नहीं होती है तो राजस्थान के अन्दर अन्न उत्पादन की स्थिति ठीक रहेगी। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर यह कहा है कि ईश्वर की कृपा से इस वर्ष वर्षा अच्छी हुई है इसलिए अन्न उत्पादन ठीक हुआ है। यह प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार की असफलता का द्योतक है जिसे राज्यपाल महोदय ने स्वीकार किया है।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान सरकार किस प्रकार

(3.15 म. प.)

(श्री विजयसिंह सभापति, पदासीन)

से अपव्यय करने जा रही है, इस सम्बन्ध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव इस सदन के अन्दर विधान सभा के अध्यक्ष महोदय को दिया है, वह स्थगन प्रस्ताव जिस समय आयेगा उस समय उसके ऊपर मैं बहस में

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

भाग लूंगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार को कि राजस्थान के अन्दर जो राज्य बीमा विभाग है, जिसका बहुत बड़ा कार्यालय है, वह कार्यालय सरकारी है और उसके अन्दर छः सौ पचास कर्मचारी कार्य करते हैं। मेरी सूचना है, मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान की सरकार ने एक षडयन्त्र रचा है राजस्थान की राजधानी जयपुर की महत्ता को कम करने के लिए कि इतनी महत्ता एक शहर न पाये। राजस्थान के वित्त मंत्री, श्री मथुरादास माथुर, राजस्थान के मुख्य मंत्री सुखाड़िया, जो जोधपुर के रहने वाले है और इस प्रकार दूसरे मंत्रियों ने षड़यंत्र रच कर जयपुर शहर की महत्ता को कम करने के लिए बीमा विभाग को तीन विभागों में विभक्त करना चाहा है, एक विभाग बीमा विभाग का जोधपुर में ले जाना चाहते हैं, एक पार्ट उदयपुर के अन्दर और एक पार्ट बीकानेर में ले जाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मेरी यह जानकारी है, मैं माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं, राजस्थान के वित्तमंत्री जो जो बजट प्रस्तुत करने वाले हैं उस बजट में साठ हजार का अधिक भार खर्च के रूप में रखा है। जो बजट आने वाला है उसमें साठ हजार रुपये का खर्च इसलिए ज्यादा रखा है क्योंकि राज्य बीमा विभाग के तीन कार्यालय जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में खोले जायेंगे, उसके अन्दर यह खर्च होगा। मै पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस विभाग के टुकड़े क्यों किये जा रहे हैं, · ·

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सभापति महोदय, आने वाले बजट में क्या आने वाला है यह आपको पता है· ··

श्री देवीदत्त गाडिया : बिल्कुल बता रहा हूं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : अच्छा. .

श्री देवीदत्त गाड़िया : बैठ जाओ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह बताइये, और क्या क्या आने वाला है, आपको सारे बजट का पता है भी ?

श्री देवीदत्त गाडिया : पंडित जी, आप विराजिये।

मैं कहना चाहता हूं, इस प्रकार इस विभाग के तीन टुकड़े क्यों किये जा रहे हैं, कर्मचारियों को दूसरी जगह क्यों भेजा जा रहा है। इससे उन्हें जो सिटी एलाउन्स मिलता है उससे वह वंचित होंगे और उनको हाउस रेंट देना पड़ेगा, उनका यातायात का खर्चा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, पूर्ण तरह से जो एस्टेब्लिश विभाग है उसको खण्डित क्यों किया जा रहा है ? राजस्थान के अन्दर आज करोड़ों रुपये का टैक्स लिया जा रहा है, क्या यह जनता पर एक और भार नहीं होगा ? यह निश्चित रूप से भार आयेगा। इस प्रकार अतिरिक्त खर्च करने से, साठ हजार का खर्च रख देने से अधिक भार पड़ेगा। मैं इसकी निन्दा करना चाहता हूं और यह पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है। इस विभाग में जो ढाई लाख पालिसी हैं उनको इधर से उधर किया जायगा। फिर क्या गारंटी होगी कि एक कर्मचारी एक जगह जाकर कर्ज ले सकता

(श्री देव दत्त गाड़िया)

है। उसको जोधपुर जाना पड़ेगा, बीकानेर जाना पड़ेगा, उदयपुर जाना पड़ेगा।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर यह भी नहीं बताया है कि इस राजस्थान के अन्दर कितने ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो एन्टी करप्शन के द्वारा पकड़े गये हैं। कितनों के विरुद्ध केसेज चल रहे हैं। कितनों की जांच सतर्कता आयोग कर रहा है? इसका अभिभाषण में पता नहीं है। ऐसा लगता है, राजस्थान की सरकार और राजस्थान का मंत्रिमण्डल आज भ्रष्टाचार को कोई पाप नहीं समझता है यह सरकार भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना चाहती है और राज्यपाल महोदय ने उसकी ताईद की है। राज्य सरकार यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहती है, और उसका इरादा होता तो अपने अभिभाषण में राज्यपाल महोदय इसको बताते, लेकिन इस सम्बन्ध में एक लाइन भी दिखाई नहीं देती है, जबकि बड़े बड़े सरकारी अधिकारी सीकर में रहने वाले ए. डी. एम. रिश्वत लेते हुए पकड़े गये। उस का क्या हुआ? कितने केसेज चल रहे हैं? इस सम्बन्ध में अभिभाषण में एक लाइन भी नहीं है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर अकाल राहत के बारे में कुछ जो बातें कही हैं कि राज्य सरकार ने इस एक साल के अन्दर पेंतालीस करोड़ रुपया खर्च किया है। यह खर्च पेंतालीस करोड़ का जो अकाल के नाम पर किया गया है, उसके अन्दर से अधिकांश रूप में, साठ पर्सेन्ट रिश्वतखोरी में गया है। क्या राजस्थान सरकार यह बता सकती है कि कितने राजस्थान के मंत्रियों ने अपने कुओं के ऊपर अकाल के पैसे से ट्यूब वेल लगाये हैं? कितने एम. एल. एज. ने, कितने कांग्रेस के प्रधान और सरपंच अकाल के नाम पर अपने खेतों के ऊपर केनाल लाये हैं? कितनों ने खेतों पर बाउन्डरी लगाई है? कितनों ने अपने खेतों का लेवल ठीक करवाया है? आज लाखों रुपया अकाल के नाम पर दिया है, लेकिन कई मंत्री और उप मंत्री हैं जिन्होंने अकाल के नाम पर ट्यूब वेल बनवाये हैं, उप मंत्री के पी.ए. ने अपने खेत पर ट्यूब वेल लगवाया है। इतना ही नहीं, मैं सिंचाई मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, बांसवाड़ा में यह दिनेश जोशी नाम का व्यक्ति कौन है? क्या यह सही है कि दिनेश जोशी के नाम से ट्रेक्टर किराये पर लिया गया और तीन महीने का अठारह हजार रुपया किराये का भुगतान किया गया जब कि ट्रेक्टर से एक दिन भी काम नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह दिनेश जोशी कौन है? क्या उद्योग मंत्री के सुपुत्र नहीं हैं? क्या कारण है कि ट्रेक्टर किराये से लिया? इस प्रकार मंत्रियों के लड़के और मंत्रियों के रिश्तेदार को अकाल के नाम पर अनुचित लाभ पहुंचाया है और धन का दुरुपयोग किया गया है। जहां सड़कें बनी हैं उनकी दुदर्शा हो रही है और जहां पर ट्यूब वेल खोदे गये हैं उनसे पानी नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, सभापति महोदय, अकाल के नाम पर लोगों ने गुलछर्रे उड़ाये हैं, जिनमें बहुत से

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

से पकड़े गये हैं। बाड़मेर के कलेक्टर ने अकाल के कई काले कारनामे पकड़े थे। उनका क्या हुआ ? उन सारे मामलों को दबा दिया गया है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अन्दर सहकारी संस्थाओं के बारे में कहा कि राज्य सरकार ने विकास के द्वारा राजस्थान की उन्नति के नाम पर हजारों सहकारी संस्थायें खोली है। यह सही है कि राजस्थान में हजारों सहकारी संस्थायें हैं। उन संस्थाओं को सरकार से कितना कर्जा मिला है ? उसका क्या हुआ ? लाखों करोड़ों के गबन के मामले चल रहे हैं चाहे झुन्झुनू कोआपरेटिव बैंक हो, चाहे बूंदी कोआपरेटिव बैंक हो, चाहे क्रय विक्रय संघ हो, चाहे चावल मिल हो चाहे महाराना मार्केटिंग सोसाइटी हो सारे के सारे भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस बैंक के खिलाफ जिस सहकारी संस्था के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें लिखित रूप में आई जिनका आडिट हुआ है, जिनकी पुलिस ने जांच की है, जिनकी भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच की है, उनका क्या हुआ ? राजस्थान के किसी मंत्री से पूछें, सहकारी विभाग के अधिकारी से पूछें, सब यह मानकर चलते हैं कि सहकारी संस्थायें भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। जांच हुई है लेकिन सब मामलों को दफनाया गया है। चावल सहकारी समिति जिसका उद्घाटन 6—7 महीने पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री सुखाड़ियाजी ने किया था। उद्घाटन करने के एक महीना बाद चावल की खरीद में ढाई लाख का घोटाला हुआ। पुलिस ने 34 बोरी पकड़ी लेकिन आज तक मामले को दबाया हुआ है। चावल मिल में घोटाला है। सहकारी विभाग के अधिकारियों ने जांच की, लेकिन ऊपर से फोन आया कि मामले को दबाओ, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस मामले को दबालो और उस मामले को दबाया जा रहा है। इस तरह की सहकारी संस्थायें चाहे बैंक हो, सबसे बड़े भ्रष्टाचार के अड्डे हैं क्योंकि अधिकांश बैंकों और सहकारी संस्थाओं में कांग्रेस पार्टी के प्रधान और एम. एल. एज. इन्वाल्वड हैं और इसी कारण से तमाम मामलों को दबाया जा रहा है।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में हजारों एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों को अनुसूचित जाति व जन जाति के गरीब व्यक्तियों को आवंटित करने की बात कही है। जमीन जरूर आवंटित हुई है इसमें दो राय नहीं। लेकिन भूमिहीन किसान व अनुसूचित जाति व जनजाति में कौन हैं ? क्या श्री गिरधारीलाल व्यास हैं ? क्या हम मानकर चलें कि चीफ व्हिप महोदय अनुसूचित जाति के हैं, क्या वह जनजाति के हैं, क्या यह भूमिहीन हैं, क्या वह गरीब हैं ? ऐसे व्यक्ति को भी जमीन आवंटित हुई है।

इतना ही नहीं मुझे माफ करें लेकिन निश्चित रूप से कह सकता हूं मुझे याद है आज से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री सुखाड़ियाजी ने सीकर के अन्दर भाषण दिया था कि जयपुर में मैं एक दिन घूमने गया मैंने देखा कि 1500 बीघा जमीन का एक प्लाट पड़ा हुआ। मैंने पूछा और जानकारी प्राप्त की कि यह जमीन किसकी

(श्री देवीदत्त गाडिया)

है। तो मुझे बताया गया कि वह 'हिज हाईनेस जयपुर की है, तो 1500 बीघा जमीन एक व्यक्ति के पास नहीं रहनी चाहिये, बेकार पड़ी नहीं रहनी चाहिए। यह आवंटित कर देनी चाहिए। मैं सुखाडियाजी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास 1500 बीघा जमीन नहीं है? चाहे उनके रिश्तेदारों के नाम हो चाहे वह बूंदी के अन्दर हो चाहे वह रघुनाथपुरा बूंदी में हो, चाहे किशनगंज तहसील बीगोद शाहपुरा में हो। 1500 बीघा से अधिक जमीन सुखाडियाजी के पास है। वह बात सीकर की ग्राम सभा में सुखाडियाजी ने कही थी।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : मंत्री के रिश्तेदारों को जमीन नहीं मिलेगी?

श्री देवीदत्त गाडिया : बैठिए। बता रहा हूं। यदि वास्तव में समाजवाद लाना चाहते हैं यदि देश के अन्दर गरीबी मिटाना चाहते हैं, लोगों को भुखमरी के शिकार से दूर करना चाहते हैं तो माननीय सदस्य जिनके पास इस प्रकार 15 बीघा से अधिक जमीन हैं वह भूमिहीनों को वितरण करने के लिए तैयार हैं? मैं श्री गिरधारीलालजी व्यास से पूछना चाहता हूं कि चाहे वह जमीन उन्होंने रिश्तेदारों के नाम एलाट करवा रखी है, मैं सुखाडियाजी से पूछना चाहता हूं, उपमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, नवाब साहब से पूछना चाहता हूं, गृहमंत्री श्री दामोदरलाल व्यास से पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार वह गरीबों को, भूमिहीन किसानों को जमीन देने के लिए तैयार हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप कह रहे हैं वह ठीक है, मैंने अपने नाम जमीन एलाट नहीं करवाई, पौने चार बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरे पास सारे की सारी नकलें हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह सही है कि मेरे लड़के के नाम 4 साल पहले 15 बीघा जमीन एलॉट हुई है और वह भी पैसा देकर एलाट करवाई है।

श्री देवीदत्त गाडिया : और भी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरे पास सारी की सारी नकले हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : रिश्वतें देकर एलॉट करवाई?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा है कि श्री गिरधारी लाल व्यास ने स्वयं अपने नाम एलॉट करवाई।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उन्होंने कहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उन्होंने कहा है कि अपने अपने रिश्तेदारों को भूमि एलॉट करवाई है। आपने अभी बताया कि बच्चे के नाम करवाई? और कौनसी जमीन है आपके पास?

श्री गिरधारी लाल व्यास : नहीं है।

Page No 98

श्री देवीदत गाडिया : बताऊंगा, मेरे पास खाते की नकलें हैं।

एक माननीय सदस्य : पैसा देकर काम करवाते हैं?

श्री डूंगाराम राजोरिया : पैसा देकर कौनसे नियमके अन्तर्गत काम करवाया?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरा कहना था कि मुफ्त में जमीन नहीं ली है, जमीन का पैसा देना पड़ता है।

श्री देवीदत गाडिया : बैंक राष्ट्रीयकरण के बारे में कहा गया था कि गरीबों को बैंकों द्वारा कर्ज दिया जाएगा लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि रिजर्व बैंक व सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आदेश दे दिया कि रिजर्व बैंक के पास पैसा नहीं है। सारे आदेश सभी बैंकों के अन्दर आ चुके हैं। सब बैंकों ने कर्जा देने से इन्कार कर दिया है और जिनकी दरख्वास्तें मंजूर हुईं वे भी रिजेक्ट कर दी हैं। इस बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है?

राज्य सरकार ने जो पहले कर्जा दिया था वह कर्जा पहले कितना दिया था और अब कितना दे रहे हैं। सब बन्द कर दिये और बैंकों के द्वारा जो दिला रहे हैं उसमें सरकार की कितनी पूंजी लग रही है, जांच की जाए तो जो सरकार कर्जा देती थी उसका आधा भी बैंक नहीं दे रही हैं, राज्य सरकार दीवालिया है।

रोडवेज के बारे में निवेदन करना है। मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। रोडवेज के चेयरमैन जो 1967 के अन्दर अजमेर से चुनाव हार गए थे श्री ज्वाला प्रसाद, उन्होंने बसों का किराया तो काफी बढ़ा दिया। आज रोडवेज की हालत यह है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अपने नेता से पूछ लें।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपभी उनकी वकालत में सांठ गांठ करते हो। टोंक में जो बस स्टेशन है वहां भारी खर्चा हो रहा है। राज्य सरकार ने चेयरमैन के रहने के लिए किराया फ्री बंगला दिया है चाहे उस पर कितना भी खर्चा लगे। चेयरमैन महोदय, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी हेड्स ऑफ डिपार्टमेन्ट्स हैं सबको किराया फ्री बंगला दे रखा है सबको आदेश दे रखा है कि चाहे मैनेजर हो चाहे डिप्टी मैनेजर हो 300), 350) के बंगले ले लो, रोडवेज उसका भुगतान करेगा। आज भी इस तरह के राजस्थान के सीनियर आर. ए. एस. ऑफिसर हैं जिनको रोडवेज में खपाया जा रहा है। इस पर इस प्रकार के खर्चे की क्या आवश्यकता है। कोई भी ऐसी रोडवेज दूसरी जगह की नहीं मिलेगी कि जिस पर इस प्रकार का प्रशासनिक खर्चा हो। रोडवेज के चेयरमैन और उसके अधिकारी राजस्थान के बाहर दौरे पर जाते हैं, दिल्ली, बम्बई आदि जाते हैं तो हवाई जहाज से उड़ान करके जाते हैं और पीछे पीछे उनके रोडवेज की कार जाती है। हवाई जहाज से इस प्रकार की यात्रा करना और गरीब जनता पर किराया बढ़ा कर इस प्रकार इसको लूट रहे हैं। गंगानगर के इलाके में रोड़वेज की बसें चल रही हैं। वहां पर

(श्री देवीदत्त गाडिया)

भारी चोरियां हो रही हैं। एम. एल. ए. की कमेटी गयी थी तो उसको पता लगा कि मशीनरी गायब है, टायर आदि गायब हैं और चोरियों में अधिकारियों का हाथ है। चेयरमैन कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : चोरों के राज में चोरी ही होगी और क्या होगी ?

श्री देवीदत्त गाडिया : वर्क शॉप अजमेर में खोला जा रहा है। तीन चार ठेकेदार ज्वाला प्रसाद जी के मुंह लगे हैं। चाहे बिजली का काम हो और कोई काम हो, उनसे सांठ गांठ करके उनको ठेके दिये जाते हैं। ट्रैक्टरों का काम कराया जा रहा है उसमें भी हजारों रुपयों की घोटाली है। उस पर क्या रोक थाम है ? क्या इससे गरीब लोगों का शोषण नहीं हो रहा है ? राजस्थान सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे और हम कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : रोकना नहीं चाहते हैं। अपने पास रखना चाहते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट का आडिट होता है और प्रतिवर्ष विधान सभा की तीन चार कमेटियां प्रतिवेदन देती हैं। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी। ये जांच करती हैं और रिपोर्ट देती हैं। उनमें बड़े बड़े घोटालों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और उनका सुधार करना चाहिये। आपने कौनसा कदम उठाया ? तीन वर्ष का इतिहास उठा कर देख लीजिये। रिपोर्ट प्रति वर्ष कमेटी की आती है लेकिन आज तक यह भ्रष्टाचार नहीं रुका। किसी अधिकारी के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाया गया। भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। अन्त में यह कहते हुए

श्री सभापति : दस दफा तो आप "अन्त में अन्त में" कह चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : कि समाजवाद का नारा देते हैं और चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। 23 वर्ष में ये नेता समाजवाद नहीं लाए, के गाय की पूंछ पकड़ कर ये कांग्रेस के नेता वैतरणी पार उतरना चाहें, उतर नहीं सकते। झुंझुनूं, चूरू, नागौर के क्षेत्रों में विरोधी पक्ष के सदस्यों पर डंडे बरसाये पुलिस ने, पत्थर फेंके, उनकी जीपों को तोड़ा। उधर के बैठने वाले नेता आज विरोधी पक्ष के सदस्यों का भाषण नहीं सुनना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इधर के लोग उनकी कलई खोलेंगे कि उन लोगों ने विरोधी पक्ष के लोगों पर पत्थर वर्षा करायी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह बिलकुल गलत है।

श्री देवीदत्त गाडिया : समाजवाद का नारा लगाया।

(श्री देवीदत्त गाडिया एवं श्री गिरधारीलाल व्यास के साथ साथ बोलने पर अक्षय)

(श्री देवीदत्त गाडिया)
जो लोग यह कहते हैं कि हम जनता के बल पर जीत कर आये हैं वह दिन दूर नहीं जनता जयपुर के चौराहों पर, कोटा और अलवर के चौराहों पर, जोधपुर के चौराहों पर खड़ी होकर उनसे एक एक पाई का हिसाब मांगेगी। कोटा, परमिट, लाइसेन्स के बल पर चुनाव जीतने वालों से जनता हिसाब मांगेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

श्री देवीदत गाडिया : निजाम को लेकर समाजवाद नहीं ला सकते। गरीब जनता को एक बार ही गुमराह किया जा सकता है उनके दिल को नहीं जीत सकते। वह दिन दूर नहीं जब राजा महाराजा की सत्ता नहीं रही तो आपकी भी सत्ता नहीं रहेगी और आप से एक एक पाई का जनता हिसाब मांगेगी। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमीलाल यादव।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : दल बदल किया इसलिये।

श्री अमीलाल यादव : सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में लोक सभा के मध्यावधि चुनाव हुए। नीतियों को लेकर ये चुनाव हुए। भारतवर्ष की जनता और खास तौर से राजस्थान की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इन्दिराजी की नीतियों को परखा और उनको बल देकर जिताया। देश के अन्दर इस बहादुर देश की नेता ने एक मानदण्ड कायम किया है।

जो दो रोज से माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है उसका रिपीटिशन न करते हुए जो मुख्य मुद्दे हैं, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रगति बतायी है उन पर ही प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश में अक्सर सूखा पड़ता रहता है पांच वर्ष में तीन वर्ष सूखा अवश्य पड़ता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने जो कार्य किये हैं वे बड़े सराहनीय कार्य किये हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि हमेशा अकाल पड़ते हैं और सोचते हैं उनके लिये हल निकालें। इसका एक महकमा भी अलग खोल दिया है। सरकार को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिये कि जिससे आगे से अकाल न पड़े। सलाहकार कमेटी होनी चाहिये। एक स्थायी कार्य होना चाहिये उसका इसमें तजकरा दिया है। जो ये अकालग्रस्त क्षेत्र हैं, 15 जिले हैं उनमें पानी, बिजली और सड़कों पर अधिक खर्चा किया जावेगा। ठीक है ये छोटी छोटी चीजें हैं, मजदूरी मिल जावेगी। लेकिन यदि परमानेन्ट तरीके के काम करेंगे तो मजदूर भी काम करेंगे और आप भी उनका परमानेन्ट हल निकाल सकेंगे। इस प्रकार से अकाल पडने से रोक सकते हैं यदि परमानेन्ट कार्य अकाल ग्रस्त क्षेत्र में किये जावेंगे तो।

(श्री अमीलाल यादव)

इसके साथ साथ यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, वास्तव में यदि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट मशीनरी को भी अपना एटीटयूड बदलना पड़ेगा । गवर्नमेन्ट की पालिसी को एक्जीक्यूट करने में उनको भी पूरी तरह से अपना रवैया बदलना होगा और काम करना होगा । आज लाल फीताशाही है और वास्तव में जो पालिसी सरकार की है यह सही रूप में एक्जीक्यूट नहीं होती है । जितने भी राजस्थान विधान सभा से कानून पास होते हैं उनके इम्पलीमेन्टेशन और एग्जीक्युशन में ही करप्शन और भ्रष्टाचार की बात होती है । कानून और रूल्स में कोई खराबी नहीं । यदि इम्पलीमेन्टेशन और एग्जीक्यूशन सही तरीके से कराया जावे तो मैं मानता हूं कि यह करप्शन की चर्चा ही बन्द हो जायेगी । आज आवश्यकता इस बात की है कि राज्य कर्मचारी, जो कि वास्तव में एग्जीक्यूशन और इम्पलीमेन्टेशन करते हैं, उनका माइन्ड बदला जाये, उनका दिमाग बदलना चाहिये ताकि वे सही तरीके से इम्पलीमेन्टेशन करें । यदि यह नहीं किया गया और यही ब्यूरोक्रेसी भारतवर्ष में चलती रही, तो बार बार करप्शन की बात होती रहेगी और भ्रष्टाचार की बात होती रहेगी । तो आज उनका माइन्ड बदलने की आवश्यकता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो सभी मेम्बर्स जानते हैं ।

श्री अमीलाल यादव : यदि कोई आदमी करप्शन की चर्चा करता है तो मिनिस्टर्स के ऊपर थोपते हैं । तो मिनिस्टर्स इस प्रकार के डाइरेक्शन नहीं देते हैं कि एक्ट या रूल्स के खिलाफ आफिसर कार्य करें ।

मैंने राज्यपाल के अभिभाषण को पढा है, उस अभिभाषण में थोड़ा सा तजकरा मिलिटरी पर्सनेल के लिये लैंड अलाटमेंट के बारे में है, इसके बारे में दो शब्द कहे गये हैं । राजस्थान में मिलिटरी पर्सनेल बहुत ही संख्या में हैं और वे बहादुर और वीर भी हैं । जितनी भी लडाइयां हुई हैं, चाहे पाकिस्तानी एग्रेशन के वक्त, चाहे चीन के आक्रमण के वक्त, राजस्थान के वीर सैनिकों ने जो कार्य करके दिखाया है उसकी बराबरी भारतवर्ष के किसी और प्रदेश के लोगों ने नहीं की होगी । लेकिन उनकी सहायता के लिये, उनके बच्चों की स्कालरशिप के बारे में, उनके आश्रितों को किसी और प्रकार से सहायता देने के बारे में, कुछ भी नहीं कहा गया है, उनके लिये कोई तजकरा नहीं है इस अभिभाषण में ।

पिछली दफा जो कमीशन्ड आफिसर्स डिस्चार्ज होकर आये थे, उनके लिये सर्विसेज में रिजर्वेशन का तजकरा आया था । लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह जो रिजर्वेशन आपने रखा था, उस रिजर्वेशन के तहत आपने कितने डिस्चार्ज्ड मिलिटरी पर्सनेल को नौकरी में रखा । यदि पर्याप्त मात्रा में नौकरी नहीं दी गई तो उनके लिये जो सुरक्षित स्थान थे उन स्थानों को आगे के लिये भी उन्हीं लोगों के लिये केरीओवर करके सुरक्षित रखना चाहिये । क्या ऐसा आपने किया है ? मैं समझता हूं आपने ऐसा नहीं

(श्री अमीलाल यादव)

किया। अभी कुछ समय पहले पुलिस विभाग में सब-इन्सपेक्टर्स और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट्स का सिलेक्शन हुआ था। उस सिलेक्शन में भी मिलिटरी पर्सोनेल के लिये कुछ स्थान सुरक्षित रखे गये थे, लेकिन उन स्थानों को यह कह कर नहीं भरा गया कि उन लोगों में से कोई पास नहीं हो सका। तो जहां तक इन लोगों के मेरिट का सवाल है, वह उन्हीं के बीच में से ही तय करना चाहिये और यदि वे लोग मिनिमम नम्बर आफ मार्क्स भी नहीं आब्टेन कर पाते हैं तो भी उन लोगों के लिये जो सुरक्षित स्थान हैं वे उनमें से ही भरने चाहिये। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मिलिटरी पर्सनेल के बारे में, जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं और जिन्होंने हमारे देश को आक्रमणों से बचाया है, उन लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिये और उन लोगों के लिये कोई प्रावधान नहीं है इस बारे में सरकार को देखना चाहिये। उनके सुरक्षित स्थानों पर उन्हें ही लगाना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज जो हमारे नौजवानों में बढती हुई बेरोजगारी है, उसके बारे में कोई प्लानिंग होना चाहिये। आज जितने भी शिक्षित नौजवान हैं, हाई स्कूल पास किये हुए, एस. टी. सी. पास हुए, बी. एड, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्नीकल हेंड्स जैसे ओवरसियर्स, इन्जीनियर्स, जितने भी हैं, उन सबकी सर्वे होनी चाहिये और उनके लिये प्लानिंग होनी चाहिये। जब तक देश में इस तरह का प्लानिंग नहीं होगा, तब तक यह जो आपने घोषणा की है कि प्रत्येक जिले के एक हजार व्यक्तियों को नौकरी दी जायेगी, वह काइटेरिया इनएफेक्टिव रहेगा, क्योंकि किसी जिले के अन्दर तो बहुत ज्यादा शिक्षित वर्ग आपको मिलेगा और किसी में बहुत ही कम।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अभी तो मैं पांच सात मिनट ही बोला हूं।

श्री सभापति : आपकी पार्टी के बहुत से और भी सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री अमीलाल यादव : जो नौजवान स्कूल और कालेज से निकल रहे हैं, अगर उनको आप रोजगार नहीं दिला सके, तो वे आपको बख्शने वाले नहीं हैं। यदि एक जिले में से एक हजार आदमियों को ही रोजगार देने का लक्ष्य रखते हैं, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि प्रत्येक जिले में कितने स्कूल और कालेज हैं, कितने एजूकेटेड लोग हैं, उनका रेशो देखकर प्रपोर्शन से रोजगार देना चाहिये।

इसके साथ साथ आपने कृषि ग्रेजुएट्स को कृषि भूमि अलाटमेन्ट करने की बात की। आज कितने बी. एससी. (एग्रीकल्चर) हैं जिनको आपने लैंड अलाट किया है? इसका भी इम्पलीमेन्टेशन और एग्जीक्यूशन होना चाहिये। हमारा ला और रूल्स स्पष्ट हैं लेकिन यदि सही मायने में वह इम्पलीमेन्ट नहीं होते हैं तो हम सही दिशा में नहीं जा सकेंगे और समाजवाद केवल नारे के रूप में ही रह जायेगा। इसलिये बेरोजगारी की जो समस्या है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिये, और जो

Page No 103

(श्री अमोलाल यादव)

जिलों के बारे में मैंने निवेदन किया कि जिले में कितने लड़के पढ़ते हैं, कितने ग्रेजुएट्स हैं, कितने ट्रेन्ड हैंड्स हैं, कितने ओवरसियर्स और कितने इन्जीनियर्स हैं, कितने बी. एससी. (एग.) हैं, उनके प्रपोर्शन के हिसाब से ही रोजगार दिलाना चाहिये और वह एक हजार तक ही सीमित नहीं होना चाहिये।

अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि शहरों और गांवों में भेदभाव की नीति अपनाई जाती है, उन्होंने शहरों और देहात का कम्पेरीजन किया था। मेरा निवेदन है कि शहरों और देहातों दोनों की तरक्की करनी चाहिये, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे यहां की 90 प्रतिशत जनता गांवों में ही रहती है। शहरों की भी तरक्की हो, यह मैं मानता हूं, लेकिन शहरों में भी जहां पर कच्ची बस्तियां हैं, जहां पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां पर पानी और सड़कों की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए माननीय सदस्य ने चर्चा नहीं की। उन बस्तियों में पानी की व्यवस्था नहीं है, उसकी चर्चा नहीं की, वहां पर कोई खर्चा नहीं किया गया, इसकी चर्चा नहीं की। केवल देहात और शहरों के बीच एक भेदभाव की भावना की बात कह कर ही रह गये। हमें देहात और शहरों के बीच भेदभाव की बात पैदा नहीं करनी है, हमारे लिये देहात और शहर दोनों ही समान हैं, लेकिन देखना यह है कि कौन ज्यादा गरीब है और कौन ज्यादा बेकवर्ड है। उनको ऊंचा उठाना है। आज के समाजवाद में जो गरीब और अमीर के बीच खाई है, उसको पाटना है और उनको नजदीक लाना है, उसमें न तो शहर को देखने की बात है और न देहात को देखने की बात है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अभी तो मुझे दस मिनट भी नहीं हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपके दल के बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं, उनको भी समय देना है।

श्री अमोलाल यादव : I will take only four or five minutes. After that I will stop.

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपको यह देखना पड़ेगा कि कितने जिलों में कितने प्रतिशत गांवों को इलेक्ट्रीफाई कर दिया जायेगा। कितने जिलों में पीने के पानी की समस्या को कम्प्लीटली खत्म कर दिया जायेगा। दिनों के साथ हम आये, हमारा काफी कैपीटल खर्च हो गया, और भी खर्च होगा, हम बढ़ रहे हैं, लेकिन तेजी के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। हमको टारगेट्स फिक्स करने चाहिये कि इन जिलों में एक भी गांव नहीं रहेगा जो सड़क द्वारा तहसील से जुड़ा हुआ नहीं होगा। यह लक्ष्य निर्धारित करके चलेंगे तो सही मायने में तेजी से हम लक्ष्य की तरफ चलेंगे।

इसी प्रकार शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के

(श्री अमीलाल यादव)

बारे से हमें यह बताना पड़ेगा कि कोई भी गांव, जिसकी आबादी तीन सौ से अधिक है, वह बिना प्राइमरी स्कूल के नहीं रहेगा। इस प्रकार के आंकड़े आने चाहिये। केवल यह कहना कि 50 स्कूल और खोले जायेंगे, यह पर्याप्त नहीं है। 26 ही जिलों में सब से ज्यादा प्राथमिकता इन दो चीजों को देनी चाहिये।

कृषि का जहां तक सवाल है, अच्छे बीज और खाद के बारे में किसान अपने आप जागरूक हैं। अच्छा बीज लेने के लिये और अच्छी खाद लेने के लिये आज उसको किसी प्रकार से समझाने की आवश्यकता नहीं है। आज प्रचार इस बात का आवश्यक है कि अच्छे बीज और अच्छी खाद का इस्तेमाल किस जगह हो सकता है, और वहां पर उनकी कोई कमी तो नही है। यदि कमी है तो उसकी पूर्ति की जाये। कई गांवों में कुए हैं, लेकिन उन पर बिजली नहीं दी गई है, वहां परबिजलीदेनेकीआवश्यकताहै। वहां यदि इनकी पूर्ति कर दी जाती है तो निश्चित रूप से देश की प्रगति होगी। इसी प्रकार जहां बोर्डर एरियाज हैं जहां दूसरे प्रदेश लगते हैं। मैं खास तौर से अलवर जिले के लिये निवेदन करना चाहता हूं। वहां पर साबी बान्ध के लिये कई बार बजट में कहा गया लेकिन आज तक उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया है। खाली सर्वे के लिये कहा जाता है। इसलिये ऐसे मसलों को लिया जाना चाहिये। अगर साबी बान्ध बना दिया जाता है तो न केवल अलवर जिले को ही फायदा होगा बल्कि इससे हरियाणा को भी फायदा होता है जो वहां की जमीन है वह काश्तकारों के काम में आ जायेगी। जनता को जो आने जाने में तकलीफ होती है वह मिटेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं जो अन्य प्रांतों में प्रगति चल रही है उसको देखकर भी हमें हर्ट बर्निंग होती है। जो बोर्डर एरिया से लिन्क है वहां पर सड़क और बिजली को लेकर ज्यादा चलना चाहिये ताकि हम यह बता सकें कि हमारे यहां भी प्रगति हो रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो क्षेत्र पिछड़े हुये हों वहां प्रगति नहीं करनी चाहिये, सभी जगह के लिये होना चाहिये। दूसरे अलवर जिले में बहरोड़ है उसमें इतनी ज्यादा एजूकेशन होते हुये भी लड़कों के लिये कालेज नहीं है। इसलिये वहां पर एक लड़कों का कालेज खोलना चाहिये। लड़कियों के लिये स्कूल ज्यादा खोलने चाहिये क्योंकि पहले तो हमारे यहां लड़कियों की शिक्षा ही बहुत कम है—कुछ तो पर्दा सिस्टम होने की वजह से और कुछ [illegible] राजाओं के द्वारा दबे रहने के कारण लड़कियों में कम शिक्षा रही है। अलवर जिले में लड़कियों की पढ़ने में ज्यादा उत्सुकता है। सारे जिले में एक लड़कियों का कालेज है इसलिए शाहजहांपुर मोढ़ा माजरीकलां में लड़कियों के सैकण्डरी स्कूल होने चाहिए।

श्री सभापति : पर्याप्त हो चुका, माननीय सदस्य। अब आप विराजिये।

श्री अमोलाल यादव : मैं अधिक समय न लेता हुआ मोटी मोटी बात निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री सभापति : आपने छोटी मोटी बात सब कह दी है ।

श्री अमोलाल यादव : मैं ज्यादा न कहते हुए केवल यह बात कह कर कि वास्तव में जो प्रगति हुई है यह कांग्रेस राज्य में हुई है । राजस्थान राज्य में पहले से काफी प्रगति हुई है । पहले क्या था और अब क्या क्या हो गया है यह सब जानते हैं काया पलट प्रगति हुई है । इन्हीं शब्दों के साथ जो राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण दिया है और माननीय सदस्य पी. के. चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय सभापति जी, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दो तीन रोज से विचार हो रहा है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने से एक बहुत सीधा सादा सा हिसाब सामने आता है । समाजवाद का जो नाम दिया गया है वह मेरी समझ में नहीं आता । यह समाजवाद कैसी चीज है और इसमें रस कैसा है । हम देखते हैं 23 साल की आजादी में इस समाजवाद के फल को चख नहीं सके । सही माने में समाजवाद कब पूरा होगा इसको सोचना है । आप सोचते हैं समाजवाद के नाम पर जो समाज का शोषण किया जा रहा है हमको इस बात पर भी सोचना है । यह समाजवाद है या समाज के ऊंचे लोग समाजवाद के नाम पर समाज का शोषण करते जा रहे हैं । अगर देश में शोषण गरीब और दबे हुये लोगों का बन्द हो गया तो देश में सही समाजवाद हो सकता है लेकिन इनकी तो करनी और कथनी में फर्क है । समाजवाद के नाम पर हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा है वह देश के सामने हो रहा है । अब देश में समाजवाद की जरूरत है समाजवाद नारों से नहीं आयेगा । समाजवाद हम सबके मिलकर लाने से होगा ।

आप जानते हैं समाजवाद एक ऐसी चीज है—समाजवाद में हिन्दुस्तान के सब नागरिक समान है छोटे और मोटे, गरीब और अमीर सबको समाजवाद में समान अधिकार होने चाहिये लेकिन हिन्दुस्तान का जो समाजवाद है, हिन्दुस्तान का जो नक्शा है वह हमारे सामने है । क्या हिन्दुस्तान में समाजवाद नाम की कोई चीज है ? मैं नहीं समझता हिन्दुस्तान में कोई समाजवाद है । हिन्दुस्तान के गरीब हरिजन है उनकी हालत क्या है ? आज वे भी हमारे समाज के अंग है और समाज में पैदा हुये हैं । आज वे लोग सड़कों पर मैला ढोते हैं और यह सरकार समाजवाद की बात करती है । लानत है ऐसी सरकार को जो समाजवाद के नाम पर उनका शोषण करती है । ऐसे समाजवाद की बात करने वाले, 20 साल से हुकूमत करने वाले यही समाजवाद का नकशा खोलकर बैठे हैं । अभी भी दबे हुये गरीब हरिजन हिन्दुस्तान में मैला ढोते हैं, टट्टियां उठाते हैं और फिर हिन्दुस्तान में समाजवाद की बात करते हैं । दबे हुये इन्सान मैला ढो रहे है । आज आप जानते है देश में दबे हुये इन्सान की हालत

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

क्या है। आज इन्सान इन्सान में कितना फर्क है यह आप जानते हैं। गांवों में रहने वाले इन्सान भी इसी हिन्दुस्तान में पैदा हुये है उनको भी नागरिकता के समान अधिकार नहीं हैं। आज गांवों में दबे हुये इन्सान खेत में कुत्तों के साथ पानी पीते हैं। इतने हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं, वे सब जानते हैं कि गांवों की हालत क्या है। अगर किसी हरिजन का हाथ छू जाये तो लोग नाराज हो जाते हैं और उसको अपवित्र मानते हैं। यह तो आपकी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बदलना है तो समाजवाद के ढोल को बजाना बन्द कर दो। हमको देश में सही समाजवाद लाना है तो इन्सान–इन्सान का भेद मिटाना होगा। समाजवाद का सही मायना बताना होगा।

आज हजारों लोग भूख से मर रहे हैं। हिन्दुस्तान के नौजवान लोग भूख से सड़ रहे हैं। राजा–महाराजाओं के पास, पूंजीपतियों के पास, सेठों के पास और नये राजाओं के पास अनाप–शनाप अनाज सड़ रहा है लेकिन हमारा दबा हुआ इन्सान भूखों मर रहा है। उनके पास करोड़ों की सम्पत्ति है लेकिन दूसरी तरफ लोग खाने को मोहताज हैं। ये देश के सामने समाज-वाद का नारा लगाने वाले जो हिन्दुस्तान पर 20 साल से शासन व्यवस्था कर रहे हैं कौनसा समाजवाद ले आये हैं लेकिन हिन्दुस्तान को बताने के लिए समाजवाद का नकशा लाये हैं। 20 साल की आजादी में जो भूख से सड़ने वाले लोग हैं उनको रोटी का टुकड़ा दिखा रहे हैं। यह समाज-वाद आज कहां से आ गया। 20 साल तक आपने राजस्थान में राज्य किया और 23 साल की आजादी का आपने दुरुपयोग किया है। मैं कहना चाहता हूं आपकी सत्ता के बीच में कौन अड़चन डाल रहा था जो आज तक आप समाजवाद नहीं ला पाये। जिनके हाथों में पिछले 23 सालों से सत्ता की हुकूमत थी, जिनके हाथों में राजस्थान का राज्य था वास्तविक रूप में वे ही समाजवाद के गद्दार हैं। उन्होंने दबे हुये लोगों का शोषण किया है। गांवों में जाते हैं और समाजवाद का नारा देते हैं तो हमारे ग्रामीण भोले भाई समझते हैं समाजवाद कोई अंगूर है क्या या कोई खाने की चीज है। आज भी दबे हुये हरिजन कुत्तों के साथ पानी पी रहे हैं। महात्मा गांधी के समाजवाद का आप इस तरह शोषण करना चाहते हैं। आप महरबानी करके समाजवाद के नाम पर शोषण करना बन्द करें और इन्सान–इन्सान में जो भेद है उसको खत्म करें। एक तरफ आप टट्टी जाते हैं पाखाने में और दूसरी तरफ हिन्दुस्तान का दबा हुआ इन्सान टट्टी को माथे पर उठा कर दूसरी जगह ले जाकर डालता है। यह है आपका समाजवाद, यह है आपकी नीति ? आपके थोथे नारों से हिन्दुस्तान का दबा हुआ इन्सान बहुत ज्यादा दब चुका है, उसकी आत्मा रो रही है कि हिन्दुस्तान की आजादी के लिए जो लोग मरे थे, राजस्थान की आजादी के लिए जो लोग मरे थे तो क्या वह इस तरह के समाजवाद के लिए मरे थे ? आपको याद रखना है कि हिन्दु-स्तान की आजादी के लिए आपसे ज्यादा उन लोगों ने बलिदान किया है, आपसे ज्यादा वह लोग जेलों में गये हैं जो कि आज दबे हुये पड़े हैं। आज उनकी को

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

कद्र नहीं है, आप उनको आज पशु समझते हैं जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए हिस्सा लिया। आप उनको भूल गए जिन्होंने राजस्थान की आजादी के लिए हिस्सा लिया। आप महात्मा गांधी को भूल गए, आप पण्डित जवाहरलाल नेहरू को भूल गए, आप भगतसिंह को भूल गए। आप सबको भूल गए लेकिन आपको कुर्सी चाहिये। आपने सोचा कि देश के सामने समाजवाद का नक्शा ले आओ और इससे 20 साल और निकल जायेंगे। आपको देश के सामने न तो समाजवाद देना है और न कोई बात है, बस आपको तो कुर्सी कायम रखनी है। लोग किस तरह से अविश्वास में आ जायें और आगे और समय निकल जाये, बस इसी में आप लगे हुए हैं। आपको समाजवाद लाना है तो सबसे पहले मैं चेयरमैन महोदय आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी हिन्दुस्तान का नागरिक किसी भी नागरिक की टट्टी उठाकर नहीं डालेगा। ऐसा कानून यदि आप बना देंगे तो मैं मानूंगा कि आपका समाजवाद है नहीं तो आपका थोथावाद है और इस नारे से आपको अपना राज्य रखना है तो आप रखते जाइये लेकिन दबे हुए इन्सान की आत्मा आज रो रही है अगर आपका यही समाजवाद है तो।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि आप नारे बहुत सुन्दर लाये। आपके बहुत ही प्रगतिशील विचार हैं। आपने लोगों के सामने बहुत सुन्दर विचार रखे हैं लेकिन आपके विचार कहां तक सही हैं यह आप देखें। हिन्दुस्तान की बीस साल की आजादी में गांवों में बसने वाले इन्सानों को पीने का पानी नहीं मिला है यह है आपके समाजवाद का नक्शा। यह है आपका समाजवाद कि लोगों को पेट भर दाने नहीं हैं। आपने हिन्दुस्तान के लोगों के सामने कैसी व्यवस्था की है? साढ़े बारह रुपये महीने का आप सहायता का देंगे और कहते हैं कि आपको भूखों नहीं मरने देंगे। यह है आपकी राज्य व्यवस्था और गरीब लोगों की आपने यह हैसियत आंकी है। आज साढ़े बारह रुपये से क्या होता है, साढ़े बारह रुपया क्या है और इससे क्या हो सकता है। आज इसमें तो चाय तक नहीं मिलती और आप कहते हैं कि इससे पेट भर लो और काया को तोड़ लो। आपका समाजवाद तो यह है कि आज अगर मन्त्री महोदय के पास एक डायरी है और उस डायरी को यदि आप दो में बांट देंगे तो उससे तो दोनों का ही काम नहीं चलेगा और यदि इस डायरी के अलावा आप दूसरी डायरी और बनायेंगे तो दोनों का काम चल जायेगा। इसी तरह से आपके पास धोती है, यदि इसी धोती को आप बांट देंगे तो फिर मुश्किल से लंगोट बन पायेगी और धोती किसी को भी नहीं मिलेगी और यदि हम समाजवाद को और आगे बढ़ायेंगे तो फिर क्या होगा यह आप खुद ही बता सकते हैं एक लाइन में आप नंगे करके खड़ा कर देंगे। यह है आपके समाजवाद का रूप। अगर आप हिन्दुस्तान के लोगों को सही माने में समाजवाद देना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राजस्थान केनाल और खेती का जो काम है उसमें ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाना

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

होगा कि हर किसान के खेत पर कुआ होना चाहिये। आप उनको लोन देंगे तो हमारे हिन्दुस्तान के किसान भाइयों की माली हालत अच्छी होगी और देश में किसान अनाज पैदा करेगा तो सही माने में समाजवाद आयेगा। लेकिन आप यह नहीं करना चाहते है। अगर आप बिजली देंगे तो उसके परिवार में जरूर समाजवाद आयेगा। लेकिन आप यह नहीं चाहते कि देश के लोग आगे बढ़ें। आप लोग जानते हैं कि राजस्थान में गंगानगर ऐसा इलाका है जहां गंग केनाल को बीकानेर के भूतपूर्व राजा श्री गंगासिंहजी लाये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमारे हिन्दुस्तान की आजादी को खतरा था नेफा और लद्दाख की तरफ से तब पण्डित जवाहरलाल जी नेहरू ने देश के लोगों के सामने यह अपील निकाली कि देश की आजादी को खतरा है और मुझे सोने की आवश्यकता है तो राजस्थान में गंगानगर एक ऐसा जिला है जिसने पण्डित जवाहरलाल नेहरू को सोने से तोला और एक बार ही नहीं बल्कि तीन-तीन बार तोला। लेकिन वह करामात आपके समाजवाद की नहीं है। वह करामात है गंग केनाल के पानी की, राजस्थान केनाल के पानी की। दूसरी ओर आपका समाजवाद क्या है? आपके समाजवाद में तो पीछे आंधी चल रही है और आगे सड़क चल रही है यह हमारे राजस्थान का समाजवाद और वहां के क्षेत्र के बीस हजार किसान अपनी मांगें लेकर आये। आप भी हरित क्रांति ला रहे है और कहते हैं कि हम हरिजनों को जमीनें देंगे लेकिन आप न तो जमीन देते हैं और न आपके पास कोई प्रोग्राम है। न जमीन देने की व्यवस्था है और न कोई बात है। आप तो कहते हैं कि हर साल जमीन को नीलाम करो। आप जानते हैं कि जब काश्तकार को आप एक साल के लिए जमीन देंगे तो एक साल के लिए काश्तकार मेहनत करेगा, उसको सुधारेगा, उसको सीधी करेगा और मेहनत करने के बाद अगली साल आप क्या करेंगे कि हम तो बोली देंगे। यह है आपके समाजवाद का नक्शा। इस नक्शे को आप बदलिये। आपकी रीति नीति को बदलिये। अगर हिन्दुस्तान में समाजवाद लाना चाहते हैं तो आप इस तरह भूमि की नीलामी मत करो। जिन काश्तकारों के पास भूमि नहीं है उनको भूमि दें। आपने नारे सुन्दर लगाये कि हम हरिजनों को भूमि देकर उनको ऊंचा उठा रहे हैं। आपने देखा है कि गंगानगर में जहां ऊंचे ऊंचे टीबे हैं वहां पर आपने हरिजनों को जमीन दी है। जब इसके लिए आफिसर्स को कहा जाता है तो वह कहते हैं कि क्या करें राज्य की व्यवस्था ही ऐसी है कि चूंकि ऊंचा उठाना है इसलिए ऊंचे टीबों पर जमीन दी है। वहां पर सात पीढियों तक भी पानी नहीं लगेगा। आप हिन्दुस्तान में सही माने में समाजवाद लाना भी चाहते हैं, देश की आजादी को मजबूत करना चाहते हैं तो आप भी खुद मजबूत हो जाओ। यदि आप मजबूत हुए तो आपका देश मजबूत होगा हम सब मजबूत होंगे और इससे गरीब लोग ऊंचा उठेंगे। आपको जल्दी से जल्दी राजस्थान केनाल को पूरा करना चाहिए। लूनकरनसर की लिफ्ट इर्रीगेशन को आपको नागौर तक पहुंचाना चाहिए।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा काम यह है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनके खेतों में कुए हों, बिजली हो और साथ ही आप उनको ट्रेक्टर्स दीजिए। लेकिन आप ट्रेक्टर किन को देते हैं? आप ट्रेक्टर उनको देते हैं जिनके पास पहले ही चार-चार ट्रेक्टर्स हैं। बीकानेर जिले में आपने किसी भी आदमी को ट्रेक्टर नहीं दिया ट्रेक्टर तो ऐसे लोगों को दिये जाते हैं जिनके पास पहले से ही ट्रेक्टर हैं और गाड़िया आप उनको देते हैं जिनके पास पहले से ही गाड़िया है। जिनके पास पहले से धोती है उनको आप दस दस धोतियां और दे देंगे लेकिन हिन्दुस्तान के नंगे नागरिक के लिए कोई समाजवाद की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए आपके पास कोई कपड़ा नहीं है, उनके लिए आपके पास मकान नहीं हैं। आपके पास उन लोगों के लिए तो व्यवस्था है कि जिनके पास पहले से ही दस मकान हैं। आप उनको और मकान बनाने के लिए पैसा दे देंगे। लेकिन आज हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत औलाद नवजवान भगतसिंह हो सकती है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि जिनके पास 10 कोठियां हैं और 10 कोठियां और बढ़ाने के लिए पैसा दे देते हैं। सिनेमा के लिए पैसा दे देते हैं, लेकिन जो हिन्दुस्तान के गावों में, जंगलों में और सड़कों पर बच्चे पैदा होते हैं उनके पास न तो तन ढकने को कपड़ा है और न बिछाने को चटाई है। हिन्दुस्तान में भुखमरी, बेकारी दिनोंदिन फैल रही है। इनके जमाने को 20 साल तो हो गये लेकिन समाजवाद लाए नहीं और न हिम्मत है। क्या करें वे ऐसे समाजवादियों से घिरे हुए हैं, उनके घेरे में है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) जिनके पास अरबों रुपये बैंकों में पड़े हुए हैं...

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपने काफी समय ले लिया है। और बहुत से बोलने वाले हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इन्दिराजी का जो समाजवाद है वह एक ऐसा समाजवाद है जिस समाजवाद को ये लोग घेरे हुये हैं। उस घेरे को तोड़ना है। जो इन्दिराजी को घेरे हुए हैं तो उस घेरे में समाजवाद के नाम पर हिन्दुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपति लोग हैं और वे इन्दिराजी के आस पास बैठे हुए हैं और वे हिन्दुस्तान में कभी समाजवाद नहीं आने देंगे। आज वे देश का धन थोड़ा थोड़ा करके हिन्दुस्तान के बाहर भेजते हैं। देश में समाजवाद लाना है तो हिन्दुस्तान के लोगों में नये सिरे से चेतना लानी पड़ेगी, नये सिरे से संघर्ष करना पड़ेगा। भाषणों से समाजवाद हिन्दुस्तान मे नहीं आयेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो भाषण मत दो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : देश को बन्दूक उठानी पड़ेगी। देश में जीवन नहीं है कि जो बन्दूक उठाये। बन्दूक से राज्य को बदल सकते हैं तभी ठोस समाजवाद आ सकता है।

इसलिए मैं आपकी मारफत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो नीति है, आपकी जो चालें हैं, आपका

Page No 110

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जो चलन है उसको मेहरबानी करके बदल दें तो बहुत अच्छी बात है। आज देश की जो दबी हुई आत्मा है, देश का गरीब तबका है वह भुखमरी से दबा हुआ है, आपकी समाजवादी व्यवस्था के शोषण से चूसा हुआ है उसको कृपा कर ऊपर उठायें। उसके ऊपर और बोझ लादकर उसको मारने की कोशिश मत करो। आप चेत जाओ समय रहते। आप समाजवाद के बोझ से दबते जायेंगे तो देश में समाजवाद आना मुश्किल है।

इसलिए मैं राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है उस अभिभाषण को बिल्कुल थोथा मानता हूं। उसमें एक समाजवादी नक्शा लाये हैं यही पिछले साल भी दिखाया है यह कोई नया समाजवाद नही सागी समाजवाद है। इस तरह के समाजवाद में हमारा विश्वास नहीं है। इसलिए देश की व्यवस्था आपके हाथ मे है राजस्थान में उसको महरबानी करके सुधारें। आपने मानव मानव में भेद कर रखा है। लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। (समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : बार बार कह दिया। भाषण समाप्त करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, मुझे सख्त एतराज है कि आप इस तरह बीच में बाधक न बनें। आप बार बार लाइट बन्द कर देते हैं।

श्री सभापति : बार बार वही की बात वही बात रिपीट कर रहे हैं उससे क्या फायदा ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देश की राज-व्यवस्था जिन लोगों के हाथों में है। राजाओं का नाम लेकर मजाक उड़ा रहे हैं तो राजाओं का राज्य क्यों नहीं बदला। देश के लोगों के सामने खाली नारा है कि समाजवाद लाना है इसलिए राजाओं के अधिकार छीनना है। आपको 20 साल हिन्दुस्तान में आजादी के बाद राज्य करने का मौका दिया है उसके बाद देश के लोगों के सामने यह नक्शा लाये हैं कि राजाओं के अधिकार खत्म करना है इसलिए गाय और बछड़े को वोट दो। वैसा ही समाजवाद का पहले नक्शा लाते। मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री नाथूलाल करौल।

श्री नाथूलाल करौल (जमवा रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो माननीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका विरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण इस सदन के अन्दर दिया है वह इस 14 साल के अरसे में जितने भी भाषण राज्यपाल महोदय ने दिये हैं उनसे सबसे गिरा हुआ है और सबसे दरगुजर भाषण मुझको यहीं पढ़ने को मिला है। माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि हमने शान्तिपूर्वक जो लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए हैं, उनको करा दिया है, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह नहीं कहा

Page No 111

(श्री नाथूलाल करोल)

कि गवर्नमेंट मशीनरी ने इन चुनावों के अन्दर काम किया है। इसका कतई उन्होंने जिक्र नहीं किया। क्यों करते ? मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं। शाहपुरा राव साहब पधार गये हैं। मैं उनकी कान्स्टटुएन्सी बैराठ का ही उदाहरण देना चाहता हूं। वे उठकर अपने चैम्बर में चले गये होंगे...

एक माननीय सदस्य : कौन से राव साहब ?

श्री नाथूलाल करोल : शिक्षा मंत्री।

माननीय सभापति महोदय, एक उप वैद्य पंचायत समिति, शाहपुरा की पंचायत खोरा, लाढखानी, ग्राम खोरा लाढ़खानी में हैं उनको 26 नवम्बर को वहां की जनता के अनुरोध पर राज्य मंत्रीजी के पी. ए. ने उप वैद्य श्री कल्याण का तबादला राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय देवीपुरा में किया गया था। उस उपवैद्य का तबादला वापिस खोरा लाढ़खानी में 16 फरवरी को कर दिया गया। तीन महीने में वापस उनको उसी जगह पर लाया गया जब कि खोरा लाढखानी के अन्दर 8 साल से बराबर वे रहते आये हैं, और जनता उनसे परेशान थी। उनके तबादले के लिए 50-60 आदमियों का डेप्युटेशन राज्य मंत्रीजी के सामने आया और उन्होंने तबादला उनका दूसरी जगह देवीपुरा में किया, लेकिन उपशिक्षा मंत्रीजी की महरबानी से उसी उपवैद्य को वापस खोरा लाढ़खानी के अन्दर 16 फरवरी को लाया गया जब कि चुनाव का टाइम था और चुनाव का समय था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिला आयुर्वेदिक अधिकारी पश्चिमी क्षेत्र ने राव साहब की कान्स्टीटुएन्सी में 22 से 28 फरवरी तक टूर किया और राव साहब की जीप में वे गये। मेरे ख्याल से टी.ए., डी. ए. भी उन्होंने उठाया होगा। चुनाव के समय उनकी कान्स्टीटुएन्सी का दौरा करना और उप वैद्य का तबादला देवीपुरा से खोरा लाढ़खानी में कर देना क्या उचित है ? उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट के लिए प्रचार किया और वोट प्राप्त करने की कोशिश की। यह एक छोटा सा उदाहरण मैंने शाहपुरा राव साहब की कान्स्टीटुएन्सी का दिया है।

मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह से चुनाव के अन्दर गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा दबाव डालकर वोट लेना यह जनतन्त्र के अन्दर अच्छा नहीं है। इस तरह से गवर्नमेंट मशीनरी के द्वारा गांव गांव में प्रचार करके वोट प्राप्त करना क्या अनुचित है। न हमारे पास साधन हैं और न गवर्नमेन्ट की मशीनरी है और न कुछ हैं। हम जनता के सामने जिस प्रकार जाते हैं उसी तरह से उनको आना चाहिए, लेकिन सत्तारूढ़ इस तरह से नहीं कर रहा है।

अब मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के मुताल्लिक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कि गरीबी और बेकारी फैलती जा रही है जिसके लिए हमें बड़ा दुःख है। उन्होंने जब अपने अभिभाषण में यह कहा है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस राज्य सरकार

(श्री नाथूलाल करोल)

से कि गरीबी को और बेकारी को किस तरह से मिटाना चाहते है ? जमीन जितनी सिवाय चक मोजूद थी वह बांट दी गई है उसका डिस्ट्रिब्यूशन कर दिया गया है। जमीन तो चली गई। बेकारी कैसे दूर होगी ? आप कहते हैं कि बेकारी दूर करने के लिए शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को जमीनें बांटी है। मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि शैडयूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स को जितनी भी जमीनें एलाट की गई हैं साल भर में भ्रष्टाचार के रूप में हुई हैं तहसील वालों ने उनसे इतना पैसा लिया है कि उन्होंने जमीनों की कीमत अदा कर दी। उनके ऊपर सरकार ने कोई अहसान नहीं किया। काफी भ्रष्टाचार हुआ और तहसील के अन्दर काफी गवर्नमेंट मशीनरी ने पैसा वसूल किया है नामान्तरणकरण करने में, पट्टा देने में, नम्बर देने में, जमीन एलाट करने में। उन्होंने खूब पैसा लिया और जमीन की कीमत ले ली। जमीन और नहीं रही है शैड्यूल्ड कास्ट के लोग इतने बेकार बैठे हैं कि उनको जमीन देकर उनकी बेकारी दूर नहीं कर सकते हैं।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि जमीन तो है नहीं। कोई है भी तो टीबे टीकरे या नदी नाले है। उनको कैसे अलाट करेंगे। उनको जिसको अलाट करेंगे तो उसका इतना खर्चा होगा कि जिसकी हद नहीं।

आप अगर बेकारी दूर करना चाहते है तो नये उद्योग लगाने पड़ेंगे। अगर सरकार इस बात को सोचे तो उसको जगह जगह उद्योग लगाना चाहिये। ये उद्योग लगाये जायें तो बेकारी दूर हो जायेगी। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा, और आपकी मार्फत सरकार से भी कहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि 91-92 ग्राम सहकारिता में आ गये हैं। वह सही है लेकिन पैसे का भारी दुरुपयोग हुआ है। वे लाखों रुपया राज्य सरकार का बकाया है। सोसाइटीज ठप्प पड़ी हुई हैं। राज्य सरकार कहती है कि हमने सहकारिता में बड़ी सफलता प्राप्त की है। मैं कहूंगा जो आपके वर्कर्स हैं वह रुपया चाट गये हैं। अगर पैसे को अच्छे धन्धे में लगाते तो गरीब आदमियों को रोजगार मिलता। आपके जो वर्कर्स हैं वह हजारों रुपया खा गये हैं। आपने पंचायत समितियों को जो भी लोन दिया है, उसका बिलकुल दुरुपयोग हुआ है। आपने अनुदान दिया है कुवे खोदने के लिये उनके गड्ढे बने हुए हैं। राज्य सरकार दिवालिया होती जा रही है। अरबों रुपया का जनता पर आपने कर्जा कर दिया है। आज सत्ता में आप हैं। कल दूसरी पार्टी सत्ता में आकर बैठेगी तो वह क्या करेगी ? राज्य सरकार का काम चुनाव जीतना और गुलछर्रे उड़ाने का ही है।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य)

श्री नाथूलाल करौल : अच्छा महाराज।

राज्य सरकार अपनी बकाया वसूल करके उसका सदुपयोग करें। दुरुपयोग रकम का न हो। बहुत से पैसे राज्य सरकार वैसे ही छोड़ देती है। पंचायत समितियों में जो पैसा बकाया है उसको वसूल किया जावे

Page No 113

(श्री नाथूलाल करौल)

राइट ग्राफ न किया जावे। मैं राज्य सरकार से निवेदन कर दूं कि राइट ग्राफ तो कर दो पर कर्जदार होते जा रहे हो। सरकार दिवालिया हो रही है। पी. ए. सी. में जो रिप्लाई देने आते थे, वह कहते थे। तो मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि राइट ग्राफ करते जाओ लेकिन यह भी ध्यान में रखो कि कर्जदार होते जा रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। उसको बचाने की कोशिश करें। ताकि यह जनता के काम आये।

मैं निवेदन कर दूं वन मंत्री महोदय को भी जयपुर के आसपास 6 मील के अन्दर जंगल है। मैं सही कहना चाहता हूँ कि जंगलों का इतना दुरुपयोग हुआ है कि सब साफ हो गये है। वन सम्पदा आपकी खत्म हो चुकी है। हर रोज 40-40 कट्टे 50-50 कट्टे बिकते हैं। आपका एक-एक आदमी 100-100 रुपये रोज कमाता है। आप इन्क्वायरी कराना चाहें तो मैं तैयार हूं। आप तो देवता आदमी हैं।

एक माननीय सदस्य : इनको पता है।

श्री नाथूलाल करौल : यहां का डी. एफ. ओ. है, वह साझीदार है। उसको और बाकी स्टाफ को भी काफी दूर भेज दिया जावे। आप विराज रहे है, तो मैंने निवेदन किया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपका मतलब यह है कि जहां जंगल कटे नहीं हैं, वहां उनको भेजें ताकि वहां भी कट जायें।

श्री नाथूलाल करौल : चारों तरफ जंगल साफ हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : यह नहीं कहना चाहते हैं।

श्री नाथूलाल करौल : कल तक आपके पास एक डेलीगेशन आने वाला है, वह यही बतायेगा कि वन सम्पदा देख लीजिये।

माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण में बिजली का कोई जिक्र नहीं है। मैं निवेदन करूं कि जयपुर से 12 मील के अन्दर रेडियस में पूरे ग्रामों में बिजली नहीं दी गई है। मैं बिजली मन्त्री से निवेदन करूं कि 12 मील के रेडियस में कितने गांव छूटे हुए हैं। जिन ग्रामों को इस परिधि में छोड़ रखा है उनको बिजली की लाइन दी जावे। यह तय किया गया था कि 40 किलोमीटर की लाइन हर पंचायत समिति में खींच देंगे। मैं निवेदन करूं कि प्रपोजल तैयार किया गया और प्रोडक्शन कमेटी द्वारा बिजली विभाग को भेजा गया है, वह अमल मे आज तक नहीं आया है। 31 मार्च होने वाला है। 13-14 दिन और रह गये हैं। जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश की जावे . .

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली के लिये निवेदन कर रहा था अब सिंचाई विभाग की तरफ राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री नाथूलाल करौल)

एक श्यामपुरा बन्ध पंचायत समिति, चाकसू में मंजूरी हो चुकी है लेकिन वैसा ही पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करूं कि जो काम हाथ मे लिया जाये उसको पूरा किया जाये।

श्री सभापति : समाप्त करें। बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री **नाथूलाल करौल** : सभापति महोदय ने कहा है कि समय कम है लेकिन अन्त में अर्ज करना चाहता हूं कि पैसे का यूटिलाइजेशन ठीक तरह से हो। पैसे की बरबादी बन्द हो। समाजवाद की तो आशा नहीं है कि समाजवाद आयेगा। 23 साल हो गये हैं। अभी तक नहीं आया है तो अब क्या आयेगा। इन्दिराजी ने जो नारा लगाया है। उसको वह पूरा करती है या नहीं। उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो चुकी है। हम भी समाजवाद चाहते हैं। आज आवें, 12 महीने मे आवें। 6 महीन मे आवें। देख लेते हैं। आता है या नहीं।

श्री **सभापति** : श्री शंकरलाल।

श्री **शंकरलाल जाट** (कपासन) : माननीय सभापति महोदय, राजपाल महोदय ने सदन में आकर जो कृपापूर्ण अभिभाषण दिया और उसके लिये श्री पी. के. चौधरी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में मैं कुछ निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

राज्यपाल महोदय ने यह बताया कि समाजवाद की दृष्टि से सरकार ने बड़े उत्साहजनक कदम उठाये हैं। मध्यावधि चुनावों की भी चर्चा हुई। वह वास्तव में यह एक ऐतिहासिक निर्णय जनता ने किया और उसी के अनुसार इन्दिराजी समाज को गति देने के लिए कदम उठा रही हैं।

हमारे सदन में चुनावों को लेकर बहुत सी बात कही गई। इन चुनावों से किशनगढ काण्ड को जोड़ा गया और कोटा की फैक्ट्री के मामले को जोड़ा गया। सेठों से मिले हुये हैं कांग्रेस वाले, यह भी कहा गया। मैं निवेदन कर दूं कांग्रेस वाले सेठों से मिले हुए नहीं हैं, बल्कि जनसंघ वाले मिले हुए हैं। यह मैं कह सकता हूं। उनको चित्तौड़ से और कोई अपना कार्यकर्त्ता नहीं मिला, इसलिये एक सेठ को बाहर से लाकर खड़ा किया। काउन्टिंग के वक्त उनके एक एजेन्ट ने कहा कि यह 14 हजार से लीड कर रहे हैं, झुंझला कर कहा कि चौदह से ही? रुपया तो 29 लाख खर्च हो गया।

श्री **भगवानदास शास्त्री** : आपकी सीटों पर पैसे वाले थे या नहीं? फिर आपने तो जाटवाद का नारा लगाकर किसी को अपने एरिया में घुसने ही नहीं दिया। पुलिस और सरकार को आपने मिला लिया था।

श्री **शंकरलाल जाट** : तो सेठों के पीछे आप भी लगे हुये हैं। आपने तो अपना अस्तित्व ही पैसे वालों के पीछे बेच दिया और यहां आकर चिल्लाते हैं कांग्रेस वाले ऐसे है। इसका नतीजा देख लिया। 350 आ गये दिल्ली में। किशनगढ़ की बात चित्तौड़ तक में फैलाई गई है कि कांग्रेस वालों ने किशनगढ़ महाराज को गोली

(श्री शंकरलाल जाट)

मारी। अपने पेम्फलेट छपवाये। बाद में सब मामला सामने आ गया। हां, हम मानते हैं वे मारे गये हैं। अब पता लगा रहे हैं, जिसने मारा है वह जेल जावेगा। पर आप इसको भी राजनैतिक रंग देकर जनता को गुमराह करें यह ठीक नहीं है।

चार-चार साल तक लम्बा अकाल राजस्थान में पड़ा पर सरकार ने पूरी सतर्कता से उनको रोजी-रोटी में लगाये रक्खा एक को भी नहीं मरने दिया। इसके लिये यह सरकार वास्तव में धन्यवाद की पात्र है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते आये हैं कि सम्वत् 56 में भी इसी तरह से अकाल पड़ा था। उस जमाने में एक रुपये में दस सेर अनाज विकता था फिर भी हजारों आदमी मारे गये थे। तो आप जो अच्छा काम यह सरकार करती है, उसको तो भूल जाते हैं। पर जो थोड़ी बहुत कमी रहती है उसके लिये काफी शोरगुल करते हैं।

एडजोर्नमेन्ट मोशन की बात आई। तेल और कोयले का अभाव है। हम भी इस पर विचार करते हैं। पर जो राजस्थान में विकास हुआ है उसके लिये कुछ नहीं कहते। नहरें, सड़कें आदि बनीं उनका बहुत विकास हुआ तो इसके लिये तो धन्यवाद दें।

सीलिंग की बात आई। कहा गया कि मई 71 तक सीलिंग में जितनी भूमि आवेगी भूमिहीनों को दे दी जावेगी। अब आपको इसमें भी सन्देह है? हो सकता है। इसके लिये सरकार सावधान रहेगी। रहना चाहिये। ये बड़े-बड़े लोग लैंडलार्ड कहीं-कहीं गड़बड़ी कर सकते हैं। वे अपने रिश्तेदारों के नाम से या अन्य प्रकार से झूठे नाम लेकर दूसरों के नाम कर सकते हैं। सरकार को इसे रोकना चाहिये।

बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि देहातों में भी पूंजीपति बैठे हैं। मैं इसका विरोध नहीं करता, हो सकते हैं। फिर भी शहरों और देहातों में बहुत फर्क है। इसको मिटाना होगा। एक तरफ जब स्कूल खोलती है सरकार तो शहर वालों को कुछ नहीं कहती, वहां चुपचाप सरकार स्कूल खोलती है, पर जब गांव में खोलने का प्रश्न आता है तो श्रमदान की बात कही जाती है। इस प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

आज शहर देहातों पर अधिक निर्भर है। गांव के लोग खेतों में मेहनत करते हैं और अनाज पैदा करते हैं। इस अनाज से शहर वालों का पेट भरते हैं। पर बदले में उनके साथ पक्षपात बरतते हैं। भेदभाव बरतते हैं। यह भेदभाव अब मिटना चाहिये समाजवादी राज में।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इससे किसानों को कुछ राहत मिली है। करजा मिला है। पर यह भी मिला है उनको जो चलते पुरजे थे। गरीबों को अभी भी लाभ नहीं मिला है। गरीबों से तो इसके माध्यम से भी रिश्वतें ली जाती हैं। अब यह नहीं होना चाहिये। गरीब लोगों को भी सही तरीके से बैंकों से मदद मिलनी चाहिये।

श्री भगवान दास शास्त्री: रेल पटरी पर अब आई है।

श्री शंकरलाल जाट : रासायनिक खाद दिया गया। वह न जाने कैसा था। कुछ भी असर नहीं किया। बेकार गया। इसकी जांच की जानी चाहिये और आगे से अच्छा केमिकल खाद मिलना चाहिये। उसके अनुसार पानी भी मिलना चाहिये। गम्भीरी नदी के कमाण्ड एरिया में खेतों को पानी देने में भी भेदभाव बरता जाता है। किसी ने पांच पांच बार तक पानी लिया है, और किसी को दो बार भी मुश्किल से मिल पाया है। यह इर्रिगेशन विभाग की लापरवाही है। उस पर सही नियन्त्रण होना चाहिये। कइयों की जगह सूखी है और कइयों के पानी भरा है। जिंक स्मेल्टर रोक फास्टफेट का जो खाद मिला वह बेकार है। बिलकुल निकम्मा है। इससे लोगों का नुकसान हुआ है। इस में किसी रसायन की कमी है। उसकी पूर्ति की जाकर इसे ऐसा बनाया जावे जिससे किसानों को और फसल को फायदा मिले।

विद्युतिकरण बेशक हुआ है। पर अभी एका-एक मील दो-दो मील के ऐसे एरिये छूटे हुए हैं जहां पचासों आदमी बिजली लगाना चाहते हैं पर तरस रहे हैं। पंचायत समितियों में प्रायोरिटी का एक रजिस्टर रहे जिसमें नाम दर्ज हों और उनको उसी हिसाब से नम्बर से बिजली मिलनी चाहिये। नहीं तो दो तीन सौ रिश्वत के ये इन्जीनियर लोग खाते हैं तब कनक्शन मिलता है। गरीबों के पास इतना पैसा कहां जो रिश्वत दे।

राज्य सरकार ने 16 जिलों को पिछड़ा माना है जहां योजनाबद्ध तरीके से काम होगा। पर खेद है कि चितौड़ पिछड़ा होते हुए भी इसमें नहीं लिया गया। इसको भी लिया जाना चाहिये। चित्तौड़गढ़ जिला हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है चाहे सड़कों की दृष्टि से या दूसरी दृष्टि से, तो उसकी तरफ भी ध्यान दें।

श्री सभापति : इसलिए तो वहां सेठ साहब गए हैं चुनावों में।

श्री शंकरलाल जाट : आज भी आजादी के बाद कई गांवों में जाकर जांच की तो जिन लोगों के आम या महुए के वृक्ष खड़े हैं उसका फायदा भूतपूर्व ठिकाने उठा रहे हैं। इससे मुकदमें हुए। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अब भी जिलाधीश को इस प्रकार से कम से कम थोड़ा पाबन्द करें कि वहां जांच करके वहां की चरिया में जो वृक्ष लगे हुए हैं उनका फायदा उनको मिलना चाहिए।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

थोड़ा सा समय हुआ है।

श्री सभापति : 12-13 मिनट ले लिये हैं।

श्री शंकरलाल जाट : भूमिहीनों को भूमि देने के लिए राज्यपाल महोदय ने बताया कि गांधी शताब्दी वर्ष में 1,89,000 हैक्टर्स भूमि एलाट की है और वह आदिवासी, अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को दी गई है। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 1962 में कपासन तहसील में जिन लोगों को भूमि दी गई है उनका अब तक कब्जा नहीं दिया

(श्री शंकरलाल जाट)

गया है। क्या गांधी शताब्दी वर्ष में कब्जा देने का प्रश्न सामने नहीं आ सकता था। तहसील बड़ी सादड़ी में कम से कम 40 आदमियों के नाजायज कब्जे के केसेज चल रहे हैं। उन्होंने दो हजार, ढाई हजार जुर्माने के जमा करा दिए हैं। इसलिए कम से कम जो आदिवासी लोग हैं जाति के मीने भी हैं, कम से कम उनकी जमीन को रेग्यूलराइज करने के शीघ्रातिशीघ्र आदेश प्रदान करें।

चित्तौड़गढ़ जिले में काफी भूसंरक्षण कार्य हुआ है लेकिन जिनका कुछ भी नहीं किया उनसे भी रुपया वसूल किया जा रहा है। सरकार उन गांवों में जांच कराए कि क्या वहां भूसंरक्षण का कार्य हुआ है या नहीं ? नहीं तो क्यों रुपया वसूल हो रहा है।

चिकित्सा सुविधायें अवश्य बढ़ रही हैं लेकिन बड़ी सादड़ी में तो 50 वर्ष पहले की व्यवस्था है, उसमें थोड़ा बहुत सुधार होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस बन्द करता हूँ। जंगलात की नरिया में पहले कृषि सम्बन्धी सुविधायें थीं हल चूड़ी वगैरह की, वह बन्द कर दी गई हैं।

इस वर्ष चुनाव के समय उधर के लोग चिल्लाते हैं कि सरकारी मशीनरी तुम्हारे साथ थी। एक परिवार वाले को एक बैल-गाड़ी लकड़ी की दी वह भी पटवारी की तसदीक पर। आप हमेशा लांछन लगाते हो कि मशीनरी तुम्हारे साथ थी। कम से कम हमें तो बख्शो।

अंत में मैं राज्यपाल महोदय के अभि-भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री लाभचंद बंद (सुजानगढ़) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने हेतु अपना मत व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय ने जो प्रथम समाजवाद की तरफ बहुत बड़ा कदम बताया, मैं नहीं समझ पाया कि राज्यपाल महोदय ने सिवा भाषणों के, कौनसा कदम उठाया है। अपने और अपने चपरासियों के स्टैंडर्ड में कौनसा भेद मिटाया है। मुख्य मंत्रीजी और अन्य मंत्रीगण अपने और अपने नीचे के कर्मचारियों के बीच में कौनसा भेद मिटाया है जिसके कारण इसको एक बड़ा कदम माना जावे। यह थोथा नारा है लोगों को बहकाने वाला नारा है, लोग अशिक्षा के कारण इस बहकावे में आ जाते हैं और इसी का फायदा इस चुनाव में उठाया गया है।

दूसरी तरफ राज्यपाल महोदय कहते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो गए। यह बात भी बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। चुनाव में जितनी अशांति की जा सकती थी, सत्तारूढ़ दल ने की। सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। बड़े बड़े कर्मचारियों, अधिकारियों व मंत्रियों के प्रभाव का दुरुपयोग किया गया और सब तरह से गुण्डागर्दी और जरायमपेशा लोगों की मदद से आतंक फैलाया गया। महाराजा किशनगढ़ की राजनैतिक हत्या का उदाहरण आपके सामने है।

कृषि की उन्नति पर राज्यपाल महोदय ने फरमाया कि हमने यह किया वह किया। आपने नहरी इलाकों में कुछ किया होगा

(श्री लाभचंद बेद)

लेकिन चूरू जिले के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया, वहां की जनता कभी नहीं भूल सकती। आपने कृषि की उन्नति के लिए क्या साधन जुटाए, वहां के किसानों के प्रति कौनसा न्याय किया ? आपने उनके डूबने का साधन जरूर बनाया। एक तरफ कुओं के लिए कर्जा देते हैं और जब वह कुआ बना देते हैं तो 0-10 साल तक बिजली नहीं देते। आज भी लोग तड़पते हैं बिजली के लिए। कुओं में 150 फीट नीचे पानी है, इंजन लगाएं तो पोसाता नहीं बैलों से पोसा नहीं सकते और बिजली की मांग करते हैं तो बिजली के प्रसार की कोई योजना नहीं है और बिजली बोर्ड वाले असमर्थता प्रकट करते हैं। जब वह कर्जा लेकर कुआ बनाते हैं उनकी किस्तें चुकाना उनके सर पर आता है तो सिवा नीलामी के क्या हो सकता है ? किसान बरबाद हो जाता है और जहां कहीं आप बिजली देते हैं तो मिनीमम गारंटी लेते हैं वह भी इतनी भारी मात्रा में कि किसान नहीं दे सकता और जहां पर बड़े पैमाने पर सिंचाइयां होती हैं वहां पर वायुमंडल दूसरा रहता है लेकिन जहां पर एक खेत में सिंचाई होती है बहुत से खेत खाली पड़े रहते हैं, वहां वायुमंडल में गर्मी रहती है। ऐसी हालत में चैत्र, वैसाख और आषाढ़ इन तीन महीनों में फसल पैदा नहीं कर सकते और मिनीमम गारंटी नहीं दे पाते हैं तो किसान की कमर तोड़ने के लिए एक वह ही काफी है।

पिछले किसान आंदोलन के अन्दर आपने आश्वासन दिया था कि हम एक बोरिंग यूनिट कायम करेंगे और जगह जगह जल भण्डार खोलने की कोशिश करेंगे लेकिन आज तक न कोई यूनिट कायम की न जल भण्डार खोजने की कोशिश की, न राहत पहुंचाई।

एक तरफ आप उद्योगों को तीन पैसे और चार पैसे में बिजली देते हैं और जहां पर 80 प्रतिशत जनता खेती पर निर्भर है, उनको आप 12 पैसे या 15 पैसे में बिजली देते हैं। इससे ज्यादा और क्या किसान की कमर तोड़ सकते हैं, क्या नुकसान पहुंचा सकते थे ? यह बात कहना कि किसानों के साथ हमदर्दी रखते हैं, किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, यह एकदम चूरू जिले के लिए बिल्कुल गलत है। वहां कोई काम नहीं किया है। जो कुछ किसान अपनी मेहनत पर करता है वही है, इसके सिवा आपने कुछ नहीं किया है।

वहां प्रकृति की देन से गत वर्ष बारिश अच्छी हो गई तो लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी। एक तरफ तीन साल तक अकाल से पीड़ित होने के बाद, घर वगैरह गिरवी रखकर कुछ अनाज पैदा किया। कुछ बोहरों को देंगे कुछ घर में खायेंगे तो आपकी तरफ से जो लोन मिला हुआ है उसकी वसूली के लिए कुर्कियां पहुंच गई और सारा माल हड़प कर गए तो इससे ज्यादा और क्या प्रहार हो सकते थे ?

शिक्षा के विषय में राज्यपाल महोदय फरमा रहे हैं कि इतने स्कूल, कालेज व प्राथमिक पाठशालायें खोलीं और 65 स्थानों पर माध्यमिक शालायें खोली हैं। मैं नहीं सोचता कि नये नये स्कूल खोलते जा रहे हैं और जहां स्थिति बिगड़ी हुई है, वहां कुछ नहीं करते। रतनगढ़ की हालत ही बता सकता हूं कि 30 हजार की पोपुलेशन में एक

(श्री लाभचंद बैद)

सरकारी माध्यमिक शाला चल रही है। छात्रों के बैठने का स्थान नहीं है। दो दो शिफ्टें चल रही हैं। दरिद्र नारायण की कृपा से बच्चे सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल जाते हैं तो आपकी तस्वीर सामने आ जाती है। ये हमारी सरकार के हथकण्डे हैं। जोकि बच्चों को भोगना पड़ता है। मैंने बार बार मांग की है। शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं कि बजट में पैसा नहीं है। पैसा जाता कहां है ? बार बार टैक्स लगाते हैं। मरने पर भी टैक्स नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपके भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची में सारे टैक्सों का पैसा साफ हो जाता है। गरीब के लिये कुछ नहीं करते हैं। नाम समाजवाद का लेते हैं। यह अधिनायकवाद है भोजवाद है।

गरीबों को, हरिजनों को जमीन बांटने की बात करते हैं। राज्यपाल महोदय ने कहा है 1 लाख 20 हजार हैक्टर भूमि 79 हजार से ज्यादा लोगों को दी है ! क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने बांटी हुई जमीन पर हरिजन भाइयों का कब्जा करा दिया ? यह सब कागजात में ही हैं। नगरपालिकाओं में फ्लश की टट्टियां बनायेंगे। ऐसा वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था। मैला सिर पर ढोने की प्रथा बन्द कर देंगे। लेकिन यह बन्द नहीं होगी। वे ही सिर पर मैला ढोते हैं जो घरों से साफ कर कर लाते हैं। जब तक आप फ्लश सिस्टम नहीं करेंगे यह कहना की हरिजनों को राहत दे रहे हैं, एक धोखा है कहने को यह आप कुछ भी कह दें वास्तव में कुछ भी नहीं है। जो कुछ आपने किया है वह सब आपके सामने और हमारे सामने है।

शासन में नियम व्यवस्था और दंड नहीं हो तब तक शासन सुचारु रूप से नहीं चल सकता है। आपने नियम बनाये वे दोषपूर्ण हैं। आप इस तरह के नियम बनाते हैं कि आपका भ्रष्टाचार चलता रहे। जयपुर में ही देख लीजिये और नगरपालिकाओं में भी देख लीजिये। नगर परिषद् के दस मील के एरिया में जमीन बेचना बन्द कर रखा है। जमीनों में गलत और नाजायज कब्जे हो रहे हैं और लगान भी नहीं देते हैं और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं।

दंड-व्यवस्था का यह हाल है कि अपराधकर्ता को कोई दंड नहीं। आडिट रिपोर्ट उठा कर देख लीजिये। सब जगह यही मिलेगा। लेकिन आप पर उसका कोई असर नहीं होता है। यह कहावत प्रसिद्ध हो गई है कि कोई ऐसा बेवकूफ होगा जो इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं करता होगा। आपके कारनामों से, शासन के कारनामों से लोगों का मानस ही गिर गया है। दिन दहाड़े चोरियां होती हैं। लक्ष्मणगढ़ में मूर्तियां चुरा ले गये। चार पांच चोरियां मन्दिरों में पहले भी हुई थीं। आपकी ओर से कोई कदम नहीं उठता। गृह मंत्री जी बूढे हो गये हैं। उनमें अब काम करने की स्प्रिट नहीं है। मुख्य मंत्रीजी को चाहिये कि वे गृह मंत्रालय किसी दूसरे को सौंप दें तो अच्छा होगा और उनसे त्यागपत्र ले लें।

स्प्रिट खत्म होने के बाद कुछ नहीं बचता और बुढ़ापे में वह अवश्यम्भावी है एक कविता है :—

बुद्धि खावे मूर्खता, मनोबल खावे मान।
तेज खावे अन्धकार ने, समय खावे प्राण॥

(श्री लाभचन्द बैद)

इन सब बातों को कहते हुए मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री **सभापति** : श्री गोरधन सोनी।

श्री **गोरधन सोनी** (मेड़ता) : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। इसलिये कि राज्यपाल महोदय ने देश की और राज्य की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनका कोई जिक्र नहीं किया है। जब समाजवाद लाना चाहते हैं और गरीबों का हित करना चाहते हैं तो उसके लिये योजना होनी चाहिये और पैसा होना चाहिये, लेकिन राज्यपाल महोदय के भाषण में उसका कोई संकेत नहीं है जिससे कि हमें महसूस हो कि इससे गरीबों का हित होगा।

मुझे बड़ा हर्ष हुआ। एक तरफ कांग्रेस क्षेत्र से यह नारा दिया कि "इन्दिरा गांधी आयी है नयी रोशनी लायी है।" राज्यपाल महोदय के भाषण को पढ़ा और उस पर विचार किया। इसमें तो नयी रोशनी की कोई बात ही नहीं है। वे ही घिसी-पिटी बातें हैं। न तो जनता को सुख और सुविधा मिली है और न कुछ।

सभापति महोदय, मैं यह बात कहना चाहता था कि कांग्रेस पक्ष ने एक बात अपना ली है कांग्रेस की हमेशा सत्ता बनी रहे और उनके स्वार्थों की पूर्ति होती रहे। इतने वर्ष तक गांधीजी के नाम पर राज्य चलाते रहे। कुर्सियों को बरकरार रखा। अब वह नाम पूरा हो गया। गोडसे ने गांधी जी की हत्या की लेकिन उनके सिद्धांतों की हत्या की इन्हीं लोगों ने और उनकी आज्ञा की अवहेलना की। वह नारा जब पुराना पड़ गया तो नया नारा लगाया कि "इन्दिरा गांधी आयी है और नयी रोशनी लायी है।" दुनियां को, जनता को इन वर्षों में इन लोगों ने तबाह किया।

एक माननीय सदस्य : गांधीजी का नाम नहीं छोड़ा है।

श्री **गोरधन सोनी** : राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम समाजवाद के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे यह पढ़ कर दुःख हुआ कि समाजवाद के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। उसके लिये कोई काम नहीं, धंधा नहीं, रीति नहीं, रिवाज नहीं, किस समाजवाद की ओर बढ़ेंगे? कोई सड़क हो, पहिया हो गाड़ी का जिसके द्वारा बढ़ते जावेंगे। अमीर और गरीब की बात करते हैं। चाहिये क्या? कोई काम होना चाहिये, सस्ता अनाज और सस्ता न्याय मिलना चाहिये। यह नहीं होगा, तो समाजवाद आवेगा कैसे?

श्री **सभापति** : सदन की अनुमति से सदन का समय दस मिनिट के लिये और बढ़ा दिया जाता है।

श्री गोरधन सोनी : इस राजस्थान में कुछ बहुत ही पिछड़े हुए हिस्से हैं। जनता भी गरीब है, उस पर अधिक बोझा आर्थिक दृष्टि से नहीं डाला जाना चाहिये। यह सोचकर सरकार को अपने खर्चों में भारी कटौती करनी चाहिये। मिनिस्टरों की इस लम्बी चौड़ी फौज पर जो लाखों रुपया खर्च होता है, उसे कम किया

(श्री गोरधन सोनी)

जाना चाहिये। सरकार के अन्य कई खर्च हैं जिनको भी कम किया जाना चाहिये, सरकार की फिजूलखर्चियों को कम किया जाना चाहिये। राजकीय फिजूलखर्च घटाना अत्यावश्यक है। इतने मिनिस्टर ! इनके अलावा रोजवेज, स्टेट होटल निगम आदि में बिठाये गये मिनिस्टर अलग !

इस समाजवाद में आपको स्वयं को उदाहरण पेश करना चाहिये। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं सुखाड़िया जी से निवेदन करूंगा कि वे दो मन्त्री कम से कम और बढ़ा दें। एक भ्रष्टाचार मन्त्री जो जनता में फैले हुए भ्रष्टाचार और इन मिनिस्टरों के काले कारनामों की एक फहरिस्त बनाता रहे। दूसरा ट्रांसफर मिनिस्टर। पचास पर्सेन्ट से अधिक काम इन मिनिस्टरों के पास केवल ट्रान्सफर करना है। तो यह काम भी उनका कम होगा। जनहित के लिये अधिक समय मिल सकेगा।

समाजवाद की बात करते हैं। 23 वर्षों से इन्हीं लोगों का राज्य चला आ रहा है। इसमें भी पिछले 15 वर्षों से ये समाजवाद का नारा लगा रहे हैं। अब काम उन्होंने क्या किया ? यह सोचने का सवाल है। आज भी समाजवाद के नाम पर यह सरकार अन्धाधुन्ध फिजूलखर्चियां करती जा रही है और इसकी पूर्ति के लिये जनता पर अन्धाधुन्ध टैक्स लगाती जा रही है।

सरकार ने समाजवाद के नाम पर अपने कारखाने लगाये। लाखों, करोड़ों रुपया उनमें लगाया। पर उनसे कितना लाभ है, यह हम सब जानते हैं ? ये भ्रष्टाचार फिजूलखर्चियों के जीते जागते अड्डे हैं। कांग्रेस वाले भी जानते हैं। सरकार का ध्यान भी दिलाया जाता है, पर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। यह पांच हजार करोड़ रुपया जो इस तरह से घाटे के व्यापार में फंसा दिया गया है, उसे अगर सड़कों पर, पेयजल की जनता की समस्या के समाधान में, अस्पतालों पर, स्कूलों पर लगाया जाता तो देश की शकल बदल जाती। पर इनमें सेवाभाव नहीं है। समाजवाद की सही स्प्रिट नहीं हैं। ये तो उस पैसे के धुआं लगाना चाहते हैं, आपाधापी और लूट-खसोट में समाप्त कर देना चाहते हैं। लोग भोले हैं, उनको नारों में उलझा कर, बहका कर लालच देकर उन पर शासन करना चाहते हैं।

इसके सिवाय इनके समाजवाद के और उदाहरण भी देखिये। एक तरफ तो इनके अधिकारी हजार, दो हजार, तीन हजार रुपया महिना तक लेते हैं, दूसरी तरफ अकाल जब यहां पड़ा उस वक्त समाजवाद के नाम पर उनको मजदूरी के रूप में केवल एक रुपया, सवा रुपया, डेढ़ रुपया मजदूरी का दिया गया और वह भी समय पर नहीं दिया गया। मस्टर रोल गलत बनाये गये। काफी गड़बड़ियां उनमें की गई। क्या यही समाजवाद है ?

सभापति महोदय, यह रेल विभाग है, केन्द्रीय सरकार के अधीन है, इन्दिराजी के हाथ में है, समाजवाद का नारा बहुत जोरों से देती हैं। अगर रेलों में वे समाजवाद अपनाती तो एक ही तरह के डिब्बे यात्रा के लिये लगाने चाहिये थे। ज्यादा से ज्यादा

(श्री गोरधन सोनी)
अगर होता तो दो श्रेणियां कर देते। लेकिन आज तो ऐयाशी का ठिकाना नहीं, समाजवाद में ऐयाशी कहां से आ गई? फर्स्ट क्लास है, सैकिण्ड क्लास है, यहीं सबर नहीं, एयर-कन्डीशन्ड और आ गई, हवाई जहाज आ गये।

और सुनिये। आप गांवों में जाइये। राजस्थान में आज भी अनेक गांव ऐसे हैं जहां लोगों के पास रहने को मकान नहीं हैं। झोंपड़े नहीं हैं सरदी में ठिठरते रहते हैं और गरमी में झुलसते रहते हैं। पर दूसरी तरफ इन समाजवादियों को आज एयर-कन्डीशन्ड बंगले चाहिये। क्या इन्दिराजी के समाजवाद का यही रूप है?

मुझे दुःख होता है जब ये एयर-कन्डीशन्ड रैलों में चलने वाले और बंगलों में रहने वाले समाजवाद करते हैं, गरीबी मिटाने की बात कह कर गरीबों को धोखे में, भुलावे में रख कर अपनी कुर्सियों को बरकरार रखना चाहते हैं। बात समाजवाद की करते हैं और काम इनके पूंजीपतियों से भी गये बीते हैं। यह धोखा कब तक चलता रहेगा? जनता जब तक गुमराह होती रहेगी भोली रहेगी तब तक।

राज्यपाल महोदय ने यह भी कहा कि चुनाव शान्तिपूर्ण हो गये। मुझे दुःख होता है कि राज्यपाल जैसा जिम्मेदार आदमी इस तरह की झूंठ और शरारत से भरी बात कहता है। क्या राज्यपाल महोदय अखबार नहीं पढ़ते? झुंझुनू नगर में जिले में नागौर में जो कुछ भी कान्ड हुए उनको पता नहीं। सुमेर सिंह जी की हत्या की गई, यह मालूम नहीं। मैं नागोर का रहने वाला हूं। चुनावों का वहां जो हाल मैंने देखा उससे बड़ा दुःख हुआ। ऐसा लगता था कि वहां तो लकड़ी, लाठी, पत्थर ये चीजें थीं। लोकतन्त्र वहां जीवीत नहीं था। आपको मालूम होगा, सभापति महोदय, कि चार वर्ष पूर्व 67 के आम चुनावों में किस ढंग से मत पत्र टैम्पर किये गये। यह तो एक ऐतिहासिक केस था। इसकी सी.बी.आई. अभी तक जांच कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में इतने अत्याचार और अनाचार तक हुए कि जिसकी सीमा नहीं। लोकतन्त्र के नाम पर 67 में यहां कलंक लगा और आज भी कलंक ये लगाते रहे हैं।

लोकतन्त्र में सभी को खड़ा होने का, बोलने-चालने का, प्रचार करने का बराबर का हक है। चुनाव के दिनों में इन कांग्रेसियों ने गांवों में विरोधियों को घुसने नहीं दिया। मारपीट तक की, पत्थरबाजी की। आतंक का वातावरण बना दिया गया। नकली वोट डाले गये। एजेन्ट को अन्दर नहीं घुसने दिया गया। फिर भी समाजवाद की दुहाई दी जाये तो यह शर्मनाक ही है। आपने सुना होगा अखबारों में पढ़ा होगा मूंडवा पेट्रोल पम्प पर स्वतन्त्र पार्टी की जीप पेट्रोल ले रही थी। पीछे से दो कांग्रेस की जीपें भी आई। जब स्वतन्त्र पार्टी की जीप पेट्रोल लेकर रवाना हुई तो कांग्रेस की जीप वालों ने हाथ देकर उसे रोका और एक जीप उसके आगे लगा दी और दूसरी उसके पीछे। आगे जाकर लोगों को उसमें से उतार दिया। जीप को रोक कर, उनको नंगा किया, कपड़े छीनकर जला डाले, लोगों को बन्दूक के कुन्दों से मारा पीटा गया। यह समाजवादियों के कारनामे हैं!

छोटी पादू, मेड़ता, डेगाना पोलिंग स्टेशन है। स्वतन्त्र पार्टी के एजेन्ट को धक्का देकर

Page No 123

(श्री गोरधन सोनी)

बाहर निकाल दिया और चालीस-पचास कांग्रेस वाले वहां घुस आये, और खूब नकली मतदान चलाया गया, और फिर वहां के पोलिंग अफसर को अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गये। तो चुनावों में जिस प्रकार की धांधली और अनियमितताएं और ज्यादतियां हुईं वे अभूतपूर्व हैं। अगर यह हालत रही तो लोकतन्त्र का नाम नहीं रहेगा। इससे बड़ा दुःख होता है।

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही कल प्रातः काल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बज कर 10 मिनिट पर शुक्रवार दिनांक 19, मार्च, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सं. 28 की सूची)

भीलवाड़ा जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों की सूची जिनको राज्य सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत की गई है :–

1.	श्रीमती नारायणी देवी बेवा श्री कन्हैयालाल	75) रु. मासिक पेंशन
2.	श्री लादूराम व्यास	100) रु. मासिक पेंशन
3.	श्री रामनिवास व्यास	100) रु. मासिक पेंशन
4.	श्री काशीलाल व्यास	25) रु. मासिक पेंशन
5.	श्री साधू सीताराम	75) रु. मासिक पेंशन
6.	श्री मथुरा प्रसाद वैद्य	100) रु. मासिक पेंशन
7.	श्री कन्हैयालाल बोहरा	50) रु. मासिक पेंशन
8.	श्री हेमराज धाकड़	100) रु. मासिक पेंशन
9.	श्रीमती जयदेव बाई बेवा श्री ओंकार धाकड़	20) रु. मासिक पेंशन
10.	श्री मानिक लाल नुवाल पुत्र श्री कजोड़ी मल	75) रु. मासिक पेंशन
11.	श्री मगन लाल भाटिया पुत्र श्री बलदेव जी	75) रु. मासिक पेंशन
12.	श्री रामचन्द्र वैद्य पुत्र श्री नाथूराम जी	150) रु. मासिक पेंशन
13.	श्री फतेहसिंह पुत्र श्री उदयसिंह	50) रु. मासिक पेंशन
14.	श्री भवानी शंकर दुखित पुत्र श्री गनपतलाल	75) रु. मासिक पेंशन
15.	श्रीमती सन्तोक बाई बेवा श्री मगनलाल	75) रु. मासिक पेंशन
16.	श्री स्वामी आत्मानन्द सन्यासी	75) रु. मासिक पेंशन
17.	श्री फूलचन्द बिहानी पुत्र श्री चौथमल	75) रु. मासिक पेंशन
18.	श्री कजोड़ीमल पुत्र श्री धूलीराम काट्या	75) रु. मासिक पेंशन

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 30 की सूची)

क्र. सं.	नाम मय पिता के नाम के	जाति	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग गज में	पूर्व आवंटन की तिथि	संशोधित मानचित्र के अनुसार आवंटन की तिथि	राशि जमा कराने की तिथि	कब्जा देने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री केशी पुत्र श्री गंगाराम	बावड़ी	2	90 वर्ग गज	27–5–66	26–2–71	8–7–66	2–3–71
2.	श्री भगता पुत्र श्री स्वरूपा	,,	3	,, ,,	23–6–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
3.	श्री मेघा पुत्र श्री हुक्मा	,,	4	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
4.	श्री चौथ पुत्र श्री स्वरूपा	,,	5	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
5.	श्री दूली पुत्र श्री स्वरूपा	,,	6	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
6.	श्री लछमा पुत्र श्री स्वरूपा	,,	7	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
7.	श्री अमरसिंह पुत्र श्री स्वरूपा	,,	8	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
8.	श्री मोडा पुत्र श्री धन्ना	,,	9	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
9.	श्री चन्दा पुत्र श्री तुलदास	,,	10	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
10.	श्री भगता पुत्र श्री तेजा	,,	11	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
11.	श्री काना पुत्र श्री तेजा	,,	12	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
13.	श्री लीमा पुत्र श्री राना	,,	13	,, ,,	27–7–66	,, ,,	5–3–68	,, ,,
13.	श्री रूपा पुत्र श्री लीमा	,,	15		27–7–66	,, ,,	5–3–68	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	श्री धन्ना पुत्र श्री रामा	बागडी	16	90 वर्गगज	23–6–66	26–2–71	8–7–66	2–3–71
15.	श्री रणजीता पुत्र श्री रामा	,,	17	,, ,,	26–6–66	,, ,,	नहीं	,, ,,
16.	श्री चोथा पुत्र श्री लक्ष्मण	,,	18	,, ,,	22–7–66	,, ,,	3–8–66	,, ,,
17.	श्री पद्मा पुत्र श्री लक्ष्मण	,,	19	,, ,,	27–7–66	,, ,,	3–8–66	,, ,,
18.	श्री लखमा पुत्र श्री लक्ष्मण	,,	20	,, ,,	27–7–66	,, ,,	3–8–66	,, ,,
19.	श्री नाथू पुत्र श्री लछमा	,,	21	,, ,,	27–7–66	,, ,,	3–8–66	नहीं दिया
20.	श्री हरिलाल पुत्र श्री लक्ष्मण	,,	22	,, ,,	27–7–66	,, ,,	3–8–66	नहीं दिया
21.	श्री पूना पुत्र श्री चोथा	,,	8A	,, ,,	27–5–66	,, ,,	3–8–66	नहीं दिया
22.	श्री सोहना पुत्र श्री तेजा	,,	14	,, ,,	27–5–66	,, ,,	3–8–66	2–3–71
23.	श्री तेजपाली पुत्र श्री सोना	,,	1	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	2–3–71

परिशिष्ट 3

(अ. प्र. सं. 22 का सूची)

दिनांक : 1–1–70 से 31–12–70 तक की अवधि में खोले गये नवीन औषधालयों की सूची

क.सं. स्थान का नाम	पं. स./तहसील	जिला
1. मीमेवाल	पं. स. रायसिंह नगर	गंगानगर
2. कूपली	,, ,,	,,
3. भोपालपुरा	सूरतगढ़	गंगानगर
4. घरनोदी बडी	पं. स. राजगढ़	चूरू
5. डागियों का गुडा	पं. स. बडगांव	उदयपुर
6. दूढ़ियां	तहसील मावली	,,
7. बिदियाद	,, ,,	नागौर
8. सेकल	पं. स. जहाजपुर	भीलवाड़ा
9. कुराड	पं. स. सांगोद	कोटा
10. बमोर	,, ,,	टोंक
11. जीणी	,, ,,	झुन्झुनू
12. बिम्मन पुरा	पं. स. कोटपुतली	जयपुर
13. घट्टंडी	पं. स. मन्डावर	अलवर
14. सरखडी कलां	पं. स. थानागाजी	अलवर
15. पल्पर	पं. स. राजगढ़	अलवर
16. कालाखा	त. सिकराय	जयपुर
17. बडला	पं. स. भिनाय	अजमेर
18. देवपुरा	पं. स. सराडा	उदयपुर
19. वरदना	तह. बांरा	कोटा
20. सुड़ाकना	पं. स बैराठ	जयपुर
21. बरखेड़ा	पं. स. उमरैण	अलवर
22. टापरा	तह. पचपदरा	बाडमेर
23. मोरोली	पं. स. धोलपुर	भरतपुर
24. शेरपुर	तह. लूनकरनसर	
25. भुमफोरा	—	डूंगरपुर
26. झोबड़ा	पं. स. रोहट	पाली

परिशिष्ठ 4

(अ. प्र. सं. 26 की सूची)

राज्य की क ख ग मण्डी समितियां का विवरण

श्रेणी क

(1) जोधपुर
(2) बीकानेर
(3) कोटा
(4) श्रीगंगानगर
(5) उदयपुर
(6) अलवर
(7) जयपुर (अनाज)
(8) अजमेर
(9) सुमेरपुर
(10) हनुमानगढ़
(11) बारां

श्रेणी ख

(1) भीनमाल
(2) बाड़मेर
(3) सोजतरोड व सोजत सिटी
(4) भवानी मण्डी
(5) गंगापुर
(6) श्रीकरणपुर
(7) रायसिंहनगर
(8) भीलवाड़ा
(9) जयपुर (फल व सब्जी)
(10) भरतपुर
(11) खेरली
(12) ब्यावर
(13) रामगंजमण्डी

श्रेणी ग

(1) जैतारन
(2) रानी
(3) शिवगंज
(4) आबूरोड
(5) बिलाड़ा
(6) पीपाड़ सिटी
(7) मेड़ता सिटी
(8) कुचामन सिटी
(9) नोखा
(10) बालोतरा
(11) नागौर
(12) पाली
(13) इन्द्रगढ़
(14) अन्ता
(15) चौमहला
(16) हिण्डौन
(17) बयाना
(18) निवाई
(19) देवली
(20) टोंक
(21) केकड़ी
(22) सवाई माधोपुर
(23) बून्दी
(24) केसरीसिंहपुर
(25) गजसिंहपुर
(26) पदमपुर
(27) नोहर
(28) भादरा
(29) सांगरिया
(30) श्री विजयनगर
(31) पीलीबंगा
(32) सादूलशहर
(33) सरदारशहर
(34) सादूलपुर
(35) निम्बाहेड़ा
(36) फतेहनगर
(37) गुलाबपुरा
(38) कपासन
(39) भिन्डर
(40) नाथद्वारा
(41) प्रतापगढ़
(42) बांसवाड़ा
(43) विजयनगर
(44) डूंगरपुर
(45) सूरजगढ़
(46) महुवा—मन्डावर
(47) नदबई
(48) बांदीकुई
(49) दौसा
(50) चौमूं
(51) मालपुरा
(52) चाकसू
(53) डीग
(54) सीकर
(55) नारायणा
(56) चिड़ावा

(57) श्रीमाधोपुर	(58) नीम-का-थाना
(59) धौलपुर	(60) बाड़ी
(61) कोटपूतली	(62) कामा
(63) फतेहपुर	(64) किशनगढ़
(65) खैरथल	(66) बैंगू

परिशिष्ट ङ

(म. प्र. सं. 21 की सूची)

क्र. सं.	नाम मय पिता के नाम के	जाति	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्ग गज में	पूर्व आंवटन की तिथि	संशोधित मान-चित्र के अनुसार आवंटन तिथि	राशि जमा कराने की तिथि	कब्जा देने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री केशो पुत्र श्री गंगाराम	बागड़ी	2	90 वर्गगज	27–5–66	26–2–71	8–7–66	27–5–71
2.	श्री मगता पुत्र श्री स्वरूपा	,,	3	,, ,,	23–6–66	,, ,,	8–7–77	,, ,,
3.	श्री मेघा पुत्र श्री हुक्मा	,,	4	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–76	,, ,,
4.	श्री चौथा पुत्र श्री स्वरूपा	,,	5	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
5.	श्री दूनी पुत्र श्री स्वरूपा	,,	6	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	नहीं
6.	श्री लखमा पुत्र श्री स्वरूपा	,,	7	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
7.	श्री अमरसिंह पुत्र श्री स्वरूपा	,,	8	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
8.	श्री मीढ़ा पुत्र श्री धन्ना	,,	9	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
9.	श्री चन्दा पुत्र श्री दूलदास	,,	10	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	2–3–71
10.	श्री भगता पुत्र श्री तेजा	,,	11	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
11.	श्री काना पुत्र श्री तेजा	,,	12	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
12.	श्री लीमा पुत्र श्री रामा	,,	13	,, ,,	22–7–66	,, ,,	5–7–68	,, ,,
13.	श्री रूपा पुत्र श्री लोभी	,,	15	,, ,,	27–7–66	,, ,,	5–7–68	,, ,,
14.	श्री धन्ना पुत्र श्री रामा	,,	16	,, ,,	23–6–66	,, ,,	8–7–66	,, ,,
15.	श्री रणजीता पुत्र श्री रामा	,,	17	,, ,,	26–6–66	,, ,,	नहीं	,, ,,
16.	श्री चौथा पुत्र लक्ष्मण	,,	18	,, ,,	22–7–66	,, ,,	3–8–66	,, ,,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	श्री पदमा पुत्र श्री लक्ष्मण	बागडी	19	90 वर्गगज	27–7–66	26–2–71	3–8–66	2–3–71
18.	श्री लखमा पुत्र श्री लछमा	,,	20	,, ,,	27–7–66	,, ,,	3–8–66	,, ,,
19.	श्री नाथू पुत्र श्री लछमा	,,	21	,, ,,	27–7–66	,, ,,	3–8–66	नहीं दिया
20.	श्री हरिलाल पुत्र श्री लक्ष्मण	,,	22	,, ,,	27–7–66	,, ,,	3–8–66	नहीं दिया
21.	श्री पूना पुत्र श्री चांद	,,	81A	,, ,,	27–5–66	,, ,,	3–7–66	नहीं दिया
22.	श्री सोहना पत्र श्री तेजा	,,	14	,, ,,	27–5–66	,, ,,	3–8–66	2–3–71
23.	श्री पेडपली पुत्र लीला	,,	1	,, ,,	27–5–66	,, ,,	8–7–66	2–3–70

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 18 मार्च, 1971)

कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
—2	शीर्षक	विधान	चतुर्थ विधान
	11	धनराशि	धनराशि के
3	6	जितना	जितनी
5	अन्तिम से 3	चाहियेा ा	चाहिये
7	,, 6	कोलोनाइजन	कोलोनाइजेशन
10	1	पर	पर रखने
10	अन्तिम से 13	ने ह सिंह हता	मनोहरसिंह मेहता
10	,, 8	आती	आती हैं।
10	,, 5	——	है
10	,, 3	रहती	रहती हैं
11	5	आते	आते हैं
19	11	असनुार	अनुसार
32	अन्तिम से 9	लौ	लोग
33	शीर्ष	आर्य	आर्य
34	अन्तिम से 11	उत्त र	उत्तर
38	7	अमीनद्दीन	अमीनुद्दीन
41	शीर्षक	तारांकित	अ. स. के तारांकित
41	4	बीता	बिता
44	5	करयी	करायी
45	अन्तिम से 1	यपुर	जयपुर
51	,, 14	के द्र	केन्द्र
62	,, 6	में	हैं,
66	,, 4	हैं	हैं इस
77	8	फर्यारिग	फार्यारिग
77	12	वास्तव	प्रस्ताव
77	18	शतीशचन्द्र	सतीशचन्द्र
79	4	शतीशचन्द्र	सतीशचन्द्र
80	अन्तिम से 1	बाद	—
121	3	जुडिशिल	जुडिशियल
123-124	शीर्षक	शासकी	शासकीय
136	,,	शासकीय वक्तव्य	याचिकाओं का उपस्थापन
140	अन्तिम से 1	पट्टा	पटटा
146	,, 13	मकराना	(मकराना)
150	,, 4	मकराणा	(मकराना)
152	11	8	85
156	अन्तिम से 6	नौकरियों	नौकरियां

1	2	3	4
157	अन्तिम से 21	ओर	और
160	,, 9	इ क्शन	इलेक्शन
160	,, 8	तोर	तौर
161	,, 7	म ो	भी
165	11	बाली	वाली
169	अन्तिम से 1	शेप	क्षेप
169	13	अस	असर
172	अन्तिम से 10	80-95	80-85
174	12 व 13	वोट	वोट
182	6	पनर्वास	पुनर्वास
184	अन्तिम से 4	का	को
190	,, 5	बुदर्शा	दुर्दशा
194	5	सारे	सारी
194	अन्तिम से 8	गिरध री लाल	गिरधारी लाल
195	1	वेवीदत	देवीदत्त
198	अन्तिम से 7	व्य स	व्यास
208	,, 9	रा ा	राजा
212	,, 1	की	--
216	,, 10 व 11	हि दुस्तान म	हिन्दुस्तान में
217	,, 23 व 24	गाडिया	गाड़ियां
218	,, 15	हि दुस्तान	हिन्दुस्तान
227	,, 8	राजपाल	राज्यपाल
228	,, 7	बात	बातें
228	,, 7	आपन	आपने
231	,, 8	जिबली	बिजली
232	2	चाहिने	चाहिये
232	16	की चरिया	के एरिया
235	8	0-10	10-10
235	17	आता	आती
242	15	डलझा	उलझा
246	अन्तिम से 1	बहां	वहां
244	3	जीवीत	जीवित